ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष : 4 | अंक : 23 | दिसंबर 2022 / Issue-1 | मूल्य : ₹ 55

dhyeyaias.com

वैश्विक संकटों के बीच जी-20 की भूमिका की तलाश करता बाली उद्घोषणा

भारत में राष्ट्रीय रोबोटिक्स बॉडी की आवश्यकता

लिव इन रिलेशनशिप व्यक्तिगत स्वतंत्रता या नैतिक दुविधा

भारत में बढ़ता सड़कों का जाल : दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अच्छी निगरानी प्रणाली की आवश्यकता

विश्व की बढती जनसंख्या के मायने : समस्याएं एवं समाधान

राष्ट्र और पर्यावरण के प्रति आदिवासियों का योगदान : उनकी चुनौतियों को हल करने की आवश्यकता

तटीय पारितंत्र के संरक्षण में मैन्ग्रोव की भूमिका: चुनौतियाँ एवं समाधान

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, **प्रत्येक 15 दिन** में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन **आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा** को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर **विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न** आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही **केस स्टडी खंड** के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम **PMI (Pre + Mains + Interview)** की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन **प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख** को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback write to us at :-

perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

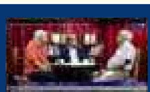

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

इस अंक में...

प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
	:	बाघेन्द्र सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन	:	डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
	:	ऋतु, प्रत्यूषा
	:	सल्तनत परवीन
	:	लोकेश शुक्ल
मुख्य समीक्षक	:	ए.के. श्रीवास्तव
आवरण सज्जा	:	अरूण मिश्र
एवं विकास	:	पुनीष जैन
टंकण	:	सचिन
	:	तरून
तकनीकी सहायक	:	मो. वसीफ खान
कार्यालय सहायक	:	राजू
	:	चंदन
	:	अरूण

समसामयिकी लेख 5-21

1. भारत में बढ़ता सड़कों का जाल: दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अच्छी निगरानी प्रणाली की आवश्यकता
2. वैश्विक संकटों के बीच जी-20 की भूमिका की तलाश करता बाली उद्घोषणा
3. भारत में राष्ट्रीय रोबोटिक्स बॉडी की आवश्यकता
4. राष्ट्र और पर्यावरण के प्रति आदिवासियों का योगदान: उनकी चुनौतियों को हल करने की आवश्यकता
5. विश्व की बढ़ती जनसंख्या के मायने: समस्याएं एवं समाधान
6. तटीय पारितंत्र के संरक्षण में मैन्ग्रोव की भूमिका: चुनौतियाँ एवं समाधान
7. लिव-इन रिलेशनशिप व्यक्तिगत स्वतंत्रता या नैतिक दुविधा

राष्ट्रीय 22-27
अंतर्राष्ट्रीय 28-33
पर्यावरण 34-39
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 40-44
आर्थिकी 45-50
विविध 51-56
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 57-60
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ... 61
ब्रेन-बूस्टर 62-68
प्रारम्भिक परीक्षा विशेष 69-75
समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 76-77
व्यक्तित्व 78

आगामी अंक में

- भारत में जेल सुधारों की आवश्यकता
- कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बढ़ते मतभेदों को दूर करना समय की मांग
- विश्व द्वारा चीन को अलग थलग करने में भारत का महत्त्व
- डिजिटल मुद्रा: भविष्य या मजबूरी
- जैव विविधता को बचाने में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयो का महत्त्व
- एमएमआर में उल्लेखनीय गिरावट: क्या भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को हासिल किया
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 अच्छी पहल: साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

राष्ट्रीय मुद्दे

भारत में बढ़ता सड़कों का जालः दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अच्छी निगरानी प्रणाली की आवश्यकता

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क और राजमार्ग मंत्रालय 2024 तक भारत में सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने के लिए काम कर रहा है। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जिसकी कुल लंबाई 6.4 मिलियन किमी. है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और शहरी और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। सड़क नेटवर्क भारत के आर्थिक सुधार में एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन अधिक सुगम होता है। भारत सरकार द्वारा इसे बढ़ावा देने हेतु भारतमाला परियोजना (66,100 किलोमीटर के आर्थिक गलियारों, सीमा और तटीय सड़कों तथा एक्सप्रेसवे का निर्माण) आदि शुरू की गई है। सड़क उपयोगकर्त्ता के लिए सड़क दुर्घटना सबसे अवांछित चीज होती है। अधिकांश सड़क उपयोगकर्त्ता सड़कों के सामान्य नियमों और सुरक्षा उपायों के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए भी अपनी ही लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।

सड़क दो गंतव्यों के बीच का एक मार्ग है जो मोटरयुक्त और गैर-मोटरचालित वाहनों के माध्यम से परिवहन को सक्षम बनाने के लिए काम में लाया जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, लाल बत्ती का उल्लंघन, सीट बेल्ट तथा हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों से बचना, लेन ड्राइविंग का पालन न करना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, ओवर स्पीडिंग, चालक के लिए व्याकुलता, रैश ड्राइविंग, नियमों का उल्लंघन, संकेतों को समझने में विफलता, थकान, अशिक्षा, फुटबोर्ड पर यात्रा करने वाले वाहन को गलत साइड से उतारना, चलती बस को पकड़ना, ब्रेक या स्टीयरिंग की विफलता, टायर फटना, अपर्याप्त हेडलाइट्स, ओवरलोडिंग, गड्ढे, क्षतिग्रस्त सड़क, अवैध स्पीड ब्रेकर, कोहरा, भारी वर्षा, तूफान आदि कारण सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। दृश्य लाइसेंस की कमी, किशोरों द्वारा अपराध से संबंधित उचित प्रावधान को न मानना, पर्याप्त टेस्ट ड्राइविंग ट्रैकों की कमी, 'रिफ्रेशर ट्रेनिंग' के लिए संस्थान उपलब्ध न होना भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। जान का जोखिम, चोट, संपत्ति की क्षति आदि सड़क दुर्घटनाओं का ही परिणाम है।

सड़क दुर्घटनाओं में भारत की स्थितिः

- सड़क दुर्घटना से संबंधित सभी मौतों में भारत का हिस्सा लगभग 10% है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कुल 1,31,714 मौतें हुईं। इनमें से 69.3% मौतों के लिए ओवर स्पीडिंग जिम्मेदार है, वहीं हेलमेट न पहनने से 30.1% मौतें हुईं जबकि 11.5% मौतों का कारण सीटबेल्ट का उपयोग न करना है।
- सड़क दुर्घटनायें विश्व स्तर पर मृत्यु का आठवां प्रमुख कारण हैं जिसमें 5-29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की अधिकता है।
- दुर्घटना मृत्यु दर (प्रति 100 हताहतों की संख्या) जो वर्ष 2001 में 26.9 थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 28.63 और वर्ष 2020 में 37.54 हो गई।

सड़क सुरक्षा हेतु किए गए उपायः

सड़क सुरक्षा- इसका उद्देश्य सड़कों पर यात्रा करते समय लोगों को सुरक्षित करना है। यह सभी सड़क उपयोगकर्ताओं जैसे पैदल चलने वालों, दोपहिया, चौपहिया, बहुपहिया और अन्य परिवहन वाहन उपयोगकर्त्ताओं को सुरक्षित बनाने के लिए है। सभी को सड़क पर वाहन चलाते समय दूसरों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

- **ब्रासीलिया घोषणा (2015):** ब्राजील में आयोजित हुए दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित ब्रासीलिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत भी इस घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्ता है जिसके तहत 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करना व 2021-2030 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्य दशक मानना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (iRAP):** यह सुरक्षित सड़कों के माध्यम से जीवन बचाने के लिए समर्पित एक पंजीकृत चैरिटी है।
- **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988:** यह अधिनियम एनएच के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण के गठन तथा उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों से संबंधित है।
- **राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2000:** यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि के नियंत्रण, रास्ते के अधिकार तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात और अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए प्रावधान प्रदान करता है।
- **सड़क मार्ग से वहन अधिनियम, 2007:** यह अधिनियम सामान्य वाहकों के विनियमन, उनकी देयता को सीमित करने और उन्हें वितरित किए गए वस्तु के मूल्य की घोषणा प्रदान करता है, ताकि ऐसे वस्तु की हानि या क्षति के लिए उनकी देयता का निर्धारण किया जा सके, जो स्वयं उनके सेवकों या एजेंटों की लापरवाही या आपराधिक कृत्यों के कारण हुआ हो।
- **मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:** यह अधिनियम यातायात उल्लंघनों, दोषपूर्ण वाहनों, किशोर ड्राइविंग आदि के

लिए दंड में वृद्धि करता है। यह एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि प्रदान करता है। यह कई प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए सड़क उपयोगकर्त्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का भी प्रावधान करता है।

- MoRTH ने वर्ष 2020 में स्वीडन में 'वैश्विक लक्ष्य 2030 की प्राप्ति के लिए सड़क सुरक्षा पर तृतीय उच्चस्तरीय वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया। इसमें 2030 तक भारत में शून्य सड़क आकस्मिक मृत्यु की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (IRAD) परियोजना का उद्देश्य मोबाइल एवं वेब ऐप के माध्यम से विभिन्न अभिलेखों से डेटा समेकन करके सड़क सुरक्षा में सुधार करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2014 में सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय ब्रॉडकास्ट के.एस. राधाकृष्णन पैनल की स्थापना की। यह गलत ड्राइविंग नियंत्रण के लिए राजमार्गों पर शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करता है। समिति ने सड़क सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा के संबंध में कई निर्देश जारी किए जैसे-

- राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करना, सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना करना, सड़क सुरक्षा कार्य रिपोर्ट की सूचना जारी करना।
- जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन करना, ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना, स्कूल पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना।

दुर्घटना निवारण के कुछ अन्य उपाय:

- सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षा और जागरूकता।
- कानून का सख्त प्रवर्तन।
- वाहन डिजाइन तथा सड़क बुनियादी ढांचा सुगम बनाना।
- तेज गति की जांच से भारत में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। 60% से अधिक सड़क दुर्घटनाएं, काफी तेज गति के कारण होती हैं। 'स्पीड लिमिट' साइनबोर्ड की स्टेट हाईवे और प्रमुख सड़कों के मानकों में कमी पाई गई है।
- स्पीड डिटेक्शन डिवाइस जैसे रडार और स्पीड डिटेक्शन कैमरा सिस्टम की स्थापना शुरू की जा सकती है। चंडीगढ़ और नई दिल्ली ने ट्रैफिक कंट्रोल में स्पीड डिटेक्शन डिवाइस जैसे डिजिटल स्टील कैमरा (चंडीगढ़), स्पीड कैमरा (नई दिल्ली) तथा रडार गन (नई दिल्ली) की सेवा पहले ही लागू कर दी है।
- राडार गन जैसे उपकरणों का प्रयोग जिससे ट्रैफिक पुलिस गुजरते वाहन की गति का अनुमान लगा सके।
- स्पीड हंप, उठे हुए प्लेटफॉर्म, राउंडअबाउट और ऑप्टिकल मार्किंग से सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने के लिए विशेष रूप से शराब, भांग या अन्य नशीली दवाओं के प्रभाव में वाहन चलाने पर भारी मोटर में वाहन जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, प्रभावी कार क्रैश मानक और उन्नत ब्रेकिंग जैसी वाहन सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य बनाना चाहिए।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा Bharat NCAP (नई कार आकलन कार्यक्रम) की शुरुआत की गई।
- सड़क सुरक्षा ऑडिट और सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में क्षमता निर्माण के लिए, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
- आपातकालीन देखभाल प्रणाली को सक्रिय करके संभावित जीवन की रक्षा की जा सकती है।

सड़क सुरक्षा हेतु वाहनों के बारे में बुनियादी जागरूकता, मौसम और सड़क की स्थिति के अनुसार रक्षात्मक ड्राइविंग, वाहन की रोशनी तथा हॉर्न का उपयोग, सीट बेल्ट पहनना, वाहन के दर्पण का अच्छी तरह से उपयोग, ओवर-स्पीडिंग से बचना, रोड लाइट को समझना, उचित दूरी बनाए रखना, सड़क पर वाहन की संख्या, संकट की स्थिति से निपटने की उचित समझ, जागरूकता संबंधी वृत्तचित्रों का प्रसारण आदि कुछ प्रभावी उपाय हो सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन इस रणनीति की सफलता के लिए सख्त कानून तथा क्रियान्वयन कार्यबल की अभी भी कमी है। साथ ही सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन के लिए सड़क के आंकड़े और उपलब्ध अवसंरचना के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखना आवश्यक है। यातायात सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करना अत्यधिक प्रभावी होगा। सड़क सुरक्षा जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, आधिकारिक वित्त प्रदान करके आवश्यक ढांचे में सुधार लाना। डेटा संग्रह प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्त्ता-योग्य बनाना, सड़क उपयोगकर्त्ताओं और आम लोगों को सड़क सुरक्षा के अधिकार तथा भावना के बारे में सचेत किया जाना चाहिए। सड़क हादसों को कम करने के लिए केवल लक्ष्य तय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित प्रयास करने की भी आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय

वैश्विक संकटों के बीच जी-20 की भूमिका की तलाश करता बाली उद्घोषणा

आज से 14 साल पहले ग्लोबल इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा था जब एशियाई वित्तीय संकट ने आर्थिक संवृद्धि की दर को बहुत धीमा कर दिया था। एक बार फिर 2020 से अब विश्व अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है और कई बड़े देश भी इकोनॉमिक रिकवरी करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। इन दोनों ही दौर के आर्थिक संकटों की एक बात जो गौर करने वाली है वो है जी-20 संगठन की भूमिका। एशियाई वित्तीय संकट के प्रभावों को देखते हुए ही 1999 में जी-20 का गठन हुआ और अब फिर से जब दुनिया आर्थिक, भू-राजनीतिक झंझावातों से घिरी है तो उसका समाधान ढूढ़ने के लिए एक बार फिर जी-20 का सम्मेलन हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की एक खास बात जिस पर ध्यान जाना चाहिए कि अब जी-20 के विकसित देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे इमर्जिंग मार्केट इकॉनमी की भूमिका और क्षमता को मान्यता देना शुरू कर दिया है। इसका प्रमाण ये भी है कि 2023 में जी-20 का आयोजन विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत करेगा तो वहीं 2024 और 2025 में इसका आयोजन क्रमशः ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका करेंगे। यह ब्रिक्स और इब्सा के बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है।

बाली उद्घोषणा से पता चलता है कि विकसित और विकासशील देश जी-20 को ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी का सबसे प्रभावी जरिया मान रहे हैं। शायद इसलिए राष्ट्रों के बीच अपने आर्थिक मतभेदों और महत्त्वाकांक्षाओं को परे रखकर, आर्थिक संरक्षणवादी नीतियों को छोड़कर वैश्विक आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने पर सहमति दिखाई दे रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य भू-राजनीतिक तनावों ने यूरोपीय देशों खासकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसलिए जी-20 के बाली समिट में राष्ट्र प्रमुखों ने कहा कि वे रूस की युद्ध की बर्बर और पाशविक मानसिकता का पुरजोर विरोध करते हैं और चाहते हैं कि रूस बिना किसी शर्त के यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य कार्यवाही को बंद करे क्योंकि युद्ध अब बहुत बड़ी मानव त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है तथा रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और लोकतांत्रिक मूल्य इस बात की इजाजत नहीं देते कि कोई देश अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं के लिए वैश्विक शांति सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की आहुति देने पर तुल जाए। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी-20 बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी सहमति व्यक्त की कि किसी भी स्थिति में परमाणु युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए।

दोनों देशों ने यह भी कहा कि परमाणु हथियार से कभी भी युद्ध नहीं जीता जा सकता है। रूस की ओर से यूक्रेन को दी जा रही परमाणु धमकियों की भी दोनों देशों ने निंदा की है। चीन का ऐसा दृष्टिकोण पश्चिमी देशों को एक अलग ही प्रकार का नैतिक साहस दे रहा है क्योंकि चीन बहुत कम ही अवसरों पर स्पष्टवादी हो पाता है।

जी-20 में भारत का यथार्थवादी रूखः

जी-20 के बाली समिट में भारतीय पीएम नरेन्द्र मोदी के दिए गए भाषण में साफ तौर पर कहा गया कि यह युग युद्ध का नहीं हो सकता। यह मोदी की मजबूत विदेश नीति और दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऐसा कहकर भारत ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के अपने साझेदारों को संदेश दिया कि भारत किसी भी प्रकार के दुविधा या असमंजस में नहीं है कि वह अपने मित्र देश रूस की अवांछनीय हरकत का समर्थन करेगा। युद्ध ने विश्व को खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा में झोंक दिया है जिससे मानवता पीड़ित है। जी-20 में रूस को लेकर भारत के स्टैंड का लोहा अमेरिका और चीन ने भी माना। मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से यूक्रेन जंग को खत्म करने का रास्ता दिखाया। मोदी ने कहा कि इस जंग को कूटनीति और संवाद के जरिए समाप्त किया जाना चाहिए।

इस बैठक में जी-20 देशों ने यूएन चार्टर के प्रति सम्मान बनाये रखने और यूएनएससी के प्रस्ताव संख्या ईएस-11/1 को याद किया जो रूस के यूक्रेन पर युद्ध की घोर भर्त्सना करता है। बाली समिट में जी-20 देशों ने यह भी माना कि यह सुरक्षा मुद्दों को हल करने का फोरम नहीं है लेकिन यह भी सत्य है कि रूस-यूक्रेन जैसे कई अन्य सुरक्षा मुद्दे ग्लोबल इकोनॉमी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं।

धारणीय विकास के लिए सहयोग जरूरीः

जी-20 के सदस्य देश नहीं चाहते कि विश्व में क्रिटिकल सप्लाई चेन धराशायी हो जाये, साथ ही जी-20 के सदस्य नहीं चाहते कि कोविड-19 की बुरी मार खाने वाले देश अब युद्ध जनित एनर्जी इन्फ्लेशन का सामना करें। जी-20 के देश चाहते हैं कि अब एक ऐसे धारणीय विकास के लिए काम किया जाए जिससे आर्थिक मंदी की सभी संभावित संभावनाओं को खत्म किया जा सके। इस बात की प्रतिध्वनि इंडोनेशिया के जी-20 की अध्यक्षता के थीम 'रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर' में सुनाई देती है। जी-20 के देशों ने सतत विकास लक्ष्यों की समय रहते प्राप्ति के लिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स से कहा है कि वे इस दिशा में वित्तीय सहयोग की मात्रा और गति दोनों को बढ़ाये ताकि फूड क्राइसिस से निपटना राष्ट्रों के लिए

आसान हो सके। जी-20 के देशों ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप ऑन फूड, एनर्जी एण्ड फाइनेंस को देखते हुए और सक्रिय भूमिका निभाने का आहवान किया है।

वन हेल्थ एप्रोच पर जोर:

जी-20 बाली समिट में जारी उद्घोषणा में इस बात का जिक्र किया गया है कि सभी देशों को कोविड-19 महामारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सर्वाधिक सुभेद्य वर्गो (वल्नरेबल कम्युनिटी) की पहचान करनी होगी जैसे-महिला, बच्चे, शरणार्थी, युवा, सीमांत कृषक, मछुआरे आदि ताकि इनके लिए सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का प्रबंध किया जा सके। दुनिया को आज 'वन हेल्थ एप्रोच' को क्रियान्वित करने के लिए काम करना चाहिए। 'वन हेल्थ' व्यक्तियों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य को संतुलित तथा अनुकूलित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। वन हेल्थ में, पशु चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र शामिल हैं। वन हेल्थ दृष्टिकोण विशेष रूप से भोजन और पानी की सुरक्षा, पोषण, जूनोटिक अर्थात पशुजन्य बीमारियों के नियंत्रण (रोग जो जानवरों तथा मनुष्यों के बीच फैल सकता है, जैसे-फ्लू, रेबीज तथा रिफ्ट वैली बुखार), प्रदूषण प्रबंधन और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (उद्भव) के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।

वैश्विक संस्थागत मूल्यों की मजबूती और जी-20:

- आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व व्यवस्था जिस एक सबसे बड़ी चुनौती का शिकार है वो हैं लगातार ग्लोबल इंस्टिट्यूशनल वैल्यूज का क्षरण। वैश्विक संस्थाओं के मूल्यों, मानकों, निर्णयों के खिलाफ जाकर काम करने की आदत कई देशों में विकसित हो गई है। इस चुनौती को हाल ही में बाली में आयोजित जी-20 समिट में महसूस किया गया है। इस बैठक में वैश्विक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वैश्विक संस्थागत मूल्यों की पुनर्बहाली पर बल दिया गया है। बाली समिट में एक नियम आधारित, भेदभावविहीन, स्वतंत्र, निष्पक्ष, मुक्त, समावेशी, समतामूलक तथा पारदर्शी मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम के विकास में विश्व व्यापार संगठन की केंद्रीय भूमिका को और मजबूत करने की बात की गई है। समावेशी संवृद्धि, नवाचार, रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए विश्व व्यापार संगठन के साथ पारस्परिक विश्वास को बढ़ा कर काम करने पर बल दिया गया है।
- सबसे महत्त्वपूर्ण ये था कि जी-20 के सदस्य देश इस बात पर सहमत थे कि वे विश्व व्यापार संगठन की संरचना, प्रकार्य, क्षेत्राधिकार, विवाद निस्तारण तंत्र से जुड़े आवश्यक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दरअसल भारत जैसे उभरते हुए विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाओं का यह कहना रहा है कि विश्व व्यापार संगठन को एक ऐसा निष्पक्ष मंच बनाया जाना चाहिए जो विकसित देशों के साथ ही विकासशील देशों, अल्पविकसित देशों, छोटे-छोटे द्वीपीय देशों के आर्थिक अधिकारों के हितों के प्रति संवेदनशील हो और निष्पक्ष निर्णय देने के लिए कार्य करें। भारत की इस अपेक्षा का जवाब जी-20 के बाली उद्घोषणा में मिला है। इसमें कहा गया है कि जी-20 के सदस्य देश सभी देशों के लिए अनुकूल व्यापार और निवेश वातावरण उपलब्ध कराएंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी देशों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड एवं फेयर कॉम्पटीशन करने का अवसर मिले। निश्चित रूप से ऐसा होने पर विभिन्न वैश्विक वित्तीय संस्थाओं का बहुपक्षीयतावाद के प्रति सम्मान बढ़ेगा और वैश्विक संस्थागत मूल्यों के क्षरण को रोकने की दिशा में काम करने के लिए राष्ट्रों को प्रेरित भी किया जा सकेगा।
- वैश्विक संस्थागत मूल्यों के संरक्षण की दिशा में काम करना अब जी-20 जैसे संगठनों के लिए एक चयन का विषय नहीं बल्कि एक अनिवार्य जरूरत बन गई है क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया में अलग-अलग प्रकार की चुनौतियां उभर रही हैं, चाहे महामारी हो, चाहे युद्ध जनित तनाव हो, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की मार हो, साइबर अपराध तथा साइबर आतंकवाद के बढ़ते हुए मामले हों उनसे कोई विकसित देश भी अछूता नहीं है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे जी-20 के देश इसलिए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर सबसे अधिक बल देते हैं। जी-20 के बाली समिट में भी कहा गया है कि विश्व समुदाय में कानून के शासन, मानवाधिकार संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की सोच से जुड़े बिना राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर पाना और उसे लंबे समय तक बनाये रख पाना एक कठिन कार्य है।
- यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन दि लॉ ऑफ दि सीज के प्रावधानों के अनुपालन और वैश्विक पर्यावरणीय संस्थाओं के बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बाली समिट में जी-20 सदस्य देशों ने बल दिया। इन देशों ने वैश्विक पर्यावरणीय संस्थागत मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 69/ 292 का आवाहन किया जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण तथा धारणीय प्रयोग से संबंधित है तथा जिसे यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन दि लॉ ऑफ दि सीज के तहत आकार दिया गया। जी-20 देशों का कहना है कि अब देशों को मिलकर वनों, समुद्री घासों, कोरल रीफों, वेटलैंड्स, पीटलैंड्स, मैंग्रोव के संरक्षण के लिए अधिक सक्रिय होकर काम करना होगा और साथ ही क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन तथा एडाप्टेशन प्रयासों को भी संस्थागत स्तर पर मजबूती देनी होगी।
- बाली समिट में जी-20 सदस्य देशों ने ग्लोबल इकोनामिक रिकवरी के लिए भी वैश्विक संस्थागत मूल्यों की मजबूती पर

बल दिया है। इसमें ओईसीडी और आईएमएफ की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा जी-20 समिट में वैश्विक आर्थिक संस्थागत मूल्यों की मजबूती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका को प्रभावी बनाने की बात कही गई है। सस्टेनेबल कैपिटल फ्लो और स्थानीय मुद्रा पूंजी बाजारों को बढ़ावा देने के लिए बाली समिट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूंजी प्रवाह के उदारीकरण तथा प्रबंधन पर संशोधित संस्थागत दृष्टिकोण का स्वागत किया गया है। यहां मैक्रो फाइनेंसियल स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क्स पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की रिपोर्ट का भी स्वागत किया गया। सीमा पार भुगतान तंत्र को बेहतर प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं की कुशल भूमिका की पहचान भी जी-20 सदस्य देशों ने की हैं। महत्त्वपूर्ण बात ये भी है कि बाली समिट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नेंस में सुधार प्रक्रिया को तेज करने पर बल दिया गया है और जनरल रिव्यू ऑफ कोटा के तहत 15 दिसंबर, 2023 तक एक नया कोटा फॉर्मूला बनाने की बात भी हुई है। भारत जैसे विकासशील देश यह चाहते हैं कि आईएमएफ का कोटा सिस्टम ऐसा हो जिससे विकासशील देशों को भी कोटा का आवंटन गैर-भेदभावकारी तरीके से किया जाए। गौरतलब है की कोटा प्रणाली आईएमएफ के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने वाली प्रणाली है। जब भी कोई देश आईएमएफ में शामिल होता है तो उसे एक कोटा प्रदान किया जाता है और यह कोटा उस देश के संबंध में तीन बातों को निर्धारित करता है। पहला, उस देश का आईएमएफ में वोटिंग राइट कितना होगा? दूसरा, उस देश की आईएमएफ में वित्तीय पहुंच कहां तक होगी? तीसरा, उस देश का आईएमएफ के बैनर तले किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण निर्णयों में क्या स्थान होगा? इससे यह भी तय होता है कि आईएमएफ किसी सदस्य देश को अधिकतम कितना वित्तीय सहयोग देगा, कोटा सिस्टम किसी सदस्य देश के आईएमएफ में अधिकतम वित्तीय योगदान को भी निर्धारित करता है। इस तरह यह एक महत्त्वपूर्ण प्रणाली है जिससे विकासशील राष्ट्रों के हित जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत जैसे देश आईएमएफ के साथ-साथ वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूटीओ आदि की संरचना तथा प्रकार्य में सुधार करने की लगातार वकालत करते हैं। इसी से वैश्विक संस्थागत मूल्य सुनिश्चित हो सकते हैं। अब जी-20 को भी देर सबेर ये बात समझ में आ ही गई है जो विश्व व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।

14 वर्षों से क्यों जरूरी रहा है जी-20:

- जी-20, विश्व के सर्वाधिक औद्योगिकृत देशों का संगठन है जिसका गठन वर्ष 1999 में जी-7 सदस्य देशों के वित्तमन्त्रियों के सुझाव पर हुआ था जिसे विकासशील देशों की उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकसित देशों के मध्य आर्थिक संवाद के एक फोरम के रूप में गठित किया गया था। यह एक अनौपचारिक व्यापारिक समूह है जिसका न तो स्थाई मुख्यालय है, न ही सचिवालय और न ही स्थाई स्टाफ। 1997 में आए एशियाई वित्तीय संकट से व्यापार, वाणिज्य, निवेश बुरी तरह से प्रभावित हुये थे जिसका प्रभाव विकसित देशों के व्यापार पर भी पड़ा। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश जिन्हें टाइगर इकोनॉमी कहा जाता था, वो भी एशियाई वित्तीय संकट से प्रभावित हुईं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, क्षेत्रीय व्यापार में असंतुलन और अन्य आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित देशों ने इस फोरम को एक महत्त्वपूर्ण संगठन के रूप में विकसित किया।
- जी-20 वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियों जैसे- आर्थिक मंदी, वैश्विक निर्धनता और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, खाद्य असुरक्षा, काला धन, मनी लांड्रिंग, आर्थिक अपराध आदि से निपटने के लिए रणनीतियां बनाता है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जी-20 बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करता है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय कर प्रशासन हेतु अपेक्षित सुधारों के लिए राष्ट्रों से समय-समय पर अपील की है। वैश्विक स्तर पर कंपनियों द्वारा कर की चोरी को रोकने और गंभीर आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए भी जी-20 ने एजेंडा निर्धारित किया है। इसके साथ ही जी-20 संयुक्त राष्ट्र सुधार, विश्व व्यापार संगठन में सुधार, ब्लू इकोनॉमी के विकास की बात करता है।
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में जी-20 देशों की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत है जबकि वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत है। विश्व की दो तिहाई जनसंख्या जी-20 सदस्य देशों में निवास करती है। जी-20 समिट में यूरोपीय यूनियन एक स्थाई सदस्य है। इसकी बैठक में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ईयू के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
- वैश्विक वित्तीय चुनौतियां, मुद्रास्फीति, पेट्रोलियम तेल की कीमतों का बढ़ना, डॉलर की तुलना में रुपये का अवमूल्यन, ब्रिटेन सहित यूरोपीय देश में गंभीर आर्थिक संकट, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के चलते शरणार्थियों का विस्थापित होना, रोहिंग्या शरणार्थी संकट, कई राष्ट्रों का भुगतान संतुलन संकट बढ़ना, वैश्विक बेरोजगारी तथा निर्धनता, खाद्यान्न असुरक्षा, कुपोषण, मानव एवं वन्य जीवों की तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग ये सब स्थितियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में दुनिया के 20 शीर्षस्थ औद्योगिक राष्ट्रों पर यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करें।

प्रौद्योगिकी

भारत में राष्ट्रीय रोबोटिक्स बॉडी की आवश्यकता

संदर्भः

डिफैक्टो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के सीईओ अजय गोपालस्वामी ने 25वें बेंगलुरु टेक समिट के दौरान नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही मानकों और सुरक्षा नियमों को निर्धारित करने के लिए नैसकॉम के मॉडल पर, नेशनल रोबोटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना का आग्रह किया है।

भारत के महत्त्वपूर्ण निजी और सार्वजनिक रोबोटों में शामिल हैं:

- मकड़ी के आकार का रोबोट जिसे 'बैंडिकूट' (Bandicoot) कहा जाता है केरल सरकार द्वारा तिरुवनंतपुरम की फर्म जेनरोबोटिक्स के साथ मिलकर नगरपालिका के मैनहोल (Manhole) और सीवर को साफ करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- इसकी उच्च गति और सटीकता के कारण, बैंगलोर स्थित एसएमई सुपर्णा प्लास्टिक्स लिमिटेड, जो प्लास्टिक बॉल वाल्व बनाती है, एससीएआरए (सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म) रोबोट का उपयोग अपनी असेंबली प्रक्रियाओं में करती है।
- इसके अतिरिक्त, रोबोट का उपयोग स्वास्थ्य सेवा उद्योग में उन प्रक्रियाओं के लिए किया जा रहा है जिनके लिए अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण के लिए , दिसंबर 2018 में, अहमदाबाद में एपेक्स अस्पताल ने अमेरिकी कंपनी कोरिंडस वैस्कुलर रोबोटिक्स द्वारा विकसित कॉर्पाथ तकनीक का उपयोग रोबोट को दूर से नियंत्रित करने और गांधीनगर में 32 किलोमीटर दूर एक मरीज की टेलीरोबोटिक हार्ट सर्जरी करने के लिए किया।
- मानव (Manav), भारत में पहला 3डी-मुद्रित ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो मुख्य रूप से अनुसंधान के लिए, अनुसंधान संस्थानों को प्रदान किया जाता है जो रोबोटिक्स को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पेश करते हैं। मानव में अंतर्निर्मित दृष्टि और ध्वनि प्रसंस्करण क्षमता है।
- देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मित्रा लोगों के साथ समझदारी से संवाद कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सलाहकार इवांका ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट (जीईएस) सम्मेलन के दौरान इसे पेश किया। बेंगलुरु के केनरा बैंक और पीवीआर थिएटर में लोगों से बात करते इसको देखा जा सकता है।
- रोबोकॉप एक पुलिस रोबोट है जिसे हैदराबाद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात का प्रबंधन करने में मदद के लिए तैनात किया गया है। यदि स्वायत्त रूप से तैनात किया गया है तो यह सुरक्षा का ख्याल रख सकता है जिसका उद्देश्य कार्यालयों, शॉपिंग सेंटरों, हवाई अड्डों, सिग्नल पोस्टों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा करना है। इससे बम भी डिफ्यूज किए जा सकते हैं।
- केम्पेगौडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जरूरतों के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक अद्वितीय रोबोट सहायक केम्पा (Sahayak Campa), जो अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में यात्रियों के सवालों का जवाब देगा।
- आरएडीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक विशिष्ट रोबोट है, जिसे नियमित गतिविधियों को स्वचालित करने और ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए विस्तारा (टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच साझेदारी) द्वारा बनाया गया था।

रोबोट की दौड़ में भारत की स्थिति:

रोबोटिक्स ने अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला खोली है, जिसके साथ दुनिया अपनी चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर रही है। इस क्षेत्र में भारत के लिए संभावनाएं निम्न हैं:

- **कृषि क्षेत्र में:** कुशल सिंचाई, सटीक खेती और जल उपयोग में सहायता करने वाले रोबोट।
- रैट होल खनन को रोकने के लिए तेल की खोज और खनिज पूर्वेक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका।
- नैनोबॉट्स का उपयोग कर तेल रिसाव की सफाई करना।
- चिकित्सा सेवाओं में सुधार, विशेष रूप से कोविड जैसी महामारियों के दौरान।
- उद्योग 4.0 रोबोट का उपयोग कर आपूर्ति श्रृंखलाओं विशेष रूप से अर्धचालक उद्योग का स्वचालन करने में सक्षम।
- परमाणु कचरे की सफाई और रिसाव को नियंत्रित करना, आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू आपरेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका।
- आतंकवाद और घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा स्वचालन।

भारत में रोबोटिक्स संस्थान और उनके प्रयास:

द सीएआईआरः सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स:

- **चतुर रोबोट:** विजन सेंसर (डीआरडीओ+सीएआईआर) का उपयोग कर वस्तु का चयन करता है।) सेना के लिए विभिन्न आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) अनुप्रयोगों के लिए शीर्ष अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी) की सुविधा सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (सीएआईआर) है।
- चंद्रमा की सतह (इसरो) को नेविगेट करने के लिए स्मार्टएनएवी

नामक रोबोट का उपयोग किया जायेगा।

एम्स नई दिल्ली में:

- इसने थाइमस ग्रंथि को हटाते हुए 'मायस्थेनिया ग्रैन्स' वाले एक रोगी की रोबोटिक सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

IIT कानपुर का रोबोटिक्स और मेक्ट्रोनिक्स केंद्र:

- **ई-यंत्र:** ई-यंत्र इंजीनियरिंग शिक्षा में रोबोटिक्स को एकीकृत करने की एक परियोजना है, जिसका लक्ष्य गणित, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना है जो छात्रों और शिक्षकों को जोड़ेगा।
- यह IIT बॉम्बे की एक परियोजना है जो इंजीनियरों के अगले समूह को एप्लिकेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम विकसित करना चाहती है ताकि वे वास्तविक दुनिया में आने वाली कुछ समस्याओं के लिए उपयोगी समाधान पेश करने में योगदान कर सकें।

भारत का रोबोटिक्स विकास:

- औद्योगिक रोबोट भारत में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं और कई अमेरिकी, कोरियाई तथा यहां तक कि जापानी भी उन्हें रोजगार दे रहे हैं।
- भारत में रोबोट का उपयोग हाल ही में शिक्षा, पुनर्वास, मनोरंजन, घरेलू उपयोग सहित उभरते क्षेत्रों को शामिल करने के लिए देश के पारंपरिक औद्योगिक और परमाणु ऊर्जा उपयोग से काफी आगे बढ़ा है।
- इसी तरह परमाणु ऊर्जा, उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय रोबोटिक्स शोधकर्ताओं की संख्या एक छोटी संख्या से बढ़कर 100 से अधिक हो गई है।

रोबोटिक्स के लिए आवेदन

- **सेना:** मानव रहित हवाई नेटवर्क की तरह टेली रोबोट का उपयोग सेना में दूरस्थ या दुर्गम स्थानों में खतरनाक कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है।
- इन्हें दुनिया भर में कहीं से भी संचालित किया जा सकता है, जिससे सेना अपने उपयोगकर्त्ताओं को जोखिम में डाले बिना इलाके को स्कैन करने और यहां तक कि लक्ष्य पर आक्रमण करने में सक्षम हो जाती है।
- यह तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों या सड़क के किनारे विस्फोटकों को निष्क्रिय करने में सेना की सहायता करता है।

- **चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य:** रोबोटिक सर्जरी के महत्त्वपूर्ण लाभों में शामिल हैं:
  - कम रक्त स्राव।
  - कम चीर फाड़।
  - कम दर्द।
  - अस्पताल में बिताया जाने वाला समय कम हो जाता है।
  - सर्जरी के बाद समस्याओं की संभावना कम हो जाती है।
  - तेजी से उपचार।
  - जापान का उदाहरण बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को उनकी दैनिक दिनचर्या में सहायता करने के लिए फ्रेंड नाम का एक अर्ध-स्वायत्त रोबोट बनाया जाना।
- **पर्यावरण:** पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, विशेष रूप से तेल रिसाव और विघटित प्रदूषकों को नैनोरोबोट्स द्वारा साफ किया जा सकता है।
  - रेडियोधर्मी कचरे को संभालने और निपटाने के लिए परमाणु ऊर्जा सुविधाओं में रोबोटों को नियोजित किया जा सकता है, जिससे वहां के श्रमिकों को संभावित हानिकारक विकिरण जोखिम से बचाया जा सके।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण:** अब तक लॉन्च किए गए लगभग हर मानवरहित अंतरिक्ष यान में रोबोट का उपयोग किया गया है:
  - क्योंकि वे निरंतर मानव पर्यवेक्षण के बिना एक असंरचित वातावरण में आवश्यक कार्य कर सकते हैं। स्वायत्त रोबोटों का उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण में किया जाता है।
  - दूर से संचालित वाहन (आरओवी) एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है जो एक रोबोट के रूप में कार्य कर सकता है। यह उस इलाके में घूम सकता है जिसमें इसे उतारा गया है या एक लैंडर के रूप में जो एक अन्य वस्तुओं के साथ संपर्क बनाता है और एक स्थिर स्थिति से संचालित होता है।
- **आपदा प्रबंधन:** सफलता के साथ कई स्नेक रोबोट बनाए गए हैं।
  - ये रोबोट वास्तविक सांपों की तरह चलते हुए बहुत छोटे क्षेत्रों में जा सकते हैं, जिससे वे ढह गई संरचनाओं में फंसे व्यक्तियों के रेस्क्यू ऑपरेशन में संभावित रूप से उपयोगी हो जाते हैं।
  - जापानी ACM-R5 स्नेक रोबोट जल और थल दोनों जगह यात्रा कर सकता है।

भारत में रोबोटिक्स: चुनौतियां:

- हार्डवेयर घटकों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के आयात की उच्च लागत के कारण, रोबोटिक प्रौद्योगिकी को अपनाना अत्यधिक महंगा है।
- चूंकि रोबोटिक्स एक बहुआयामी विषय है, इसलिए शीर्ष प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।

- रोबोटिक्स की कई विषयों के साथ संबद्धता के कारण, भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में भाग लेने वाले छात्रों के पास इस उद्योग में काम करने के लिए आवश्यक चार से पांच इंजीनियरिंग विषयों में विशेषज्ञता की कमी है।
- इसके अतिरिक्त, अधिकांश छात्र ऐसा काम करते हैं जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है तथा नवीन अनुसंधान को लेकर उत्साह की कमी है।
- रोबोटिक्स को अपनाना पूंजी गहन है, और जब मानव श्रम की सस्ती लागत की तुलना की जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से बाद के पक्ष में पैमाना बताता है।
- विषय पढ़ाने के लिए योग्य प्रशिक्षकों की कमी है, इंजीनियरिंग के छात्रों को भारत में कुछ क्षेत्रों के बाहर अच्छी तरह से रोबोटिक्स नहीं पढ़ाया जाता है।

निष्कर्ष:

रोबोट जल्द ही इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बनने को तत्पर हैं, जबकि कई लोग अक्सर इन्हें बड़ी समस्याओं के समकालीन समाधान के रूप में संदर्भित करते हैं। साहित्यिक विशेषज्ञों और सिद्धांतकारों ने भविष्यवाणी की है कि रोबोट 'मानव के खिलाफ होकर' और हमारी जरूरतों को पूरा करने के बजाय हम पर हमला करके मानवता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दरअसल, रोबोटिक्स के विकास के अच्छे और हानिकारक दोनों पहलू हैं। इसलिए, मनुष्य के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आविष्कारों की सुरक्षित सीमाओं को समझें तथा सटीक और जिम्मेदार तरीके से रोबोटिक सेवाओं का उपयोग करें। किसी भी मामले में, इन स्वचालित मशीनों ने दुनिया को बहुत लाभान्वित किया है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम के एक सेट द्वारा नियंत्रित होती हैं तथा अपने परिवेश के साथ सम्पर्क में रहकर कार्य करती हैं।

कला एवं संस्कृति

राष्ट्र और पर्यावरण के प्रति आदिवासियों का योगदान: उनकी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता

संदर्भ:

हाल ही में पहाड़ी जनजातीय समुदाय को जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है।

परिचय:

जनजातीय मानव समाज के ऐसे अंग हैं जो प्राय: मानव संस्कृति की आदिम अवस्था में रहते हैं। इनकी एक निश्चित भू-भाग, विशेष प्रकार की भाषा, आदिम धर्म तथा परंपरा है। डॉ. डी. एन. मजूमदार के शब्दों में एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है जिनका एक सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह व्यवसाय या उद्योगों के संदर्भ में निश्चित निषिद्धों का पालन करते हैं।

जनजातियों का राष्ट्र के प्रति योगदान:

स्वतंत्रता आंदोलन में:

- 1757 ई. से 1947 ई. तक के औपनिवेशिक शासन के दौरान जनजातियों ने ब्रिटिश शासन का व्यापक विरोध किया जिनका पहला विद्रोह 1768 ई. का चुआर विद्रोह माना जाता है।
- उसके उपरांत आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड इत्यादि कई स्थानों पर इनके विद्रोह हुए। मिजो विद्रोह (1810), कोल विद्रोह (1795 तथा 1831), मुंडा विद्रोह (1900), गारो तथा खासी विद्रोह (1829), संथाल विद्रोह, गोंड विद्रोह, नागा विद्रोह इत्यादि प्रमुख विद्रोह रहे हैं।
- स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रानी गिडालू या रानी गाडिन्ल्यू ने जनजातीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन में परिणत करके, राष्ट्रीय एकता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

कला एवं संस्कृति में योगदान:

- जनजातियों ने भारत की कला एवं संस्कृति को समृद्ध करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके प्रमुख नृत्य में भूरिया नृत्य, बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला परधोनी तथा ददरिया नृत्य, सहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला हुल्की नृत्य प्रमुख है। इसके साथ ही थोपटी नृत्य, धाड नृत्य, बराली नृत्य, नागा जनजाति द्वारा किया जाने वाला रांगन्मा नृत्य इत्यादि भी प्रमुख नृत्य हैं।
- इसके साथ ही चित्र-विचित्र मेला (गुजरात), शामलाजी मेला इत्यादि प्रमुख मेले जनजातियों से संबंधित हैं।
- त्यौहारों के मामले में सेकेरेन्यि त्यौहार (नागा जनजाति), लूई नगई नी त्यौहार (नागा जनजाति), ड्री त्यौहार (आपतानी जनजाति), लोसार (मोनापा जनजाति) इत्यादि प्रमुख त्यौहार हैं जो भारत की विरासत को समृद्ध करते हैं।
- भारत में चित्रकला का आरंभ भीमबेटका की गुफाओं से माना जाता है जो कि जनजातियों द्वारा निर्मित किए गए हैं।

इस प्रकार जनजातियों ने राष्ट्र के निर्माण तथा कला एवं संस्कृति की समृद्ध विरासत प्रदान करने के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

जनजातियों का पर्यावरण में योगदान:

सदियों से आदिवासियों का वनों से घनिष्ठ सम्बंध रहा है। हमारी संस्कृति मूलत: अरण्य संस्कृति रही है। वन एवं वन्य जीवों को वहाँ के स्थानीय वनवासियों द्वारा अपने परिवार का अंग माना गया। वनवासी समाज द्वारा वनों में स्वंत्रतापूर्वक रहकर वहीं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये सदैव वनों को संरक्षित करने का कार्य किया है। वनों से जनजातियों का लगाव हम इसी से तय कर सकते हैं कि मुख्य रूप से जनजातीय विद्रोह उसी समय आरंभ हुआ जब औपनिवेशिक शासन ने जंगलों पर अधिकार करना आरंभ किया। हम यह कह सकते हैं कि जनजातीय समुदाय पर्यावरण के नैसर्गिक संरक्षक है जिसका वर्णन हमें निम्नवत दिखता है:

- बिश्नोई आंदोलन 1731 मारवाड़ के खेजड़ी गांव में, चिपको आंदोलन 1974 उत्तराखंड में, बिहार का जंगल बचाओ आंदोलन 1980, बलिया पाल आंदोलन इत्यादि प्रमुख आंदोलन है जिनमें जनजातियों ने सक्रिय रूप से वनों की रक्षा के लिए तत्कालिक राज्यों अथवा राज्य सरकारों के विरुद्ध प्रखर रूप से आंदोलन किया।
- जनजातीय समुदायों द्वारा पेड़ों, वृक्षों, नदियों, जंगलों इत्यादि को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। वे वनों से भावनात्मक लगाव रखते हैं।
- इसके साथ ही औषधियों तथा वनोपज के औद्योगिक प्रयोग की पारंपरिक ज्ञान पद्धति भी, वन संरक्षण में जनजातियों को एक महत्त्वपूर्ण प्रदान करती है।
- जनजातीय क्षेत्र के लोग सामुदायिक संरक्षण तथा पवित्र उपवन को संरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- पर्यावरण के प्रति जनजातियों के इसी लगाव को देखते हुए सरकार द्वारा 2006 में वन अधिकार अधिनियम का निर्माण किया गया जिसमें जनजातियों की उनके जंगल पर अधिकारों की पुष्टि की गई।

जनजातीय समुदायों की प्रमुख समस्याएं:

- **विश्वास संकट:** जनजातीय समुदाय की सबसे प्रमुख समस्या

मुख्य भूमि के लोगों के साथ विश्वास कम होना है। 1894 तथा 1952 के वन अधिनियमों में ये उपबंध किए गए की जनजातियों को वनों से दूर किया जाए। इसके साथ ही औपनिवेशिक ताकतों से विद्रोह करने के कारण जनजातियों में से कई जनजातियों को आदतन अपराधी घोषित कर दिया गया। इन परिस्थितियों ने मुख्य भूमि तथा जनजातीय लोगों के मध्य विश्वास संकट को जन्म दिया।

- **आर्थिक संकट तथा भूमि अतिक्रमण:** जनजातीय समुदाय की दूसरी सबसे बड़ी समस्या आर्थिक संकट है। एक तरफ वे झूम कृषि करते हैं जिसके कारण कृषि में स्थाई आय की सुविधा समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही जनजातीय समुदायों की भूमि पर विकासात्मक परियोजनाओं द्वारा किए गए निर्माण कार्यों से उनकी भूमि भी छीन ली जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के पूर्व ही लगभग 43,00,000 हेक्टेयर जनजातीय भूमि को कानूनी अथवा गैर-कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है।
- **स्वास्थ्य की समस्या:** स्वास्थ्य की समस्या तीसरी सबसे बड़ी समस्या है। जनजातियां महामारी तथा संक्रामक रोगों के प्रति बहुत ही अधिक सुभेद्य होती हैं। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच कम होती है। इन कारणों से जनजातीय समुदाय में जीवन प्रत्याशा भी बहुत ही कम रहती है।
- **प्रकृति से लगाव में व्यवधान:** कई बार जब संरक्षण के नाम पर विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने पर यूनेस्को उस क्षेत्र का संरक्षण विभाग ग्रहण कर लेता है, तब जनजातीय समुदाय इस संरक्षण को अपने विरुद्ध अतिक्रमण मानते हैं। यह भी बाहरी लोगों तथा जनजातीय लोगों के मध्य विवाद का कारण बनता है।
- **वन अधिकार अधिनियम से संबद्ध चिंताएं:** यद्यपि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के द्वारा वनों पर जनजातियों के अधिकार की पुष्टि की गई थी परंतु वन अधिकार अधिनियम के शिथिल क्रियान्वयन में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आयी है। कई संरक्षण वादी संगठनों द्वारा वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद-246 के अनुसार भूमि राज्य सूची का विषय है। अतः केंद्र सरकार अथवा संसद इस पर कोई भी कानून नहीं बना सकती। कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्य सरकारें अपने-अपने भूमि नियमों के अनुसार वनों को संरक्षित कर सकती हैं। हालांकि यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है।

इसके साथ ही जनजातीय समुदाय कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं जैसे-बलात धर्मांतरण, पार्थक्य बाल विवाह, अशिक्षा जैसे समस्याओं से ग्रस्त हैं जिसका निस्तारण करना आवश्यक है।

जनजातीय समुदाय की समस्याओं के निस्तारण के लिए लिए गए प्रयास:

संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान का अनुच्छेद-15 तथा 16 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।
- संविधान का अनुछेद-17 अस्पृश्यता के समापन की घोषणा करता है।
- संविधान का अनुच्छेद-21 सभी के लिए गरिमामय जीवन का उपबंध करता है जिसमें जनजातीय जीवन भी सम्मिलित है।
- संविधान का अनुच्छेद-23 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है जिसमें मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।
- संविधान का अनुच्छेद-342 अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है।
- संविधान में अनुसूची-5 तथा अनुसूची-6 में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं।
- संविधान का अनुच्छेद-371 कई राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है जिनमें अधिकतर जनजातियां निवास करती हैं।

विधिक प्रावधान:

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989:

- यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के विरुद्ध होने वाले अपराधों को गैर-जमानती तथा दंडनीय घोषित करता है।
- यह अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विरुद्ध होने वाले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अपराध से उन्हें संरक्षण प्रदान करता है।

पेसा अधिनियम 1996:

- 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भूरिया समिति की अनुशंसाओं पर आधारित था।
- यह जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन हेतु प्रतिबद्धता स्थापित करता है।
- हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने इन नियमों को अधिसूचित किया है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006:

- वन अधिकार अधिनियम 2006 जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है। इसमें संरक्षित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण आवासीय स्थान इंगित करने का प्रावधान है।
- हालांकि इसका शिथिल क्रियान्वयन एक चिंता का विषय है।

कार्यकारी आदेश:

- राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में अपने आदेश द्वारा विधान निर्माण कर सकते हैं।
- जनजातीय प्रशासन हेतु क्षेत्रीय तथा स्वायत्त जिला परिषदें बनाई गई हैं।
- जनजातीय लोगों को सामाजिक न्याय तक पहुंच स्थापित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कार्यरत है।

अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग:

- अनुच्छेद-338 (ए) में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है।
- 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2004 से प्रवर्तित है।
- इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा अन्य सदस्य होते हैं।
- 3 पूर्णकालिक सदस्यों में से एक का महिला होना अनिवार्य है।
- यह अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े सभी मुद्दों का परीक्षण तथा निर्देशन करता है।

अन्य तथ्य:

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.6 प्रतिशत (लगभग 104 मिलियन) आदिवासी आबादी है। इन समुदायों की आवश्यक विशेषताएं हैं:-

1. आदिम लक्षण।
2. भौगोलिक अलगाव।
3. अलग संस्कृति।
4. पार्थक्य।

- भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें से लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGS) हैं। उनमें भील सबसे बड़ा आदिवासी समूह है।
- ओडिशा में सबसे अधिक जनजातीय समुदाय (62) पाए जाते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है जो कि राज्य की कुल आबादी का 21.1% है।

जनजातीय समुदाय के सुधार हेतु निर्मित समितियां:

सरकार द्वारा समय-समय पर जनजातीय समुदाय के विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया है:

- अनुच्छेद-340 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पहला पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग, 1953) ने भी अनुसूचित जनजातियों के बारे में अपनी अनुशंसा दी थी।
- एलविन कमेटी (1959) का गठन जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिये बुनियादी प्रशासनिक इकाई के कार्यकरण से सम्बंधित था।
- लोकुर समिति (1965) का गठन अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंड स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था।
- भूरिया समिति (1991) पेसा अधिनियम से सम्बंधित।
- मुंजेकर समिति (2005) ने जनजातीय शासन तथा प्रशासन का परीक्षण किया।
- प्रो. वर्जिनियस शाशा (2013) जनजातियों के समग्र विकास से सम्बंधित है।

आगे की राह:

उपरोक्त प्रयासों के बाद भी अनुसूचित जनजातियों की स्थिति अभी भी सुभेद्य से बनी हुई है। यह आवश्यक है कि सरकार, नागरिक समाज तथा पर्यावरण संरक्षणविद मिलकर इस संदर्भ में एक ठोस कदम उठाए हैं। इसमें वन अधिकार अधिनियम का बेहतर क्रियान्वयन, एकलव्य स्कूलों के माध्यम से जनजातीय शिक्षा का प्रसार, जैव संसाधनों से प्राप्त जानकारी तथा लाभ को जनजातीय समुदायों के साथ वितरित करने के कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। इससे जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक स्थिति का उन्नयन होगा जो कि देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

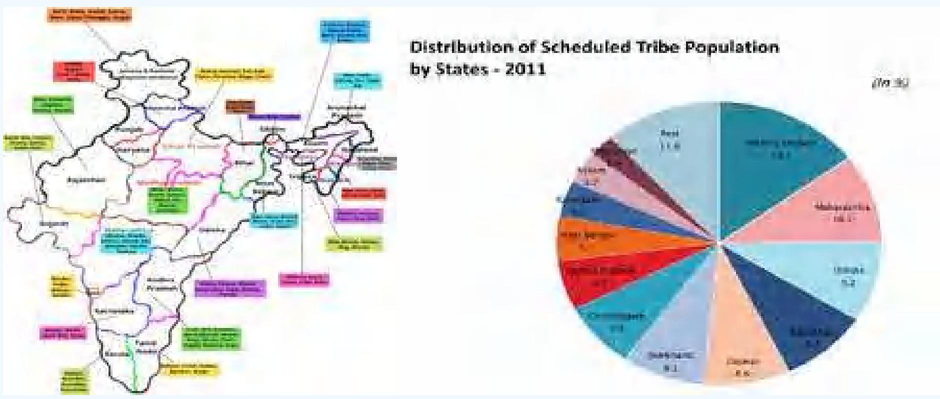

आर्थिक मुद्दे

विश्व की जनसंख्या में वृद्धि के मायने: समस्याएं एवं समाधान

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक आबादी 8 अरब पहुंच गई है।

परिचय:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा वैश्विक आबादी के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व की आबादी 8 अरब की सीमा तक पहुंच चुकी है। ये आंकड़े निश्चित ही जलवायु परिवर्तन, जल-जंगल-जमीन के विवाद तथा तकनीकी प्रवर्धन के संदर्भ में चिंताजनक है जिनका समाधान आवश्यक है।

विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृतियां:

सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र:

- रिपोर्ट में वर्णित आँकड़ों के अनुसार, विश्व की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या एशिया में रहती है। चीन और भारत 2.81 बिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ, दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं।

वृद्धि दर में कमी:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 12 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब तक पहुंची है परंतु 8 अरब से 9 अरब तक पहुंचने के लिए इसे लगभग 15 वर्ष लगेंगे तथा 2037 में विश्व की जनसंख्या 9 अरब होगी।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद सर्वाधिक कम गति से आगे बढ़ रही है जो कि 2020 से लगभग 1% से भी कम हो गई है।
- वैश्विक आबादी का 60% ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से कम है। 1990 में मात्र 40 प्रतिशत लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते थे।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यह अनुमान लगाया है कि 2080 तक विश्व की जनसंख्या 10.4 बिलियन तक पहुंचेगी तथा 2100 ई. तक भी इसी पर स्थिर रहेगी।

जनसंख्या की क्षेत्रीय असमानताएं:

- विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या एशिया में निवास करती है तथा भारत व चीन विश्व के सर्वाधिक 2 बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं।
- रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों में आय का स्तर कम है वहां प्रजनन दर अधिक है।
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया जैसे देश 2050 तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदाई होंगे।
- 2050 तक उप-सहारा क्षेत्र भी जनसंख्या में व्यापक योगदान देगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की प्रवृतियां:

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने बताया कि वर्ष 2020 में लगभग 281 मिलियन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किया है। दक्षिण एशियाई देशों से प्रवास की प्रवृत्ति बहुत व्यापक मात्रा में देखी गई है।

भारत के संबंध में रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- 2023 तक भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होगी।
- भारत में प्रजनन दर 2.1 है जोकि प्रतिस्थापन दर के समान हो चुकी है तथा भविष्य में इसके और अधिक कम होने की संभावना है।
- 2048 तक भारत की आबादी चरम स्थिति के साथ 1.7 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है और 2100 तक यह घटकर 1.1 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है।
- 2022 में भारत की 68% आबादी 15-64 वर्ष के बीच है, जबकि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की आबादी 7% है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान समय में भारत का यूथ बल्ज (Youth Bulge) अधिक है जो 2030 तक यथास्थिति बना रहेगा।
- विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.412 बिलियन तथा चीन की जनसंख्या 1.424 बिलियन है।

जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं:

बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि निश्चित ही कई समस्याओं को जन्म देगी। जैसे:

- **पर्यावरणीय तनाव:** जनसंख्या वृद्धि सतत विकास को प्रभावित करेगी। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा जिसके फलस्वरूप जलवायु संकट और अधिक बढ़ सकता है। अधिक जनसंख्या के लिए आवास, ऊर्जा तथा जल की आपूर्ति पर्यावरण पर दबाव बनाएगी।
- **तकनीकी प्रवर्धन के साथ द्वंद:** वर्तमान समय वैज्ञानिकता से परिपूर्णता का समय है। विश्व चतुर्थ औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर रहा है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा मशीनीकरण के द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होगा जिससे रोजगार के कम होने की व्यापक संभावना

है। इस स्थिति में अधिक जनसंख्या आर्थिक संसाधनों पर भी दबाव उत्पन्न करेगी।

- **वर्ग संघर्षः** बढ़ी हुई जनसंख्या वर्ग संघर्ष को भी बढ़ावा दे सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारी मात्रा में संसाधनों पर अधिकार की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। इसी के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर संरक्षणवाद को बढ़ावा देने वाली सरकारों का निर्माण हो रहा है उदाहरण स्वरूप चिली में। इस संरक्षणवाद के कारण ब्रेक्जिट, डीग्लोबलाइजेशन, ट्रेड वार, आयात प्रतिबंध जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं जो समस्याएं वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देती हैं।
- **असमानताः** जहां एक ओर उत्तरी अमेरिका विश्व के क्षेत्रफल का 16% प्रतिनिधित्व करता है, वहीं वहां की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की केवल 6% प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी तरफ एशिया वैश्विक क्षेत्रफल का 18% है परंतु यहां वैश्विक जनसंख्या का 67% निवास करता है। यह असमानता आय पर भी दिखती है जहां उत्तरी अमेरिका संपूर्ण वैश्विक आय का 45% प्रतिनिधित्व करता है, वहीं एशिया मात्र 12% आय की असमानता जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता में भी वृद्धि करती है। इसके फलस्वरूप एशियाई तथा अफ्रीकी देश जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सुभेद्य हैं।

इन समस्याओं के साथ ही जनसंख्या वृद्धि के कारण युद्ध, महामारी, खाद्य सुरक्षा संकट, ध्रुवीकरण, अनियोजित नगरीकरण, भरण पोषण तथा आवास की समस्या होती है।

जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान कैसे हो?

- **जनसंख्या वृद्धि को साझी समस्या के रूप में ध्यान देनाः** वर्तमान समय में आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन के समान ही जनसंख्या वृद्धि में शादी को वैश्विक समस्या माना जाए तथा यूएनएफसीसीसी के समान ही जनसंख्या वृद्धि के लिए एक नियामक संस्था बनाई जाए। एक वैश्विक संधि के द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर सारे नियम बनाए जाएं जिनका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- **परिवार नियोजनः** परिवार नियोजन एक संकल्पना है जिसके द्वारा परिवार में दंपत्ति द्वारा बच्चों की संख्या सीमित रखने का प्रयास किया जाता है। एक अच्छे राष्ट्र के लिए परिवार नियोजन को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।
- **विवाह की आयु में वृद्धिः** सरकार को लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु में वृद्धि करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप भारत में लड़कों की आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 21 वर्ष करना।
- **मानव संसाधन विकास पर ध्यानः** देश तथा समाज को शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे आयामों पर ध्यान देना चाहिए। इससे न सिर्फ जनसंख्या वृद्धि रुकेगी, बल्कि देशों में आर्थिक विकास भी होगा।
- **भूमि का समुचित उपयोगः** आवास हेतु फ्लैट सिस्टम का प्रयोग, कृषि के समय भूमि क्षरण की अनुचित प्रवृत्तियों का विरोध इत्यादि द्वारा जहां एक तरफ जनसंख्या के आवासन की व्यवस्था की जा सकती है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य को भी सुधारा जा सकता है।
- **कौशल विकासः** कौशल विकास के द्वारा जनसांख्यिकी अभिशाप को, जनसांख्यिकीय लाभांश में परिणित किया जा सकता है। इन कदमों के साथ ही मानव पूंजी अवसंरचना में निवेश, निरोधकों का प्रयोग, जनसंख्या नीति तथा उसका सख्ती से अनुपालन इत्यादि प्रयासों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है।

अन्य तथ्यः

- 253 मिलियन के साथ भारत में दुनिया की सबसे बड़ी किशोर आबादी (10-19 वर्ष) है।
- भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद अभी भी 0.7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है जो इसके यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है।
- यह 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में आरंभ किया गया था। 1987 में जिसे आधिकारिक तौर पर 'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष' नाम दिया गया। इसका जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council & ECOSOC) द्वारा स्थापित किया गया है।

निष्कर्षः

जनसंख्या विस्फोट को एक वैश्विक आपदा समझने के बाद विश्व के कई देशों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेहतर प्रयास किए हैं जिसका परिणाम वैश्विक जनसंख्या दर में कमी के रूप में सामने आया है। यह भी स्पष्ट है कि आय में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि को कम करती है। अतः यह आवश्यक है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र, उप-सहारा क्षेत्र जैसे आर्थिक रुप से कमजोर क्षेत्रों में, वैश्विक सहयोग के माध्यम से विकास को बढ़ावा दिया जाए जो स्वमेव जनसंख्या को कम करने में सहायक होगा।

पर्यावरण

तटीय पारितंत्र के संरक्षण में मैन्ग्रोव की भूमिका

- तटीय पारितंत्र की सुरक्षा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अति महत्त्वपूर्ण है। इसलिए आज विश्व के कई देशों के प्रमुख पारितंत्र के संरक्षण के लिए संवेदनशील हैं। वे इस दिशा में राष्ट्रीय नीतियां भी बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ों पर भी बल दे रहे हैं। हाल ही में मिस्र में सम्पन्न हुए कोप-27 की बैठक में मैन्ग्रोव संरक्षण के लिए राष्ट्रों के बीच एक विशेष सर्वसम्मति देखी गई। विश्व के कई देशों ने मैन्ग्रोव के आवरण को बढ़ाकर इसके कार्बन सिंकिंग की भूमिका पर बल दिया और मैन्ग्रोव अलायन्स फॉर क्लाइमेट लांच किया गया है। मैन्ग्रोव अलायन्स फॉर क्लाइमेट संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के नेतृत्व में शुरू की गई पहल है जिसमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल हैं।
- मैन्ग्रोव अलायन्स फॉर क्लाइमेट का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मैन्ग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता को बढ़ाना है। दूसरे शब्दों में मैन्ग्रोव संरक्षण साक्षरता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। इसी कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री ने अपने देश की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए घोषणा की है कि उनका देश अगले दो माह में 3 मिलियन मैन्ग्रोव लगाने का लक्ष्य रखता है। संयुक्त अरब अमीरात ने ये भी कहा है कि उसने कोप-26 में लक्ष्य तय किया था कि 2030 तक 100 मिलियन मैन्ग्रोव के वृक्ष लगायेंगे।
- अब यहां एक सवाल ये उठता है कि संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देश मैन्ग्रोव लगाने पर इतना बल क्यों दे रहे हैं? मैन्ग्रोव का पर्यावरण संरक्षण में क्या स्थान है जो कोप-27 में राष्ट्रों की रुचि का विषय बना? दरअसल, मैन्ग्रोव किसी भी पारितंत्र में समुद्र और स्थल के बीच सहजीवी संबंध (Symbiotic Relation) को दर्शाते हैं। ये तटीय जैवविविधता के संरक्षण तथा मत्स्य संसाधन की सुरक्षा के जरिये मछुआरों के आजीविका के संरक्षण का मजबूत माध्यम हैं। यह वैश्विक रूप से संकटापन्न जीव-जंतुओं के संरक्षण का प्रभावी आधार है। यह प्लैंक्टन, समुद्री अकशेरुकी जीवों, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों और स्तनपायी जीवों के संरक्षण को आधार प्रदान करता है। मैन्ग्रोव को टाइडल फॉरेस्ट्स, कोस्टल वुडलैंड्स, वॉकिंग फॉरेस्ट इन दि सी, रुट ऑफ दि सी और ओशेनिक रेन फॉरेस्ट्स के नाम से भी जाना जाता है।

समुद्री जल में चट्टान की तरह रहता है मैन्ग्रोव:

- मैन्ग्रोव लवणता या खारेपन को अवशोषित करने वाले ऐसे पादप समुदाय (Salt Tolerant Plant Communities) होते हैं जो विश्व में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019 में बताया गया है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां उच्च वर्षा 1,000 से 3,000 मिलीमीटर तक और तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहां पर मैन्ग्रोव की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। मैंग्रोव पारितंत्र इसलिए खास होते हैं क्योंकि इनमें बेहतरीन अनुकूलन क्षमता पायी जाती है जिनकी आकारिकी (Marphology), शरीर रचना (Anatomy) और शरीर क्रिया विज्ञान (Physiology) ऐसी होती है जो इन्हें जलमग्न मिट्टी को जीवित रखने में मददगार होती है। इनकी अनुकूलन क्षमता ऐसी है कि ये उच्च लवणता तथा बारंबार आने वाले चक्रवाती तूफानों और ज्वारीय उफानों (Tidal Surges) से आसानी से निपट सकती है। इनकी जड़े ऐसी होती हैं जिससे ये तटीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने में समर्थ होते हैं। मैन्ग्रोव पादपों में विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूलन की क्षमता होती है। ये ब्रीडिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर्स, स्टिल्ट रूट्स, बट्रेस रूट्स और विविपैरस रूट्स विशेषताओं से होती हैं।
- उल्लेखनीय है कि मैन्ग्रोव कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। किसी भी पौधे के भूमिगत ऊतक को श्वसन के लिये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन मैंग्रोव वातावरण में मिट्टी में ऑक्सीजन सीमित या शून्य होती है।
- इसलिये मैंग्रोव जड़ प्रणाली वातावरण से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। इस उद्देश्य के लिये मैंग्रोव की जड़ें आम पौधों से अलग होती हैं जिन्हें ब्रीडिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। इन जड़ों में कई छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ऑक्सीजन भूमिगत ऊतकों में प्रवेश करती है।
- **विवियोपोरस विशेषता:** कुछ मैंग्रोव प्रजातियों में जड़े अपने तने और शाखाओं से अलग रास्ता अपनाती हैं तथा अपने मुख्य तने से कुछ दूर जाकर मिट्टी में अपनी जगह बनाती हैं, ऐसा ही केले के वृक्ष में भी होता है। मैन्ग्रोव की ऐसी जड़ें अपने रूप आकार और अपने द्वारा मिट्टी के किसी क्षेत्र को भौतिक सहायता देने के चलते स्टिल्ट रुट कहलाती हैं। इन जड़ों में भी कई छिद्र होते हैं जिससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन जड़ों में पहुँचता रहता है। वहीं मैन्ग्रोव के विविपैरी (Vivipary) विशेषता की बात करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लवणीय या खारा जल और दुर्बल लवणीय मिट्टी जो बिना ऑक्सीजन की या बहुत ही कम ऑक्सीजन के साथ हो, वो बीजों को अंकुरित होने के लिए तथा मजबूती पाने के लिए उचित पर्यावरण नहीं दे सकता। इस समस्या से निपटने के लिए मैन्ग्रोव प्रजातियों में रिप्रोडक्शन की एक अनोखी व्यवस्था होती है जिसे विविपैरी कहते हैं। प्रजनन के इस प्रकार में बीज सीडलिंग्स में अंकुरित और विकसित होते हैं जबकि उस समय भी वे अपने मूल वृक्ष (Parent Tree) से

जुड़े होते हैं। इन सीडलिंग्स को आमतौर पर प्रोपाग्यूल्स कहते हैं और वे उस वक्त भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जब वे अपने मदर ट्री से जुड़े होते हैं।

- परिपक्व अंकुर पानी में गिर जाता है और किसी अलग स्थान पर पहुँच कर ठोस जमीन में जड़ें जमा लेता है।

ब्लू कार्बन के भंडारण का जरिया हैं मैन्ग्रोव:

- समुद्री पारितंत्र का 2 प्रतिशत से भी कम हिस्सा मैंग्रोव का है, लेकिन ये 10-15 प्रतिशत कार्बन अवशोषित करते हैं। एक बार जब पत्ते और पुराने पेड़ मर जाते हैं तो वे समुद्र तल पर गिर जाते हैं तथा संग्रहीत कार्बन को अपने साथ मिट्टी में दबा लेते हैं। इस दबे हुए कार्बन को 'ब्लू कार्बन' के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह मैंग्रोव जंगलों, समुद्री घास और नमक के दलदल जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्र में पानी के नीचे जमा होता है।

भारत में मैन्ग्रोव संरक्षण:

- भारत में मैंग्रोव संरक्षण तथा संवर्द्धन की पहल सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों ही स्तरों पर की जा रही है। सरकार ने देश में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ नियामक उपायों के माध्यम से कदम उठाए हैं। मैंग्रोव तथा प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता प्रसार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी तटीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव संरक्षण और प्रबंधन के लिए वार्षिक कार्ययोजना क्रियान्वित की गई है। इस कड़ी में कुछ महीनों पहले भारत की जिन पांच आर्द्र भूमियों को रामसर की अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता मिली है, उनमें तमिलनाडु का पिचवरम मैंग्रोव क्षेत्र शामिल है।
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तटीय संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से तीन राज्यों गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का संचालन कर रहा है, जिसकी गतिविधियों में मैंग्रोव का रोपण उल्लेखनीय रूप से शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मैंग्रोव संरक्षण के लिए समर्पित एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की गई है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव वैश्विक संरक्षण के प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में 5000 वर्ग किलोमीटर में फैली मैंग्रोव की 50 से अधिक प्रजातियां हो सकती हैं। भारत मैंग्रोव के संरक्षण और बहाली पर जोर दे रहा है। इससे जैव विविधता के समृद्ध स्थल सरंक्षित रहेंगे और प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में काम करते रहेंगे।
- भारत में मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर की बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2019 के अनुसार भारत में मैंग्रोव कवर 4,975 वर्ग किमी. है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15 प्रतिशत है। प्रतिशत के हिसाब से कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है जिसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है।
- यह वन रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और ज्वारनदमुख वाले मगरमच्छों का घर है, वहीं भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ओडिशा के भितरकनिका में स्थित है जो ब्राह्मणी और वैतरनी नदी के दो नदी डेल्टाओं द्वारा बनाया गया है। यह भारत में सबसे महत्त्वपूर्ण रामसर आर्द्रभूमि में से एक है। गोदावरी-कृष्णा मैंग्रोव क्षेत्र ओडिशा से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं।
- गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा में मैंग्रोव वन फैले हैं। केरल के बैकवाटर में मैंग्रोव वन का घनत्व उच्च है। तमिलनाडु के पिचावरम में मैंग्रोव वनों से आच्छादित जल विस्तृत क्षेत्र में फैला है। यह कई जलीय पक्षी प्रजातियों का घर है। पश्चिम बंगाल में भारत के मैंग्रोव कवर का 42.45 प्रतिशत हिस्सा है जिसके बाद गुजरात 23.66 प्रतिशत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 12.39 प्रतिशत हैं।

सामाजिक मुद्दे

लिव-इन रिलेशनशिपः व्यक्तिगत स्वतंत्रता या नैतिक असमंजस

सन्दर्भः

हाल ही में लिव-इन पार्टनर आफताब द्वारा श्रद्धा की निर्मम हत्या ने समाज की आत्मा को झकझोर दिया जिसके बाद से 'लिव-इन रिलेशनशिप' में नैतिकता के मुद्दों को लेकर नये सिरे से बहस शुरू हो गयी है। यद्यपि लिव-इन रिलेशनशिप ने युवाओं के बीच अपनी जगह बनाई है।

परिचयः

भारत प्राचीन संस्कृतियों का देश रहा है, जहां खान-पान, रहन-सहन, आदि सब में संस्कृति गूढ़ रूप से विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति व समाज समय के साथ बदल रही है। लिव-इन रिलेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रेमी युगल भविष्य में विवाह करने या न करने के इरादे से दीर्घकालिक या अल्पावधि के आधार पर एक साथ रहने का निर्णय लेते हैं। इन दिनों 'लिव-इन रिलेशनशिप' शब्द का अधिकांशतः प्रयोग 'बिना शादी किये एकसाथ रहने वाले जोड़े' के संदर्भ में किया जाता है। भारतीय कानून में लिव-इन रिलेशनशिप की कोई परिभाषा वर्णित नहीं है।

लिव-इन रिलेशनशिप के विभिन्न पहलुः

- लिव-इन बिना विवाह (अर्थात विवाह द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के बिना) के दाम्पत्य जीवन का अनुभव करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों युग्ल को अपना व्यक्तिगत स्पेस मिल जाता है, जहाँ वो बिना अतिरिक्त जिम्मेदारियों के जीवन का आनन्द उठा सकते हैं। शादी जैसी लगभग बंद व्यवस्था के विपरीत 'लिव-इन रिलेशनशिप' में आना-जाना आसान है। दोनों में से कोई भी रिश्ते से बाहर निकल सकता है, जब रिश्ता सहजता से नहीं चल रहा हो। साथ ही अपने 'लिव-इन-पार्टनर' को बदलना भी आसान होता है, जब आप अपने सहसाथी से संतुष्ट न हो। इसके विपरीत विभिन्न धर्मों में विवाह को एक 'संस्कार' के रूप में माना जाता है, जो सात जन्मों का रिश्ता होता है, जिसे स्वर्ग में बनाया जाता है। चूँकि विवाह एक सामजिक और कानूनी व्यवस्था है, इससे बाहर निकलने अर्थात तलाक में समय लगता है और समाज तलाकशुदा लोगों के प्रति तिरस्कार का भाव रखता है।
- यह विवाहित जीवन से पूर्व अभ्यास के रूप में होता है। युगल को पर्याप्त समय मिलता है अपने सहसाथी को, उनकी रूचियाँ तथा विचारों को जानने-समझने का। यह दोनों के बीच परस्पर विश्वास की एक मजबूत नींव तैयार करता है, जो किसी भी रिश्ते के लिए पूर्व आवश्यक शर्त है। 'लिव-इन रिलेशनशिप' विवाह की तुलना में अधिक लैंगिक समावेशी है, जहाँ पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार करते हैं तथा बराबरी के साथ घरेलू और वित्तीय जिम्मेदारियां साझा करते हैं। महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत करने वाले, जो विवाह को पुरुष वर्चस्व वाली पितृसत्तात्मकता संस्था के रूप देखती है, 'लिव-इन रिलेशनशिप' के प्रबल समर्थक हैं। अधिकांश अच्छी जॉब करने वाले उच्च महत्त्वाकांक्षी युवा 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहते हैं क्योंकि यह विवाह से पहले, कैरियर की प्रगति और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह एलजीबीटीक्यू, अंतर-जाति और अंतर-धार्मिक युगल के लिए एक वैकल्पिक द्वार है जो अन्य सामाजिक नियमों का निषेध करता है।
- भारत में शादी से पहले किसी के साथ रहना टैबू माना जाता है। भारत में विवाह विशेष रूप से औरत की वर्जिनिटी (कौमार्य) का प्रश्न होता है। शादी से पहले अपने साथी के साथ रहने वाली महिला को अपवित्र और चरित्रहीन समझा जाता है। इस प्रकार यह सामजिक मूल्यों और मानदंडों के विरुद्ध है। चूंकि 'लिव-इन रिलेशनशिप' से बाहर निकलना आसान है, इसलिए यह अत्यधिक अस्थिर और सामाजिक रूप से असुरक्षित व्यवस्था है। प्रतिबद्धता की कमी के कारण, पार्टनर एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाने से बचने की कोशिश करते हैं। इसके लचीले चरित्र के कारण, एक व्यक्ति एक समय में कई पार्टनर के साथ लिव इन में रह सकता है जिससे वफादार साथी मानसिक पीड़ा तथा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। गलत व्यक्ति के साथ रिश्ते में पड़कर विशेषकर महिलाओं को यौन सुख के उपकरण के रूप में प्रत्युक्त करके उनका शोषण किया जा सकता है। लिव-इन रिलेशनशिप से भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चे के अधिकारों (अच्छी परवरिश तथा पिता की सम्पत्ति में अधिकार) के संबंध में कुछ वाजिब चिंताएं हैं। आमतौर पर दादा-दादी अपने पोते पोतियों को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चें के प्रति दादा-दादी अक्सर उपेक्षा का भाव रखते हैं, जिससे बच्चे की परवरिश प्रभावित हो सकती है।

लिव-इन रिलेशनशिप पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयः

- पटेल और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि औपचारिक विवाह के बिना दो वयस्कों के बीच 'लिव-इन रिलेशनशिप' को अपराध नहीं माना जा सकता। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो लिव-इन रिलेशनशिप को अवैध ठहराए। इसी प्रस्ताव को तुलसा बनाम दुर्घाटिया मामले में सही ठहराया

गया था, जहां कई वर्षों के 'लिव-इन रिलेशनशिप' को शादी के समान मान्यता प्रदान की गयी थी। खुशबू बनाम कन्नियाम्मल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'लिव-इन रिलेशनशिप' को एक कदम आगे बढ़ कर सकारात्मक प्रोत्साहन प्रदान किया है। मामले में अभियोग पक्ष का दावा था कि कथित तौर पर अभिनेत्री खुशबू की विवाहपूर्व सेक्स की टिप्पणी से समाज के नैतिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि शादी के बिना साथ रहना कोई अपराध नहीं है, अर्थात परस्पर सहमति के साथ, वयस्क व्यक्तियों द्वारा बनाये गये विवाहपूर्व संबंध अपराध नहीं है।

- इन्हीं प्रगतिशील विचारों को आगे बढाते हुए डी. वेलुसामी बनाम डी. पच्चौअम्मल मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'लिव-इन रिलेशनशिप' और शादी के संबंध की प्रकृति को समान मान्यता देते हुए, लिव-इन में रहने वाली महिला को, सहसाथी द्वारा गुजारा भत्ता देने का निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बिना विवाह के साथ रहने वाली महिलाएं यदि निम्नलिखित चार शर्ते पूरी करती हैं, तो वह गुजारा भत्ता पाने की पात्र होंगी:
  1. दंपत्ति को समाज के समक्ष जीवनसाथी के रूप में व्यवहार करना होगा।
  2. आवश्यक रूप से वे विवाह करने की कानूनी आयु को पूरा कर चुके हो।
  3. वैध विवाह के लिए आवश्यक सभी मापदण्ड को पूरा करते हो।
  4. आवश्यक रूप से उन्होंने परस्पर सहमति से सहवास किया हो, साथ ही दुनिया के समक्ष कम से कम कुछ समय के लिए जीवनसाथी के रूप में रहे हो।
- न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शामिल 'शादी की प्रकृति' से संबंधित शर्ते पूरी करना भी आवश्यक है। अधिनियम की धारा-2 के अंतर्गत युगल को अनिवार्य रूप से एकसाथ एक छत के नीचे (केवल वीकेंड या एक रात के संबंध के आधार पर नहीं) रहने का प्रावधान पूरा करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय देते हुए कहा कि सारे 'लिव-इन रिलेशनशिप' के मामलों को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों/सुविधाओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
- इसी तरह अन्य प्रमुख चिंता, लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे की वैधता के निर्धारण के संदर्भ में है। सर्वोच्च न्यायालय ने उदय कुमार बनाम आयशा और अन्य मामले में कहा कि लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से बच्चे पैदा हो सकते हैं, जिन्हें नाजायज (अवैध) नहीं कहा जा सकता। इस निर्णय ने पूर्व के लंबित कई मामलों का समाधान प्रस्तुत किया।
- इसलिए जब भी 'लिव-इन रिलेशनशिप' की बात आती है, न्यायालय द्वारा एकरूपता लाने की दिशा में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलती है।

आगे की राह:

यद्यपि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, अनुच्छेद-21 में वर्णित गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार में शामिल है, फिर भी 'लिव-इन रिलेशनशिप' को समग्रता के साथ विनियमित नहीं किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन साथी के चयन में सतर्कता बरतनी चाहिए। अपने परिजनों माता-पिता तथा अभिभावकों को जीवन के सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय में शामिल करना चाहिए ताकि व्यक्तिगत खुशी तथा दायित्वों का सार्वभौमिकता के रूप में बढ़ावा दिया जा सके।

ध्येयIAS most trusted since 2003
NEW BATCH - FACE TO FACE
GENERAL STUDIES
for PCS
Bilingual
16th DECEMBER
8 AM & 6 PM
for IAS
Hindi & English Medium
2nd JANUARY
8 AM & 5:30 PM
CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5
Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow , UP
7234000501 / 02

1 NCW ने महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक करने हेतु डिजिटल शक्ति 4.0 किया लॉन्च

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने साइबर स्पेस में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा कौशल प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय परियोजना, डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की। NCW ने इसे साइबरपीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया।

डिजिटल शक्ति अभियान के बारे में:

- डिजिटल मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने तथा देश भर में महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में यह अभियान शुरू किया गया था।
- इस परियोजना के माध्यम से भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबरस्पेस सुरक्षा टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जागरूक किया गया है।
- यह महिलाओं के लिए रिपोर्टिंग तथा निवारण तंत्र, डेटा गोपनीयता और प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद करता है।
- अभियान का तीसरा चरण, जो मार्च 2021 में लेह में शुरू किया गया था, एक महिला द्वारा किसी साइबर अपराध का सामना करने की स्थिति में रिपोर्टिंग पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक संसाधन केंद्र विकसित किया गया था।

डिजिटल शक्ति 4.0:

- चौथा चरण महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध/अनुचित गतिविधि के खिलाफ सशक्त पर केंद्रित है।
- डिजिटल शक्ति महिलाओं और लड़कियों को उनके लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तथा खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखने हेतु प्रशिक्षित करके उनकी डिजिटल भागीदारी में तेजी ला रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW):

- NCW की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। NCW की वर्तमान अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा हैं।
- इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ हैं।
- यह शिकायतों पर गौर करता है और महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने, कानूनों को लागू न करने तथा महिला समाज के कल्याण के संबंध में नीतिगत निर्णयों के गैर-अनुपालन से संबंधित मामलों का स्वत: संज्ञान लेता है।

एनसीडब्ल्यू के प्रमुख कार्य:

1. महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
2. उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।
3. शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना।
4. महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

आगे की राह:

डिजिटल शक्ति महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ साइबर हिंसा से लड़ने के बड़े लक्ष्य की दिशा में योगदान करेगी तथा इंटरनेट को उनके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएगी। यह पहल पूरे देश में हर जगह महिलाओं को सशक्त बनाने के आयोग के निरंतर प्रयास को मजबूती प्रदान करेगी।

2 धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्च मानक स्थापित करने की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

पिछले कुछ वर्षों में धर्मांतरण राजनीतिक रूप से एक गंभीर मुद्दा बन गया है। धर्म परिवर्तन की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण बहुत खतरनाक है। इससे 'अंतत: राष्ट्र की सुरक्षा के साथ-साथ धर्म की स्वतंत्रता और नागरिकों की अंतरात्मा प्रभावित होती है'।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों की पृष्ठभूमि:

- हिंदू शाही परिवारों की अध्यक्षता वाली रियासतों ने सबसे पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, विशेष रूप से 1930 और 1940 के दशक के उत्तरार्ध में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने वाले कानून पेश किए।
- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किए जो केवल विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन

को प्रतिबंधित करते हैं।

- उत्तर प्रदेश धार्मिक धर्मांतरण निषेध अध्यादेश, 2020 को भी 60 दिनों के नोटिस की आवश्यकता है। हालांकि, धर्मांतरण के पीछे की असली मंशा का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट को पुलिस जांच करने का भी अधिकार है।
- मध्य प्रदेश कानून के तहत, यह साबित करने का दायित्व, कि धर्मांतरण वैध तरीके से किया गया था, यह धर्मांतरित व्यक्ति पर निर्भर है।

मुख्य बिंदु:

- पीठ ने सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए संघ, राज्य या अन्य संस्थाओं द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं, यदि धर्मांतरण बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से हुआ हो।
- जब अदालत स्वतः इस मुद्दे पर ध्यान देती है, पूछती है कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, तो इसका मतलब है कि 'जबरन' धर्मांतरण एक महत्त्वपूर्ण समस्या है और मौजूदा कानून इससे निपटने के लिए अपर्याप्त हैं।
- संविधान का अनुच्छेद-25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार है, लेकिन कम से कम 10 राज्यों ने अभी तक 1960 के दशक से धर्मांतरण विरोधी कानून बना चुके हैं।
- दावा यह है कि आईपीसी प्रावधानों सहित कानूनी सुरक्षा उपाय जबरदस्ती धमकाना, लुभाना या धमकी के माध्यम से धर्मांतरण को रोकने में विफल रहे हैं। हालांकि, इन शब्दों का गलत अर्थ निकाला जाता रहा है।
- धर्मांतरण की बहस का वर्तमान संदर्भ आदिवासी क्षेत्रों और अंतर-धार्मिक विवाहों में बढ़ते मिशनरी गतिविधियों के कारण है।

ऐसे कानूनों के सन्दर्भ में न्यायिक आदेश:

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सलामत अंसारी-प्रियंका खरवार 2020 के मामले में साथी चुनने या पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार को अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है।
- **हादिया केस:** इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि पोशाक और भोजन, विचारों तथा विचारधाराओं के मामले, प्रेम और साझेदारी आदि पहचान के केंद्रीय पहलुओं के भीतर हैं। अतः इसमें न तो राज्य और न ही कोई अन्य कानूनी पार्टनर्स किसी प्रकार की स्वतंत्रता को बाधित या सीमित कर सकते हैं।
- **सरला मुद्गल केस:** अदालत ने माना था कि गैर-इस्लामिक आस्था वाले व्यक्ति द्वारा इस्लाम में धर्मांतरण वैध नहीं है यदि धर्मांतरण बहुविवाह के उद्देश्य से किया जाता है।

आगे की राह:

न्यायपालिका को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में सक्रियतापूर्ण निर्णय दे ताकि प्रत्येक नागरिक ऐसे कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हों जो स्वयं या दूसरों के लिए हानिकारक न हों। हालांकि, धोखाधड़ी धर्मांतरणों के खिलाफ कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि यह मौलिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे। धर्म परिवर्तन पर न्यायिक और विवेकपूर्ण हस्तक्षेप के प्रति सचेत होना चाहिए ताकि अस्पष्ट शब्दावली और पूर्वाग्रह को दूर किया जा सके।

3 किशोर न्याय अधिनियम, 2015

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा है कि उदार किशोर कानून ने किशोरों को जघन्य अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया है और कोर्ट ने सरकार को कानून की फिर से जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कोर्ट ने 8 साल की बच्ची की हत्या और रेप पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जघन्य अपराध के लिए नाबालिगों को वयस्कों की तरह माना जाएगा। अदालत ने इस बारे में संदेह व्यक्त किया कि क्या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 कम सजा के प्रावधान के साथ किशोर अपराधियों के लिए जघन्य अपराध करने के लिए सुरक्षा जाल बन गया है?

किशोर न्याय अधिनियम (जेजे अधिनियम) की वर्तमान स्थिति:

- किशोर न्याय अधिनियम के तहत, अपराधों को 'छोटे अपराध' [धारा 2 (45)], 'गंभीर अपराध' [धारा 2 (54)], और 'जघन्य अपराध' [धारा 2 (33)] में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों के साथ उस अपराध की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग व्यवहार किया जाता है, जिस पर उनके द्वारा किए जाने का आरोप लगाया जाता है। 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, जिस पर जघन्य अपराध करने का आरोप है, को प्रारंभिक मूल्यांकन [धारा 15 (1)] आयोजित करने के बाद बोर्ड द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में छूट दी जा सकती है।
- प्रारंभिक मूल्यांकन के तहत, एक बच्चे की इस तरह का अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों

को समझने की क्षमता और जिन परिस्थितियों में उसने कथित रूप से अपराध किया है का आकलन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन के पूरा होने पर, बोर्ड जेजे अधिनियम [धारा 15(2)] के तहत मामले को समझ सकता है, या बच्चे को एक वयस्क के रूप में मानने और मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश पारित कर सकता है [धारा 18(3])]। ऐसे मामलों की समझ के लिए सत्र न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। बाल न्यायालयों को यह तय करने का अधिकार है कि क्या उसके सामने पेश किए गए बच्चे को आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत एक वयस्क के रूप में माना जाना चाहिए या किशोर न्याय प्रणाली के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को एक बोर्ड के रूप में जांच करना चाहिए (धारा 19)।

- एक वयस्क के रूप में व्यवहार किए गए बच्चे के मुकदमे के निर्णय पर, बाल न्यायालय को उसे दोषी पाते हुए बच्चे की विशेष जरूरतों, निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों और बाल-सुलभ माहौल बनाए रखने पर विचार करते हुए एक आदेश पारित कर सकता है [धारा-19 (1)(I)]। किसी बच्चे को मौत या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती (धारा 21)।
- बाल न्यायालय द्वारा सजा दिए गए बच्चे को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सुरक्षित स्थान पर अपनी सजा भुगतनी होगी। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन करके यह पता लगाया जाएगा कि क्या उसने सुधारात्मक परिवर्तन किए हैं और यदि बच्चा समाज का योगदान देने वाला सदस्य हो सकता है [धारा 20 (1)] और ऐसा पाए जाने पर, बाल न्यायालय बच्चे को शर्तों [धारा 20 (2) (i)] पर रिहा कर सकता है, और यदि नहीं, तो बच्चा अपने शेष कार्यकाल को पूरा करने के लिए जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है [धारा 20 (2) (ii)]।

आगे की राह:

जेजे एक्ट के प्रावधानों के विश्लेषण पर न्यायिक अवलोकन पूरी तरह से सही नहीं है। किशोर छूट प्रणाली अधिनियम में मौजूद है, इसलिए यह कहना कि यह उदार है, खुद को गलत साबित करता है। जब विधेयक को संसद में पेश किया गया, तो कई बाल कल्याण संगठनों ने बाल अधिकारों के खिलाफ होने के कारण किशोर छूट प्रणाली की आलोचना की। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि जेजे अधिनियम अपने आप में एक कठिन कार्य है और बाल कल्याण के लिए एक सुधारवादी दृष्टिकोण जारी रहना चाहिए।

4 नेटवर्क तैयारी सूचकांक 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट (एनआरआई 2022) के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति में छह पायदान का सुधार किया है और अब इसे 61वें स्थान पर रखा गया है।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट:

- रिपोर्ट वाशिंगटन स्थित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी, गैर-पक्षपातपूर्ण अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान, पोर्टुलान्स संस्थान द्वारा तैयार की गई है।
- यह इंडेक्स मापता है कि कोई अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मकता तथा भलाई को बढ़ावा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का कितनी अच्छी तरह उपयोग कर रही है।
- 2022 के अपने नवीनतम संस्करण में, एनआरआई रिपोर्ट ने 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क-आधारित तत्परता परिदृश्य को मैप किया है।
- एनआरआई चार अलग-अलग स्तंभों के आधार पर रैंक करता है: प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव, जिसमें कुल 58 विषय शामिल हैं।
- सूचकांक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव दोनों के संदर्भ में मापता है। यह दर्शाता है कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए बदलाव के लाभों को एक देश कैसे प्राप्त करेगा।

NRI-2022-महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष:

- संयुक्त राज्य अमेरिका 80.3 के कुल स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा जिसके बाद सिंगापुर (79.35) और स्वीडन (78.91) का स्थान रहा।
- सिंगापुर ने 2021 में रैंक 7 से 2022 में दूसरे स्थान पर त्वरित सुधार देखा है।
- शीर्ष 10 प्रदर्शनकर्त्ता नीदरलैंड (चौथा), स्विट्जरलैंड (पांचवां), डेनमार्क (छठा), फिनलैंड (सातवां), जर्मनी (आठवां), दक्षिण कोरिया (नौवां) और नॉर्वे (दसवां) हैं।

एनआरआई पर भारत का प्रदर्शन:

- भारत का स्कोर 2021 में 49.74 से सुधरकर 2022 में 51.19 हो गया।

भारत विशिष्ट संकेतक:

1. 'एआई प्रतिभा एकाग्रता' में पहली रैंक।
2. 'अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ' और 'देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट' ट्रैफिक में दूसरा स्थान।
3. 'दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश' और 'घरेलू बाजार आकार' में तीसरी रैंक।
4. 'आईसीटी सेवा निर्यात' में चौथा स्थान।
5. 'FTTH/बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन' और 'AI साइंटिफिक पब्लिकेशन' में 5वीं रैंक।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास अपनी आय के स्तर को देखते हुए उम्मीद से कहीं अधिक नेटवर्क तैयार है।
- यूक्रेन(50) और इंडोनेशिया (59) के बाद भारत निम्न-मध्यम-आय वाले देशों के समूह में 36 में से तीसरे स्थान पर है। इसने सभी स्तंभों और उप-स्तंभों में आय वर्ग के औसत से अधिक अंक प्राप्त किए।
- भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 11वें स्थान पर है।

आगे की राह:

रिपोर्ट का उद्देश्य नीति निर्माताओं को उन शक्तियों और कमजोरियों के लिए सचेत करना है जिन्हें दूर किया जा सकता है तथा उन्हें रणनीतिक निर्णय लेने और उचित कार्यवाही करने में मदद करें।

5 विमान सुरक्षा नियम 2022

चर्चा में क्यों?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान सुरक्षा नियम, 2022 के मसौदे को अधिसूचित किया है।

विमान सुरक्षा नियमों के बारे में:

- यह नियम विमान सुरक्षा नियम, 2011 का स्थान लेंगे और संसद द्वारा सितंबर 2020 में विमान संशोधन अधिनियम, 2020 पारित किए जाने के बाद आवश्यक थे। यह नागरिक उड्डयन और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक के साथ-साथ बीसीएएस को वैधानिक शक्तियां प्रदान करते हैं।
- मसौदा विमान सुरक्षा नियम, 2022 नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) को सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए हवाई अड्डों और एयरलाइंस (कंपनी के आकार के आधार पर) पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने में सक्षम करेगा। बीसीएएस हवाई अड्डों और एयरलाइंस पर भी जुर्माना लगा सकता है:
  - अगर वे एक सुरक्षा कार्यक्रम विकसित करने और लागू करने में विफल रहते हैं।
  - यदि वे सुरक्षा मंजूरी मांगे बिना संचालन शुरू करते हैं।
- बीसीएएस किसी इकाई के हवाई अड्डे की सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम को निलंबित या रद्द करने में भी सक्षम होगा।
- नियमों में प्रत्येक इकाई को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों को अनधिकृत पहुंच से बचाने और संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाने की भी आवश्यकता है।
- इससे संगठनों को साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने में मदद मिलेगी।
- नियम 'गैर-प्रमुख क्षेत्रों' में सीआईएसएफ कर्मियों के बजाय निजी सुरक्षा एजेंटों को नियुक्त करने और राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 द्वारा अनुशंसित सुरक्षा कर्तव्यों को सौंपने के लिए हवाई अड्डों को अधिकृत करते हैं।

संशोधन की क्या आवश्यकता है?

- संयुक्त राष्ट्र के एविएशन वॉचडॉग, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) के बाद संशोधन की आवश्यकता थी, वैधानिक शक्तियों के बिना काम करने वाले तीन नियामकों के बारे में सवाल उठाए थे।
- विमान (संशोधन) विधेयक 2020 ने 1934 के विमान अधिनियम में संशोधन करके नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) को वैधानिक संगठनों के रूप में मान्यता दी।

आगे की राह:

विमान सुरक्षा नियम 2022 के लागू होने के बाद, देश में एक प्रभावी विमानन सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करने में काफी मदद साबित होंगे।

6 नो शेव नवंबर और मोवेम्बर-कैंसर जागरूकता आंदोलन

चर्चा में क्यों?

कैंसर के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नवंबर माह में नो शेव नवंबर (No Shave november) और मोवेम्बर (Movember) पहल शुरू हो जाती है। इन आंदोलनों के दौरान कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से व्यक्ति शेविंग/ग्रूमिंग गतिविधियों को नहीं करते है। इससे बचने वाले पैसे को कैंसर के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन मैथ्यू हिल फाउंडेशन को दान दिया जाता है। यह फाउंडेशन इन पैसों को उन संस्थाओं तक पहुंचाता है जो कैंसर से बचाव, इलाज, रिसर्च और एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं।

नो शेव नवंबर और मोवेम्बर अभियान से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु-

- शिकागो स्थित हिल परिवार के बच्चों ने इसे 2009 में शुरू करने का फैसला किया जिसका उद्देश्य उनके पिता मैथ्यू हिल की मृत्यु के बाद दान के लिए धन जुटाना था। मैथ्यू हिल एक पेट के कैंसर के रोगी थे जिनकी नवंबर 2007 में मृत्यु हो गई थी।
- 2004 में शुरू किया गया मोवेंबर (Movember) भी एक जागरूकता अभियान है। ये दो शब्दों मुश्टैश (मूंछ) और नवंबर को मिलाकर बनाया गया शब्द है। नो शेव नवंबर जहां सिर्फ कैंसर अवेयरनेस तक सीमित है, वहीं मोवेंबर इसके साथ-साथ पुरुषों के हेल्थ और लाइफस्टाइल की तरफ अवेयर करने का काम करता है। इस कैंपेन में पुरुष नवंबर में मूंछें उगाकर इसे अपना सपोर्ट देते हैं।
- यह प्रोस्टेट कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों, वृषण कैंसर सहित पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलता है।

ये आंदोलन कितने सफल हैं?

- 'नो शेव नवंबर' और 'मोवेम्बर' दोनों पहलों ने विश्व स्तर पर काफी लोकप्रियता हासिल की है।
- 'नो शेव नवंबर' की वेबसाइट के अनुसार यह पहल कैंसर जागरूकता, अनुसंधान और रोकथाम के लिए करीब 12 मिलियन डॉलर जुटाने में सक्षम रही है।
- दूसरी ओर, मोवेंबर के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2021 में दुनिया भर में छह मिलियन मो ब्रोस (पुरुष प्रतिभागी) और मो सिस्टर्स (महिला प्रतिभागी) की भागीदारी दर्ज की तथा सामूहिक रूप से वे लगभग 87.9 मिलियन डॉलर जुटाने में सक्षम रहीं।

भारत द्वारा कैंसर के क्षेत्र में किए गए कार्यः

- भारत सरकार द्वारा कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शुरू किए राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जिला स्तर तक लागू किया जा रहा है।
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG) भी स्थापित किया है। अगस्त 2022 में, राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड ने पूरे भारत में कैंसर की देखभाल में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोइता सेंटर फॉर डिजिटल ऑन्कोलॉजी (केसीडीओ) की स्थापना की।

7 भारत निर्वाचन आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

चर्चा में क्यों?

- हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच चुनाव आयुक्तों के लिए कार्यात्मक स्वतंत्रता की मांग करने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 1950 के दशक में आठ साल से गिरकर 2004 के बाद से अब तक तीन सौ दिनों से भी कम रह गया हैं।
- शीर्ष अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया की पर तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि ये नियुक्तियां संवैधानिकता को चुनौती दे रही है।

SC ने चुनाव आयुक्तों के बारे में क्या कहा है?

- भारत के संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को अत्यधिक जिम्मेदारी व शक्तियां प्राप्त हैं।
- योग्यता के साथ, चरित्र भी महत्त्वपूर्ण है, ताकि चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए लोग अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें।
- अदालत ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 324 में ऐसी नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया प्रदान करने के लिए एक कानून बनाने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
- ऐसी नियुक्तियों में निगरानी के लिए कानून के अभाव में सरकारें फायदा उठा रही हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त छह साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं। सरकार 65 वर्ष के करीब किसी व्यक्ति को चुनती है जो पूरे छह साल की सेवा नहीं दे पाता, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर होती है।

सरकार की राय:

- इस मुद्दे पर संविधान में किसी तरह की चर्चा नहीं की गई है।
- यदि संविधान, मूल संविधान सभा द्वारा रखे गए कई विचारों के बावजूद कोई रुख अपनाता है, तो उस स्थिति का विरोध नहीं किया जा सकता है।
- शक्तियों के पृथक्करण को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह संविधान की मूल विशेषता है।
- यह मामला संसद में बहस के लिए है न कि अदालत में।

सुप्रीम कोर्ट का सुझाव:

- सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि नियुक्ति समिति में मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति से इन मामलों में कम हस्तक्षेप की संभावना होगी।

आगे की राह:

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तथा भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए टीएन शेषन जैसे क्षमता वाले मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है। हालांकि ऐसे व्यक्तित्व कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन बिना पक्षपात के नियुक्तियां इस धारणा को और मजबूत कर सकती हैं।

1 19वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नोम पेन्ह में 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष आसियान-भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है जिसे आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

आसियान के बारे में:

- एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस एक क्षेत्रीय संगठन है जो सभी सदस्य देशों को आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ लाता है। इसकी स्थापना अगस्त, 1967 में बैंकॉक (थाईलैंड) में एशिया के 5 संस्थापक देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी।
- इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से सदस्य राष्ट्रों में हस्तांतरित होती रहती है।
- इनका कुल संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर है।

वर्तमान सदस्य देश:

- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के बीच गहरे प्राचीन संबंधों, समुद्री संपर्क तथा क्रॉस-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को स्वीकार किया गया, जो आसियान-भारत संबंधों को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
- मानव संसाधन, डी-माइनिंग और विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होती है।
- भारत और आसियान देशों ने डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल व्यापार, डिजिटल कौशल तथा नवाचार, साथ ही हैकथॉन में क्षेत्रीय क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाना शामिल है।
- भविष्य हेतु लचीला और टिकाऊ खाद्य आपूर्ति विकसित करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करके स्मार्ट कृषि में सहयोग को बढ़ावा देना।
- आसियान और भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग बढ़ाकर, स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करता है। इसमें अनुसंधान और विकास व सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के क्षेत्र शामिल हैं।
- आसियान-इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (AITIGA) की समीक्षा में तेजी लाने की मांग की ताकि इससे व्यापार-सुविधा और एकीकरण को बढ़ावा मिल सके।
- वियतनाम और इंडोनेशिया में ट्रैकिंग, डेटा रिसेप्शन एण्ड प्रोसेसिंग स्टेशनों की स्थापना, अंतरिक्ष क्षेत्र में आसियान-भारत सहयोग को बढ़ाना, सहयोग के नए क्षेत्रों में आसियान और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के खिलाड़ियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना।
- आसियान और भारत ने नए संवाद मंच स्थापित करके साइबर सुरक्षा पर सहयोग को मजबूती प्रदान की है।
- भारत ने प्रभावी पर्यटन कार्ययोजनाओं के माध्यम से आसियान देशों के साथ पर्यटन और संबंधित उद्योगों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं।

आगे की राह:

भारत-आसियान संबंध भारत की एक्ट-ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है। एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा है, लेकिन यह अभी एशिया में महत्त्वपूर्ण नॉन-टैरिफ बाधाओं के कारण सीमित है। भारत निवेश की नई योजनाएं बनाकर, कौशल को उन्नत करके, परिवहन ढांचे में सुधार करके आसियान देशों से व्यापार तथा निवेश को बढ़ाकर अपने संबंधों को और मजबूत कर सकता है।

2 ड्रग-फ्री चाइल्डहुड ग्लोबल मीट

चर्चा में क्यों?

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) और वर्ल्ड फेडरेशन अगेंस्ट ड्रग्स (WFAD) के सहयोग से केरल के तिरुवनंतपुरम में 'राइट टू ए ड्रग-फ्री चाइल्डहुड' पर तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका थीम 'चिल्ड्रन मैटर- राइट टू ए ड्रग-फ्री चाइल्डहुड' था।

सम्मेलन के बारे में:

- यह उन कारणों पर प्रकाश डालता है जो बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन की ओर ले जाते हैं तथा उन नीतियों और प्रोटोकॉल पर काम करते हैं जिन्हें सरकारों द्वारा अपनाया जा सकता है।
- सत्र को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा संबोधित किया गया था जिसमें दुनिया भर से

नागरिक समाज के सदस्यों, नीति निर्माताओं, बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय तथा राज्य आयोगों के सदस्यों, सरकारी प्रतिनिधियों, पेशेवरों और युवा नेताओं की भागीदारी देखी गई थी।

आइसलैंडिक मॉडल-सम्मेलन में एक प्रमुख विषय:

- ➢ आइसलैंडिक मॉडल नशीली दवाओं के उपयोग के विकारों से प्रभावित किशोरों को सामान्य जीवन में वापस लाने में हस्तक्षेप करता है।
- ➢ यह नशे के आदी बच्चों की ऊर्जा को खेल और अन्य गतिविधियों जैसे रचनात्मक कार्यों में लगाकर उन्हें नया जीवन देने का प्रयास करता है।
- ➢ यह माता-पिता, शिक्षकों और स्पोर्ट्स क्लब जैसे हितधारकों के साथ सहयोग करके कार्य करता है।
- ➢ वर्तमान में, आइसलैंड नशामुक्त किशोरों की यूरोपीय सूची में पहले स्थान पर है।

वेंडा (No to Drugs):

- ➢ यह फोर्थ वेव फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो आइसलैंडिक मॉडल की तर्ज पर केरल में 'वैकल्पिक खोज' मॉडल की पुरजोर वकालत करती है।
- ➢ वेंडा (VENDA) के तहत प्रमुख गतिविधियों में बच्चों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम, फुटबॉल प्रशिक्षण, समर कैंप, फुटबॉल टूर्नामेंट जबकि अभिभावकों, शिक्षकों, परामर्शदाताओं, पुलिस और आबकारी अधिकारियों के लिए जागरूकता कक्षाएं शामिल हैं।
- ➢ वेन्डा उन जिलों में सक्रिय है जहां नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षण में, ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के अनुसार नशे की लत वाले किशोरों की संख्या अधिक है।

आगे की राह:

नशे की समस्या बढ़ती जा रही है जिसे हल करने के लिए, सभी सामुदायिक हितधारकों सहित दीर्घकालिक रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह वैश्विक सम्मेलन युवाओं को उनके अधिकारों, पुनर्वास और बच्चों के सामाजिक सामंजस्य की वकालत करने के लिए शिक्षित तथा सशक्त करेगा, साथ ही बच्चों के साथ काम करने में परिवार और स्कूल की भूमिका को उजागर करेगा।

3 वैश्विक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन और राज्य की भूमिका

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में तीसरे मंत्रिस्तरीय 'नो मनी फॉर टेरर' (एनएमएफटी) सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के प्रयासों और खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रकाश डालता है।

मुख्य विचार:

यह सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व को आगे बढ़ाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए भारत के ठोस प्रयासों का हिस्सा है। विशेष UNSC ब्रीफिंग (जो दिसंबर में होगी) के साथ यह 'नो मनी फॉर टेरर' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, हाल ही में गठित काउंटर टेररिज्म कमेटी (CTC) के साथ तालमेल रखने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था जिसमें 20 देशों और 78 से अधिक बहुपक्षीय संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया था।

इस सत्र में चर्चा हुई:

- ➢ आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझान पर।
- ➢ आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों के उपयोग पर।
- ➢ उभरती प्रौद्योगिकियां और आतंकवादी वित्तपोषण पर।
- ➢ आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने में चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर।

सम्मेलन का एजेंडा:

भारत ने इस तरह के मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया:

- ➢ साइबर अपराधों से संबंधित कानूनों पर सार्वभौमिक सहमति का अभाव।
- ➢ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमजोर नियंत्रण और आतंकवादी और चरमपंथी समूहों द्वारा उनका दुरुपयोग।
- ➢ डार्क वेब और क्रिप्टो-मुद्रा से संबंधित मुद्दे।
- ➢ आतंकवाद के वित्तपोषण की गुमनाम, विकेन्द्रीकृत और अप्राप्य प्रकृति के साथ-साथ क्राउडफंडिंग।
- ➢ उभरते आतंकवाद-वित्तपोषण तंत्र के खतरों की पहचान और शमन में प्रभावी बहुपक्षीय और बहु-हितधारक दृष्टिकोणों पर ध्यान।
- ➢ आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए गैर-लाभकारी और गैर-सरकारी संगठनों के फ्रंट स्ट्रक्चर के रूप में दुरुपयोग

पर विचार-विमर्श।

एनएमएफटी सम्मेलन के बारे में:

यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक सहयोगात्मक पहल है जिसे पहली बार 2018 में पेरिस में आयोजित किया गया था। इसके बाद, सम्मेलन का दूसरा संस्करण 2019 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था।

सम्मेलन का उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने पर चर्चा को आगे बढ़ाना है।
- यह आतंकवाद के वित्तपोषण के सभी पहलुओं के तकनीकी, कानूनी, नियामक और सहयोग पहलुओं पर चर्चा को भी शामिल करना चाहता है।

आगे की राह:

आतंकवादी संगठनों द्वारा दिखाई गई अनुकूलन क्षमता और अवसर अत्यधिक सटीक होते है। अच्छी तरह से जुड़ी हुई वित्तीय खुफिया जानकारी ही आतंकवादी समूहों की संरचना के साथ-साथ व्यक्तिगत आतंकवादियों की गतिविधियों को प्रकट करती है। इसके अलावा, आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक सहमति बनाने की जरूरत है और सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हितधारकों द्वारा ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

4 यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम

चर्चा में क्यों?

इण्डोनेशिया के बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 16 नवंबर, 2022 को यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के साथ भारत से साझेदारी की घोषणा की।

यूके-भारत यंग प्रोफेशनल स्कीम क्या है?

- यूके-भारत यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के तहत, 18-30 आयु वर्ग के बीच 3,000 डिग्री धारक भारतीयों प्रतिवर्ष को यूके में दो साल तक नौकरी उपलब्ध करवाएगा।
- 2023 की शुरुआत में, यह योजना पारस्परिक आधार पर संचालित होगी जहां ब्रिटिश नागरिकों को भारत में समान मौका दिया जाएगा।

यूके-भारत यंग प्रोफेशनल योजना का महत्त्व:

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लगभग सभी अन्य देशों की तुलना में, यूनाइटेड किंगडम के भारत के साथ अच्छे संबंध हैं।
- ब्रिटेन में सभी विदेशी छात्रों में से लगभग एक-चौथाई भारतीय हैं, तथा लगभग 95,000 रोजगार वहां भारतीय निवेश द्वारा उत्पन्न होता है।
- यूके सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत को भारत के साथ यूके के संबंधों और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक 'महत्त्वपूर्ण क्षण' के रूप में वर्णित किया।
- भारत इस योजना से लाभान्वित होने वाला पहला वीजा देश होगा जो यूके-भारत प्रवासन और संघटन भागीदारी समेकित करेगा जिस पर पिछले वर्ष सहमति हुई थी।

यूके-भारत संबंध:

- हालांकि साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद के बाद दोनों देशों के लिए एक समझदार रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल था। समय बदलते ही सही संबंध कमोवेश अच्छे हो रहे फिर भी 2021 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत-यूके संबंध में सुधार की गति दिखाई दे रही है।
- समझौते के तहत भारत-यूके संबंधों के लिए 2030 का रोडमैप भी स्थापित किया गया है, जो मोटे तौर पर दोनों देशों के लिए साझेदारी के लक्ष्यों को निर्धारित करता है।
- ब्रिटेन का G-7, G-20, APEC आदि का प्रमुख सदस्य होना भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के लिए आवश्यक साबित हो सकता है।
- यूके ने हाल ही में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए संयुक्त राष्ट्र में नई स्थायी सीट के निर्माण का समर्थन किया तथा स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार का आह्वान किया।
- इसके अलावा, दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले कुछ समय से चल रहे राजनीतिक उठापटक से यह विलम्ब हुआ है।

आगे की राह:

G-20 शिखर सम्मेलन में भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच चर्चा के दौरान कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई जिसमें सुरक्षा सहयोग भी शामिल था। हालांकि, यूके के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि दोनो देशों को व्यापार समझौते को साकार करने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि वह 'गति से अधिक गुणवत्ता' चाहते हैं, यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल योजना इस बात का अवलोकन हैं कि भविष्य में दोनों देशों के आपसी हितों की पूर्ति एवं वैश्विक शान्ति व सुरक्षा हेतु एक साथ कार्य कर सकते हैं जो दोनो देशों के लिए लाभकारी होगा।

5 फ्रांस ने किया ऑपरेशन बरखाने का अंत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समाप्ति के दौरान इमैनुएल मैक्रॉन ने साहेल में फ्रांसीसी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की जिसमें पैन-सहेलियन ऑपरेशन बरखाने को उसके मौजूदा स्वरूप में समाप्त करने के साथ अफ्रीका में एक दशक लंबे ऑपरेशन बरखाने को समाप्त किया गया है।

ऑपरेशन बरखाने क्या है?

- ऑपरेशन बरखाने एक विद्रोही-विरोधी ऑपरेशन था जो 1 अगस्त, 2014 को शुरू हुआ।
- फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका के साहेल में जनवरी 2013 में ऑपरेशन सर्वल लॉन्च किया। यह ऑपरेशन अल-कायदा से जुड़े इस्लामिक चरमपंथियों का मुकाबला करने तक सीमित था जिन्होंने उत्तरी माली पर नियंत्रण कर लिया है।
- 2014 में, इस ऑपरेशन सर्वल को बढ़ाकर इसका नाम बदलकर ऑपरेशन बरखाने कर दिया गया।

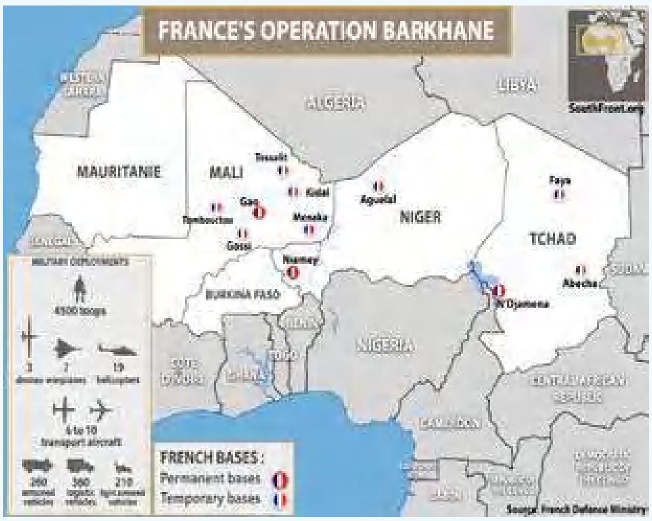

ऑपरेशन बरखाने का उद्देश्य:

- उन्नत ऑपरेशन का उद्देश्य साहेल क्षेत्र में गैर-राज्य सशस्त्र समूहों के पुनरुत्थान को रोकने में स्थानीय सशस्त्र बलों की सहायता करना था। इसका नेतृत्व फ्रांसीसी सेना ने अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में इस्लामी समूहों के खिलाफ किया था। ऑपरेशन का नेतृत्व पांच देशों के सहयोग से किया गया था, जिनमें से सभी पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हैं जो साहेल तक फैले हुए हैं। इसने माली, नाइजर, बुर्किना फासो, मॉरिटानिया और चाड में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया। इस मिशन के हिस्से के रूप में, लगभग 4,500 फ्रांसीसी कर्मियों को स्थानीय संयुक्त आतंकवाद विरोधी बल के साथ तैनात किया गया था।
- ऑपरेशन का नाम अर्धचन्द्राकार टिले के प्रकार के नाम पर रखा गया था जो सहारा रेगिस्तान में आम है।

साहेल में फ्रांसीसी सैन्य अभियान के दो लक्ष्य थे:

- उत्तर में विद्रोहियों से माली को मुक्त कराना।
- आतंकवाद विरोधी अभियानों का उपयोग करके पश्चिम अफ्रीका में प्रमुख आतंकवादियों को प्रभावहीन बनाना।

ऑपरेशन सर्वल की कुछ सफलताएं:

- 2014 में, फ्रांसीसी नेतृत्व वाली सेना चरमपंथियों से माली के उत्तरी हिस्सों को फिर से हासिल करने में सक्षम थी।
- 2020 में, इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा के दो प्रमुख नेता और अल-कायदा-संबद्ध ग्रुप डी साउथियन ए ल'इस्लाम एट ऑक्स मुसलमान को बेअसर कर दिया गया था।

ऑपरेशन सर्वल की सफलता के कारण ऑपरेशन बरखाने चलाया गया। लेकिन इस ऑपरेशन में विफलताओं की एक शृंखला देखी गई। जैसे:

- इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े नए समूहों का उदय।
- आतंकवाद से निपटने में ऑपरेशन की विफलता के कारण मानवीय संकट उत्पन्न हुआ।
- 2022 की पहली छमाही में माली, बुर्किना फासो और नाइजर में हिंसा के कारण 5,450 मौतें हुई। पिछले वर्षो की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।
- 2021 में साहेल में इस्लामी हिंसा की 2,000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई।
- क्षेत्र की उग्रवाद को हल करने में विफलता के कारण सेना के लिए नागरिक समर्थन से साहेल में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ी।
- जिहादियों का दमन करने में फ्रांसीसी सेना विफल रही।

इस ऑपरेशन का परिणाम अनिर्णायक रहा। इस ऑपरेशन के स्थान पर महत्वपूर्ण फ्रांसीसी योगदान और नेतृत्व के साथ एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन साहेल में आतंकवाद विरोधी अभियानों और सुरक्षा बल प्रशिक्षण और सहायता की जिम्मेदारी ली है।

6 फ्रांस से एआई पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभालेगा भारत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएआई पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता संभाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने फ्रांस से प्रतीकात्मक अधिग्रहण के लिए टोक्यो में जीपीएआई की बैठक में देश का प्रतिनिधित्व किया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है जिसे मनुष्यों की तरह सोचने और उनके कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यह शब्द उन सभी मशीन पर भी लागू किया जा सकता है जो सीखने और समस्या-समाधान जैसे मानव दिमाग से जुड़े लक्षण प्रदर्शित करता है।

एआई पर वैश्विक भागीदारी के बारे में:

GPAI जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहल है। GPAI अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का एक समूह है। भारत एक संस्थापक सदस्य के रूप में 2020 में GPAI में शामिल हुआ। संस्थापक सदस्य के रूप में भारत का स्थान यह भी दर्शाता है कि दुनिया, भारत को एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कैसे मानती है जिसने हमेशा नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग की वकालत की है।

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ने की उम्मीद है। 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भी योगदान देने की भी उम्मीद है, जो देश के 5 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी लक्ष्य का 10 प्रतिशत है।

आगे की राह:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी बदलाव के लिए जिम्मेदार रहा है। यह प्रक्रिया सरलीकरण और स्वचालन के माध्यम से उत्पादकता में काफी सुधार कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी उद्योग 4.0 के मूलभूत आधारों में से एक है। नीति आयोग ने 2018 में एआई रणनीति को पेश किया और समावेश और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के बारे में बात करने वाले अग्रणी देशों में से एक बन गया। सभी प्रासंगिक क्षेत्रों और मूल्य शृंखलाओं में एआई को अपनाने में तेजी लाने की आवश्यकता है। एआई का भविष्य शोधकर्ताओं, निजी संगठनों और नागरिकों जैसे विभिन्न हितधारकों के समूह की आवश्यकता द्वारा तय किया जाएगा।

7 कनाडा की हिन्द-प्रशांत रणनीति

चर्चा में क्यों?

कनाडा ने क्षेत्र में सैन्य और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की रूपरेखा तैयार करते हुए अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित इंडो-पैसिफिक रणनीति शुरू की है।

रणनीति के बारे में:

- रणनीति ने जलवायु परिवर्तन और व्यापार के मुद्दों पर उसके साथ काम करते हुए चीन से निपटने को लेकर बनायीं गयी है। रणनीति के अनुसार कनाडा बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए विदेशी निवेश नियमों को कड़ा करेगा और चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति बंद करने से रोकेगा। रणनीति कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और जलवायु के साथ-साथ इसके आर्थिक लक्ष्यों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- रणनीति पांच परस्पर जुड़े रणनीतिक उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करती है:
  - शांति, लचीलापन और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
  - व्यापार, निवेश और आपूर्ति शृंखला के लचीलेपन का विस्तार।
  - निवेश करें और लोगों को जोड़ना।
  - टिकाऊ और हरित भविष्य का निर्माण।

» कनाडा भारत-प्रशांत के लिए एक सक्रिय और घनिष्ठ भागीदार के रूप में।

भारत रणनीति में कहां है?

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत का बढ़ता रणनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय महत्व इसे इस रणनीति के तहत कनाडा के अपने उद्देश्यों की खोज में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बनाता है। कनाडा और भारत में लोकतंत्र और बहुलवाद की एक साझा परंपरा है, एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और बहुपक्षवाद के लिए एक आम प्रतिबद्धता, हमारे वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार में पारस्परिक हित और व्यापक और बढ़ते लोगों से लोगों के बीच संबंध हैं।

रणनीति के अनुसार-भारत के साथ सहयोगी पक्ष:

- गहरे व्यापार और निवेश के साथ-साथ लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर सहयोग सहित आर्थिक संबंधों को बढ़ाएगा।
- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की दिशा में एक कदम के रूप में अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट (ईपीटीए) पर हस्ताक्षर करके कनाडा, बाजार तक पहुंच का विस्तार करना चाहता हैं।
- भारतीय बाजार में भारतीय व्यवसायों के साथ भागीदारी करने वालों के लिए ईपीटीए के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापार आयुक्त सेवा के भीतर एक कनाडा-भारत डेस्क बनाया जाएगा।
- रणनीति के तहत नई दिल्ली और चंडीगढ़ में कनाडा की वीजा-प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर, निवेश करना और लोगों को जोड़ना शामिल है।
- रणनीति के तहत अकादमिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, युवा और अनुसंधान आदान-प्रदान का समर्थन करना भी शामिल है।
- रणनीति के तहत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में, पर्यावरण की रक्षा में और हरित प्रौद्योगिकियों को लागू करने में सहयोग में तेजी लाना।
- नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे आपसी हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टीम कनाडा के उन्नत व्यापार मिशन भेजना।

आगे की राह:

कनाडा की इंडो-पैसिफिक रणनीति यह सुनिश्चित करेगी कि कनाडा इंडो पसिफिक में सक्रिय भूमिका निभाए। कनाडा इंडो-पैसिफिक भविष्य के क्षितिज को साझा समृद्धि के स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ देख रहा है जो कनाडाई और पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

ध्येयIAS® most trusted since 2003
NEW BATCH - FACE TO FACE
GENERAL STUDIES
PREMIUM BATCH
हिंदी माध्यम
19 DECEMBER 11:30 AM
ENGLISH MEDIUM
19 DECEMBER 5:30 PM
SP MARG, CIVIL LINES, PRAYAGRAJ 0532-2260189, 8853467068

1 रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पनामा में हुए CITES (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीशीज) के 19वें सम्मेलन में भारत ने मीठे पानी के सरीसृप प्रजाति रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल को बेहतर ढंग से संरक्षित करने का प्रस्ताव रख इसे परिशिष्ट-I (उन प्रजातियों के लिए है जो गंभीर रूप से खतरे में हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं) में स्थानांतरित करने की बात की है। इस सम्मेलन में जानवरों और पौधों की लगभग छह सौ प्रजातियों के लिए सख्त व्यापार नियमों पर विचार किया जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विलुप्त होने के बढ़ते खतरे के अधीन हैं।

रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल:

लाल-मुकुट की छत वाला कछुआ या बंगाल की छत वाला कछुआ मीठे पानी के कछुओं की एक प्रजाति है जो दक्षिण एशिया में पाई जाती है। यह अपने पूर्व जीनस कचुगा प्रकार की प्रजाति थी। मादाएं 56 सेमी (22 इंच) की खोल लंबाई तक बढ़ सकती हैं और 25 किलोग्राम (55 पौंड) वजन कर सकती हैं, लेकिन नर काफी छोटे होते हैं। कछुए जमीन पर धूप सेकना पसंद करते हैं। प्रजनन के मौसम में, नर कछुओं के सिर और गर्दन चमकीले लाल, पीले और नीले रंग के दिखाई देते हैं। मादाएं घोंसलों की खुदाई करती हैं जिसमें वे तीस तक अंडे दे सकती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बटागुर कचुगा है।

सुरक्षा को खतरा:

वैश्विक एनजीओ TRAFFIC द्वारा एक अध्ययन में पाया कि 2009-2019 से भारत में लगभग 11,000 कछुओं और मीठे पानी के कछुओं को जब्त किया गया है।

- उत्तरी भारत और बांग्लादेश के गंगा तराई क्षेत्रों में प्रदूषण और जलविद्युत परियोजनाओं के कारण निवास स्थान के नुकसान के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है।
- यह अवैध खपत और अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी खतरों का सामना कर रहा है।
- यह प्रमुख हाइड्रोलॉजिकल परियोजनाओं और नदी के प्रवाह की गतिशीलता और घोंसले के शिकार समुद्र तटों और जल प्रदूषण पर उनके प्रभावों के लिए अतिसंवेदनशील है।
- इन कछुओं को मांस और खोल के लिए काटने, मछली पकड़ने के जाल में डूबने, जल प्रदूषण और अन्य चुनौतियों के कारण भी इनकी मौत हुई।
- रेत खनन और गंगा नदी के किनारे मौसमी फसलें उगाने से नदी के किनारे बालू-पट्टी प्रमुख रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिनका उपयोग प्रजातियों द्वारा घोंसले के लिए किया जाता है।

सुरक्षा हेतु किए गए उपाय:

- यह पहले से ही प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत है।
- यह सीआईटीईएस परिशिष्ट-II में शामिल है
- यह 1972 के भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (संशोधित) की अनुसूची-I के तहत संरक्षित है।
- प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इस कछुए को 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' होने का दर्जा दिया है। भारत ने संरक्षण के उपाय किए हैं, और एक बंदी प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

2 चरम जलवायु अब एक सामान्य प्रक्रिया

चर्चा में क्यों?

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नई रिपोर्ट, जो भारत में जलवायु परिवर्तन पर देखरेख करती है, ने 1 जनवरी से 30 सितंबर, 2022 तक 273 दिनों में से 241 दिन चरम मौसम की घटनाओं को दर्ज किया है।

विषम जलवायु के बारे में:

- भारत ने इस वर्ष अत्यधिक गर्मी, बाढ़ और वर्षा का सामना किया। विशेषज्ञों के अनुसार आर्थिक नुकसान और खाद्य असुरक्षा को रोकने के उद्देश्य से जलवायु अनुकूलन हेतु अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। विषम मौसम की घटनाएं जून-सितंबर के बीच, दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि में व्यापक थीं। इस दौरान, अधिकांश राज्यों ने दो चरम घटनाओं का अनुभव किया। बिजली गिरना और भारी बारिश तथा बाढ़ और भूस्खलन का। इस वर्ष जनवरी में, मध्य भारत में वर्षा 1981-2010 की अवधि में औसत वर्षा से 203% अधिक रही, वहीं मार्च में, उत्तर पश्चिम भारत में 1981-2010 की अवधि में तापमान, औसत तापमान से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मई के महीने में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे भारत में किसी भी महीने के लिए सबसे अधिक है।

संभावित कारण:

- कई अध्ययनों से पाया गया है कि मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर में गर्मी की लहरों की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि की है। हाल के वर्षों में, भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों

में गर्मी की लहरों की आवृत्ति बढ़ी है, जिससे अधिक गर्मी के साथ अत्यधिक गर्मी जैसे जोखिम बढ़े हैं।

- बाढ़ प्राकृतिक और मानव-संबंधी दोनों कारकों से शुरू होती है। प्रमुख प्राकृतिक कारक, जिनमें अधिक या लंबे समय तक वर्षा होना, आंधी और तूफान आना शामिल हैं। इनसे शहरों और तटीय क्षेत्रों में भीषण बाढ़ का कारण बनते हैं। मानव-प्रेरित कारको में वार्मिंग से मौसम प्रभावित होता है जिससे भारी बारिश होती है और समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण अधिक व्यापक तूफान बढ़ रहा है।

आगे की राह:

बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ विषम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में और वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत पहले ही अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 5 प्रतिशत हानि कर रहा है और यह संख्या 10% तक बढ़ सकती है। यदि वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित नहीं होती है। यद्यपि पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार, बचाव तथा राहत प्रदान करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है फिर भी भारत को अनुकूलन और लचीलापन में और अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी। जलवायु प्रभावों के प्रबंधन में राष्ट्र को वैश्विक समर्थन की आवश्यकता है। भारत की लगभग 80% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जो गंभीर बाढ़ या गर्मी की लहरों जैसी अत्यधिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। बाढ़ और चक्रवात के लिए भारत की परिष्कृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के बावजूद, एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी में सुधार की आवश्यकता है जिसे और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए।

3 भारत के भूजल संसाधन

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 के लिए भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन जारी किया। भूजल गहरे जलभृतों, पारगम्य चट्टानों और अवसादों में संग्रहित होता है तथा पंपिंग कुओं का उपयोग करके निकाला जाता है। अक्सर जलभृत नवीकरणीय जल संसाधन होते हैं, जो धीरे-धीरे सैकड़ों से लेकर कई हजारों वर्षों तक वर्षा के पानी से भरे होते हैं।

रिपोर्ट में रेखांकित मुद्दे:

1. परीक्षण से एकत्र की गई जानकारी का एक विस्तृत विश्लेषण भूजल पुनर्भरण में वृद्धि को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से नहर से पुनर्भरण में वृद्धि, सिंचाई के पानी के वापसी प्रवाह तथा जल निकायों/टैंकों और जल संरक्षण संरचनाओं से पुनर्भरण के कारण हो सकता है। यह विश्लेषण 2017 के आकलन डेटा की तुलना में देश में 909 मूल्यांकन इकाइयों में भूजल की स्थिति में सुधार का संकेत देता है। इसके अलावा, अधिक निष्कार्षित इकाइयों की संख्या में समग्र कमी और भूजल निष्कर्षण स्तर के चरण में भी कमी देखी गई है।
2. संग्रहण योग्य भूजल संसाधनों का मुख्य स्रोत वर्षा से पुनर्भरण है, जो कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का लगभग 61% योगदान देता है। उच्च स्थानिक भिन्नता के साथ, भारत में औसतन लगभग 119 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। देश के एक बड़े हिस्से में तमिलनाडु को छोड़कर मुख्य रूप से जून से सितंबर के महीनों में दक्षिण-पश्चिम (एसडब्ल्यू) मानसून के दौरान वर्षा होती है। जहां अक्टूबर से दिसंबर तक पूर्वोत्तर मानसून का प्रमुख योगदान है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य भी हैं जो सभी मौसमों में महत्त्वपूर्ण वर्षा प्राप्त करते हैं।
3. वर्तमान मूल्यांकन में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मापा गया है। कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण (2022 तक) 239.16 बीसीएम के रूप में आंका गया है। पूरे देश में भूजल निष्कर्षण का औसत चरण लगभग 60.08% है।
4. शैल संरचनाओं के प्रकार, उनके भंडारण और संचरण विशेषताओं का भूजल पुनर्भरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलोढ़ संरचनाओं जैसे झरझरा संरचनाओं में आमतौर पर उच्च विशिष्ट पैदावार होती है जो भूजल के अच्छे भंडार होते हैं। दूसरी ओर, देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई हिस्से में व्याप्त विखंडित संरचनाओं में भूजल की उपस्थिति ज्यादातर अपक्षयित, संयुक्त और चट्टानों के खंडित भागों तक सीमित है। यह भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए किसी भी रणनीति में निम्नलिखित का संयोजन शामिल हो आवश्यक है:
   - उपलब्धता के आधार पर भूजल के निष्कर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से आपूर्ति पक्ष के उपाय।
   - उपलब्ध संसाधनों को नियंत्रित करने और संरक्षित करने के उद्देश्य से मांग-पक्ष के उपाय।

आगे की राह:

भारतीय संदर्भ में भूजल संसाधनों का प्रबंधन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है क्योंकि यह मानव समाज और भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं से संबंधित है। भूजल उपलब्धता और इसके उपयोग का अत्यधिक असमान वितरण दर्शाता है कि समग्र रूप से देश के लिए कोई एकल प्रबंधन रणनीति नहीं अपनाई जा सकती है। अत: एक सतत व सुगम व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने की आवश्यकता है ताकि बेहतर परिणाम मिल सके।

4 आक्रामक पौधे-भारत के प्राकृतिक और कृषि के लिए खतरा

चर्चा में क्यों?

इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, रांची की एक टीम ने दो आक्रामक पौधों की प्रजातियों क्रोमोलाएना और लैंटाना कैमरा के फैलाव की गतिशीलता का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने जांच करने के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया और पाया की ये पौधे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित नहीं होंगे।

आक्रामक पौधे क्या हैं?

वे पौधे जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं बल्कि उस क्षेत्र में उन्हें पेश किया गया है जहां वे फैलते हैं और इन नए आवासों में कई नकारात्मक प्रभाव (जैसे मूल जैव विविधता को प्रभावित करना, आर्थिक और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना) का कारण बनते हैं, आक्रामक पौधे कहलाते हैं। इसे 'घुसपैठी जाति' भी कह सकते हैं।

आक्रामक पौधे कहाँ से आते हैं?

- कई बार ये सजावटी, फूलों की खेती या कृषि उपयोग के लिए जान-बूझकर पेश किए गए जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय अमेरिकी झाड़ी लैंटाना कैमारा को भारत में 19वीं शताब्दी में सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था लेकिन अब यह स्क्रबलैंड्स और जंगलों सहित विविध स्थलीय आवासों पर आक्रमण करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार के माध्यम से नए क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं।
- बीज या पौधे के टुकड़े कपड़ों से जुड़कर या गलती से माल के आयात के साथ आ सकते है। पार्थेनियम ने 1956 में यूएसए से गेहूं के आयात के माध्यम से भारत में अपना रास्ता बनाया था।

आक्रामक पौधे कैसे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं?

जैव विविधता जटिल रूप से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और मानव कल्याण से जुड़ी हुई है। विश्व स्तर पर, जैव विविधता भोजन का उत्पादन करने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती है

- वे देशी पौधों के आवासों पर कब्जा कर सकते हैं, सफलतापूर्वक इन मूल निवासियों को भीड़ से बाहर कर सकते हैं।
- कुछ देशी पेड़ पौधों के विकास को उनके एलोपैथिक गुणों और कवक के साथ भूमिगत पारस्परिकता को बाधित करके दबा सकते हैं।
- कुछ आक्रमणकारी जंगल की आग और मिट्टी के कटाव के जोखिम को भी बढ़ाते हैं।
- भारत में पार्थेनियम पशुधन के लिए विषाक्त हैं। खरपतवार सांस और त्वचा रोगों को बढ़ाकर मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।
- आक्रमणकारी कृषि और चरागाह भूमि पर आक्रमण करके भारी आर्थिक नुकसान भी पहुँचाते हैं।
- वन विविधता में बाधा डालने के अलावा, वैश्विक कृषि उत्पादकता को कम करता है।

भारत के कुछ सबसे कुख्यात आक्रमणकारियों में लैंटाना, पार्थेनियम, सियाम वीड, मैक्सिकन डेविल, जल कुंभी और मेसकाइट शामिल हैं। भारत को दुनिया में सबसे अधिक आक्रामक वनस्पति वाले क्षेत्रों में माना जाता है। यहां 200 से अधिक आक्रामक प्रजातियां हैं।

आक्रामक पौधों को नियंत्रित करने के उपाय:

- काटना, जलाना और उखाड़ना।
- जलकुंभी-अस्थायी रूप से जलाशयों को साफ करने के लिए यांत्रिक निष्कासन का उपयोग।
- मैक्सिकन भृंग का जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयोग।
- स्थायी प्रबंधन के लिए एक एकीकृत ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च की आवश्यकता पर बल।
- IAPS प्रसार की मैपिंग और निगरानी करके भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के साथ उनके जुड़ाव के माध्यम से प्रबंधन

को मजबूत किया जा सकता है।

आगे की राह:

जैविक आक्रमण को वैश्विक स्थिरता के लिए बढ़ते खतरे के रूप में पहचाना गया है। इससे संबंधित समस्याओं के बारे में कृषकों, बागवानों और पौध नर्सरी मालिकों के बीच जागरूकता बढ़ाकर इसके प्रसार को कम किया जा सकता है। देशी प्रजातियों के साथ आक्रामकों को बदल कर, बाहरी सैर के बाद पालतू जानवरों की सफाई करने से बीजों को उनके फर से फैलने से रोका जा सकता है। किसी नए स्थान पर जाने से पहले अपने

5 कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को तमिलनाडु के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गयी। यह मान्यता वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 26ए(1)(बी) के तहत की गई है। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य को पड़ोसी कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ेगा।

कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य:

- तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य के रूप में कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र घोषित किया है। 686.406 वर्ग किमी के विस्तार का यह अभयारण्य जंगलों से सटे एक संरक्षित परिदृश्य का हिस्सा होगा जो वर्तमान में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य का गठन करता है। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक साझा क्षेत्र है।
- यह 35 स्तनपायी प्रजातियों और 238 पक्षी प्रजातियों का घर है। यहां लीथ के नरम खोल वाले कछुए, चिकनी लेपित ऊदबिलाव, मार्श मगरमच्छ और चार सींग वाले मृग आदि पाए जाते है। घड़ियाल विशाल गिलहरियाँ और लेसर फिश ईगल भी यहां होते हैं जो विशेष रूप से कावेरी नदी और वन नदी प्रणाली पर निर्भर हैं।

कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य को पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है।
- यह कावेरी नदी बेसिन में वन्यजीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा, सन्निहित नेटवर्क बनाता है।
- यह मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और इरोड फॉरेस्ट डिवीजन के माध्यम से नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व को निरंतरता प्रदान करता है।
- यह अभयारण्य हाथियों का एक महत्वपूर्ण आवास है। यह दो हाथी गलियारों की मेजबानी करता है नंदीमंगलम-उलीबांडा गलियारा और कोवाइपल्लम-अनेबिद्दाहल्ला गलियारा।
- कावेरी नदी पर निर्भर रहने वाली नदी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कावेरी बेसिन का पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण महत्वपूर्ण है।
- भूरे रंग की विशाल गिलहरी, चार सींग वाला मृग, और लेसर फिश ईगल विशेष रूप से कावेरी नदी और वन पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर हैं। यह अभयारण्य इन विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करेगा।
- नए अभयारण्य का वन क्षेत्र शिकार के आधार का हिस्सा हैं और यह क्षेत्र बाघों के अनुकूल क्षेत्र है। यहां तेंदुए और अन्य लाल-सूचीबद्ध बड़े मांसाहारियों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस क्षेत्र में संरक्षण के प्रयास आवास की सुरक्षा और बहाली, मिट्टी के कटाव को कम करने और डाउनस्ट्रीम स्टेनली जलाशय की गाद को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। टीएन ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के मिशनों के साथ यह महत्त्वपूर्ण कदम राज्य की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

6 भारत COP-27 जलवायु के लिए मैंग्रोव एलायंस में शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत मिस्र के शर्म अल-शेख में पार्टियों के सम्मेलन (COP-27) के 27वें सत्र में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) में शामिल हुआ है। अपने कार्बन सिंक को बढ़ाने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप यह कदम, नई दिल्ली को श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य देशों के साथ क्षेत्र में मैंग्रोव वनों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए सहयोग करेगा। गठबंधन में शामिल होने के बाद भारत ने कार्बन पृथक्करण के लिए वनों की कटाई और वन क्षरण (REDD) कार्यक्रमों से उत्सर्जन को कम करने के साथ मैंग्रोव संरक्षण के एकीकरण का आह्वान किया।

यह कदम 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुरूप है।

जलवायु के लिए मैंग्रोव एलायंस क्या है?

- मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) एक अंतर-सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। इसके सदस्यों में संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल हैं।
- यह गठबंधन जलवायु परिवर्तन के प्रकृति-आधारित समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। यह दुनिया भर में मैंग्रोव वनों के पुनर्वास की गारंटी देता है।

भारत में मैंग्रोव:

- भारत दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर का लगभग आधा योगदान देता है। वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, देश का मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15 प्रतिशत है। 2019 के बाद से, कवरेज में केवल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

मैंग्रोव का महत्त्व:

- मैंग्रोव छोटे पेड़ और झाड़ियाँ हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं, खारे पानी में पनपते हैं, और भूमि और समुद्र के किनारे अनोखे जंगल बनाते हैं। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में अन्तर-ज्वारीय जल में रहने वाले पेड़ों और झाड़ियों से युक्त-विविध समुद्री जीवन का प्रतिनिधत्व करते हैं। वे एक समृद्ध खाद्य वेब का भी समर्थन करते हैं।
- मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से हैं।
- ये महत्त्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सह-लाभ प्रदान करते हैं क्योंकि वे स्थलीय वर्षा वनों की तुलना में 400 प्रतिशत तेजी से कार्बन का भंडारण करने में सक्षम हैं।
- ये तटीय क्षेत्रों को समुद्र के स्तर में वृद्धि, कटाव, सुनामी और तूफान के बढ़ने से बचाते हैं।
- ये समुद्री जैव विविधता के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं।
- दुनिया की लगभग 80 प्रतिशत मछली आबादी अपने अस्तित्व के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर करती है।
- मोलस्क और शैवाल से भरे सब्सट्रेट छोटी मछलियों, मिट्टी के केकड़ों और झींगों के लिए प्रजनन भूमि के रूप में कार्य करते हैं और स्थानीय कारीगर मछुआरों को आजीविका प्रदान करते हैं।

आगे की राह:

मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता पर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने और शिक्षित करने का प्रयास कर सकता है। एमएसी से माध्यम से वातावरण में बढ़ती जीएचजी एकाग्रता को कम किया जा सकता है।

7 एशिया रिपोर्ट 2021 में जलवायु की स्थिति

चर्चा में क्यों?

एशिया रिपोर्ट 2021 जलवायु की स्थिति, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) व संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया तथा प्रशांत द्वारा (ESCAP) संयुक्त रूप से तैयार की गई। रिपोर्ट को मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन वार्ता COP-27 में प्रस्तुत किया गया। 14 नवंबर, 2022 को जारी इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में, एशिया में कम से कम 48.3 मिलियन लोग 100 से अधिक प्राकृतिक खतरों से प्रभावित हुए। इन घटनाओं में सूखा, अत्यधिक तापमान, बाढ़, हिमनदी झील का फटना, भूस्खलन, तूफान और जंगल की आग शामिल हैं।

रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

रिपोर्ट 2021 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लगातार बढ़ते मानव, वित्तीय और पर्यावरणीय टोल को कम कर रहे हैं, खाद्य असुरक्षा और गरीबी को बढ़ा रहे हैं और सतत विकास को रोक रहे हैं।

- चीन और भारत सहित एशियाई देशों में बाढ़ को सबसे महंगी आपदा माना गया है। बाढ़ के कारण चीन को 18.4 बिलियन डॉलर, भारत को 3.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण सबसे अधिक मौतें और आर्थिक क्षति हुई।
- 2001-2020 के औसत की तुलना में भूस्खलन के कारण होने वाले नुकसान में 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इस अवधि में सूखे से होने वाले नुकसान में 63 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सूखे ने इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को प्रभावित किया।

- तूफान के कारण भारत को 4.4 बिलियन डॉलर का, चीन को 3 बिलियन डॉलर और जापान को 2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
- रिपोर्ट भविष्य में जल संकट के लिए एक चिंताजनक परिदृश्य दर्शाती है। उच्च पर्वतीय एशिया, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर बर्फ की सबसे बड़ी मात्रा है। ग्लेशियर के पीछे हटने की दर तेज हो रही है। 2021 में असाधारण रूप से गर्म और शुष्क परिस्थितियों के परिणामस्वरूप कई ग्लेशियरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है।
- 2021 में एशिया में औसत तापमान 1981-2010 की अवधि के औसत से लगभग 0.86 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक लागत नेपाल के लिए अनुमानित है, उसके बाद कंबोडिया और फिर भारत।
- डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट ने जलवायु के प्रति संवेदनशील एशियाई महाद्वीप की ओर से नुकसान और क्षति पर महत्त्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। यह जलवायु संकेतकों और एसडीजी के बीच के अंतर्संबंधों को दर्शाती है।

आगे की राह:

प्राकृतिक खतरों से निपटने के लिए बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणालियों और जलवायु पूर्वानुमानों के विकास को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता है। जलवायु संकट, खाद्य असुरक्षा और बढ़ती गरीबी सतत विकास की दिशा में दुनिया की प्रगति के लिए बड़ी बाधाएं पैदा कर रही है। अधिकांश एशियाई देशों ने जलवायु कार्रवाई योजनाओं में अनुकूलन को प्राथमिकता दी है। पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना अग्रिम कार्रवाई करने, तैयारियों को बढ़ाने और इन खतरों के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ध्येयIAS® most trusted since 2003
NEW BATCH - FACE TO FACE
GENERAL STUDIES
for PCS
Bilingual
16th DECEMBER
8 AM & 6 PM
for IAS
Hindi & English Medium
2nd JANUARY
8 AM & 5:30 PM
CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5
Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow , UP
7234000501 / 02

1 भारतीय सेना एलएसी पर 3डी-प्रिंटेड बंकर बनाएगी

चर्चा में क्यों?

भारतीय सेना लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ सीमा की रक्षा करने वाले अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए मॉड्यूलर, 3डी-प्रिंटेड अगली पीढ़ी के बंकरों का निर्माण करेगी।

महत्त्वपूर्ण जानकारी:

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ अग्रिम स्थानों पर गोला-बारूद के भंडारण हेतु भूमिगत सुविधाएं भी सृजित की जाएंगी।
- इससे चीन के साथ सीमा गतिरोध की स्थिति में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने हेतु व्यापक बुनियादी ढांचे के रूप में नई सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण होगा।
- गांधीनगर और मद्रास के आईआईटी के साथ साझेदारी में सेना द्वारा मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं।
- बंकर बनाने के लिए 3डी-प्रिंटेड को लद्दाख ले जाया जाएगा जिससे समय और परिवहन लागत की बचत होगी।

3डी-प्रिंटिंग के बारे में:

- 3डी-प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीएडी (कंप्यूटर एडेड डिजाइन) फाइल से त्रि-आयामी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।
- यह एक योगात्मक प्रक्रिया है जहां सामग्री की लगातार परतों को बिछाकर वस्तु बनाई जाती है। प्रत्येक परत में वस्तु के पतले कटा हुआ क्रॉस-सेक्शन होता है।
- आमतौर पर, 3डी-प्रिंटिंग में प्रयुक्त सामग्री प्लास्टिक या धातु की होती है। सेना द्वारा शुरू की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं के लिए एक विशेष प्रकार के कंक्रीट का उपयोग किया जाता है।
- चीन, रूस और अमेरिका ने 3डी-प्रिंटेड संरचनाओं के साथ ऐसी परियोजनाओं को पहले ही पूरा कर लिया है।

3डी-प्रिंटिंग अवसंरचना का उपयोग करने के लाभ:

- 3डी-प्रिंटेड संरचनाएं डिजाइन के अधिक लचीलेपन और पूर्णता में वेग की अनुमति देती हैं।
- यह संभावित रूप से समग्र निर्माण लागत को कम करता है जिससे संबंधित कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है।
- यह एक ही समय में श्रम उत्पादकता में वृद्धि करते हुए पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों के उपयोग की अनुमति देता है।
- यह आसानी से उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां स्थितियां प्रतिकूल हैं।

3डी-प्रिंटिंग बंकरों की विशेषताएं:

- इस परियोजना के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, त्वरित सुखाने वाले कंक्रीट और मिश्रण का रूप होता है।
- बनाए गए बंकर बहुत मजबूत होते हैं जो टी-90 टैंक से सीधी टक्कर झेल सकेंगे।
- सेना सैनिकों के रहने हेतु आश्रय स्थल बनाने के लिए 3डी-प्रिंटिंग पद्धति का उपयोग कर रही है। पूर्वी सेक्टर में चार ऐसे दो मंजिला शेल्टर बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 64 सैनिकों को रखने की क्षमता है।

आगे की राह:

सशस्त्र बलों द्वारा तैनात 3डी-प्रिंटिंग संरचनाएं देश की सुरक्षा को धार देती हैं जिसे अनुसंधान तथा एक ऐसे वातावरण के संबंध में सरकार और निजी खिलाड़ियों से एक मजबूत समर्थन की आवश्यकता है जो उद्योग के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाने के लिए अनुकूल हो।

2 आर्टेमिस-I मिशन

चर्चा में क्यों?

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने आर्टेमिस-I नामक मानव रहित चंद्रमा मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

आर्टेमिस-I मिशन के बारे में:

- आर्टेमिस-I नासा का एक मानवरहित मिशन है जिसकी शुरुआत नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल के परीक्षण से हुई। आने वाले दशकों में चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति बनाने के लिए तेजी से जटिल मिशनों की श्रृंखला में आर्टेमिस-I पहला मिशन है। आर्टेमिस-I के लिए प्राथमिक लक्ष्य अंतरिक्ष यान के वातावरण में ओरियन के सिस्टम को प्रदर्शित करना है और आर्टेमिस-II पर चालक दल के साथ पहली उड़ान से पहले एक सुरक्षित पुनः प्रवेश, वंश (Descent), स्प्लैशडाउन और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना है। आर्टेमिस-I मिशन के सबसे महत्त्वपूर्ण चरणों में से एक ओरियन मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसने 38,000 किमी/घंटा या ध्वनि की गति से 32 गुना अधिक गति से ग्रह के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और इसके नीचे की शील्ड 3,000 सेल्सियस तक तापमान सहने की क्षमता का भी परीक्षण हुआ।

आर्टेमिस-I मिशन का महत्त्व:

- आर्टेमिस-I उस नए अंतरिक्ष युग में पहला कदम है जो इंसानों को नई दुनिया में ले जाने, उतरने और दूसरे ग्रहों पर रहने के वादे को पूरा करने के लिए है।
- क्यूबसैट (आर्टेमिस-I मिशन का पार्ट) विशिष्ट जांच प्रयोगों के लिए उपकरणों से लैस है, जिसमें सभी रूपों में पानी की खोज तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन शामिल है।
- इसमें जैविक प्रयोग किए गए हैं, और मनुष्यों पर अंतरिक्ष के वातावरण के प्रभाव की जांच, ओरियन पर डमी 'यात्रियों' के प्रभाव के माध्यम से की जाएगी।

आगामी आर्टेमिस मिशन क्या हैं?

आर्टेमिस-II:

- यह मिशन 2024 में उड़ान भरेगा। आर्टेमिस-II में नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान में एक चालक दल होगा। यह पुष्टि करने के लिए एक परीक्षण मिशन होगा कि अंतरिक्ष यान की सभी प्रणालियां उसी तरह से संचालित होंगी जिस तरह से मनुष्य उसमें सवार हैं।
- लेकिन आर्टेमिस -I का प्रक्षेपण आर्टेमिस-I के समान होगा। चार अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल ओरियन पर सवार होगा और चंद्रमा की दिशा में जाने से पहले ICPS पृथ्वी की दो बार परिक्रमा करेगा।

आर्टेमिस-III:

- यह 2025 के लिए निर्धारित है और अपोलो मिशन के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने की उम्मीद है।

भारत में चंद्र मिशन:

- चन्द्र पर रिसर्च के मामले में भारत भी पीछे नहीं है। चंद्रयान-1 परियोजना के तहत भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसे अक्टूबर 2008 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन था जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल थे। रोवर प्रज्ञान को विक्रम लैंडर के अंदर रखा गया। हालांकि, मिशन पूरी तरह सफल नहीं रहा क्योंकि यह चंद्रमा पर लैंडर और रोवर उतारने में विफल रहा। फिर भी, इसरो ने हाल ही में भारत के तीसरे चंद्र अभियान चंद्रयान-3 की घोषणा की, जो चंद्रयान-2 की निरंतरता होगी जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा।

3 लार आधारित गर्भावस्था परीक्षण किट

चर्चा में क्यों?

जेरूसलम स्थित स्टार्टअप द्वारा विकसित दुनिया का पहला लार-आधारित गर्भावस्था परीक्षण किट जल्द ही इजराइल, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात में फार्मेसियों और अन्य खुदरा स्टोरों पर उपलब्ध होगा। लार, मुंह में एक पानी जैसा स्राव होता है जो लार ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। लार जीभ तथा दांतों सहित मुंह को नम और साफ करने का काम भी करती है। इसमें एंजाइम भी होते हैं जो पाचन प्रक्रिया शुरू करते हैं। सैलिग्नोस्टिक्स, एक इजराइली बायोटेक कंपनी है, जिसने COVID-19 परीक्षण किट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के आधार पर गर्भावस्था परीक्षण विकसित किया है।

लार आधारित गर्भावस्था परीक्षण की प्रक्रिया:

- लार परीक्षण भी उतना ही सरल है जितना पारंपरिक गर्भावस्था परीक्षण। इसमें कुछ सेकंड के लिए परीक्षण किट का एक हिस्सा अपने मुंह में डालते हैं, जो कंपनी के अनुसार 10 मिनट से कम समय में परिणाम देता है। कई यूरिन आधारित परीक्षणों की तरह, गर्भावस्था के लिए उत्तरदायी हार्मोन β-hCG (ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन) की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, सैलिग्नॉस्टिक्स लार परीक्षण द्वारा मिस्ड पीरियड के पहले दिन लिया जा सकता है।

गर्भावस्था के दौरान हार्मोन की भूमिका:

मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन (एचसीजी):

- यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान ही बनता है। यह लगभग विशेष रूप से प्लेसेंटा में बनता है। पहली तिमाही के दौरान मां के रक्त और यूरिन में पाए जाने वाले एचसीजी हार्मोन का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। वे अक्सर गर्भावस्था से जुड़ी मिचली (Nausea) और उल्टी में एक भूमिका निभाते हैं।

ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन (एचपीएल):

- इस हार्मोन को ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमैमोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लेसेंटा द्वारा बनाया जाता है जो भ्रूण को पोषण देता है। यह स्तनपान के लिए स्तनों में दूध ग्रंथियों के लिए उत्तरदायी होता है।

एस्ट्रोजन:

- हार्मोन का यह समूह महिला यौन लक्षणों के विकास में मदद करता है जो आमतौर पर अंडाशय में बनता है। यह गर्भ के दौरान स्वस्थ गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करने के लिए प्लेसेंटा द्वारा भी बनाया जाता है।

प्रोजेस्टेरोन:

- यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान अंडाशय और प्लेसेंटा द्वारा बनाया

जाता है। यह एक निषेचित अंडे के आरोपण के लिए गर्भाशय की परत को मोटा करने के लिए उत्तरदायी होता है।

आगे की राह:

विभिन्न चिकित्सीय जांच के लिए लार एक अच्छा माध्यम है। यह हार्मोन, वायरस तथा यहां तक कि बीमारियों का पता लगाने का एकमात्र आसान और स्वच्छ साधन है। लार आधारित यह किट गर्भावस्था के परीक्षण के दौरान रक्त और यूरिन के नमूनों की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा सकता है।

4 व्यक्तिगत कोशिका 'संपादन' का कैंसर के इलाज हेतु प्रयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) में पीएसीटी फार्मा के वैज्ञानिकों ने विशिष्ट नवजातजनों के लिए, कैंसर रोगियों से कई टी सेल रिसेप्टर्स (टीसीआर) को अलग करने के लिए एक विधि विकसित की है जिसने गैर-वायरल सीआरआईएसपीआर संपादन दृष्टिकोण का उपयोग किया है।

वैज्ञानिकों ने पहली बार इस CRISPR तकनीक का इस्तेमाल जीन डालने के लिए किया है जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने की अनुमति देता है जो इम्यूनोथेरेपी की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

CRISPR जीन एडिटिंग तकनीक:

- यह कैंसर के लिए एक व्यक्तिगत उपचार विकसित करने में एक नया प्रयोग है। इस तकनीक का उपयोग पहले मनुष्यों में कैंसर के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को अधिक सक्रिय करने की अनुमति देने के लिए विशिष्ट जीन को हटाने के लिए किया गया है। सीआरआईएसपीआर का इस्तेमाल न केवल विशिष्ट जीन को बाहर निकालने के लिए किया गया, बल्कि प्रतिरक्षा कोशिकाओं में नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए भी किया गया, ताकि रोगी की अपनी कैंसर कोशिकाओं में उत्परिवर्तन को पहचानने के लिए कुशलतापूर्वक पुनर्निर्देशित किया जा सके।

कार्य प्रणाली:

- जब रोगियों को पुन: संक्रमित किया जाता है, तो ये सीआरआईएसपीआर-इंजीनियर प्रतिरक्षा कोशिकाएं कैंसर के लिए तरजीह देती हैं, वहां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली प्रतिरक्षा कोशिकाएं बन जाती हैं।
- मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर विशिष्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें सामान्य कोशिकाओं से अलग कर सकते हैं।
- ये हर मरीज के लिए अलग-अलग होते हैं। इसलिए कैंसर के इलाज के लिए एक व्यक्तिगत सेल थेरेपी उत्पन्न करने हेतु उन्हें अलग करने और उन्हें प्रतिरक्षा कोशिकाओं में वापस डालने का एक कुशल तरीका खोजना बड़े पैमाने पर दृष्टिकोण को संभव बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इन प्रतिरक्षा रिसेप्टर्स को रोगी के अपने रक्त से अलग करने का एक कुशल तरीका खोजा है।
- कैंसर के लिए व्यक्तिगत सेल उपचार की पीढ़ी एक ही चरण में क्लिनिकल-ग्रेड सेल की तैयारी में प्रतिरक्षा रिसेप्टर्स को बदलने के लिए सीआरआईएसपीआर तकनीक का उपयोग करने की नई विकसित क्षमता के बिना संभव नहीं है।
- शोधकर्ताओं ने 16 रोगियों को विभिन्न प्रकार के ठोस कैंसर के इलाज की रिपोर्ट दी, जिसमें कोलन, स्तन और फेफड़ों के कैंसर शामिल हैं।
- रोगियों के रक्त से उनके बंधन के आधार पर प्रतिरक्षा कोशिकाओं को अलग किया गया था, जो रोगी के स्वयं के कैंसर से 350 म्यूटेशन तक प्रदर्शित होते हैं। कुल मिलाकर 5000 से अधिक म्यूटेशनों को प्रतिरक्षा प्रणाली के एचएलए उप प्रकारों के 34 स्वादों में लक्षित किया जाता है। उन्हें एक-चरणीय सीआरआईएसपीआर संपादन का उपयोग करके रोगी की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं में वापस डाला गया, जिसमें मौजूदा प्रतिरक्षा सेल रिसेप्टर्स के नॉक-आउट और प्रतिरक्षा रिसेप्टर्स के नॉक-इन शामिल थे जो उन कोशिकाओं को विशेष रूप से उत्परिवर्तनों को पहचानने के लिए पुनर्निर्देशित कर सकते थे।

आगे की राह:

मरीजों पर कीमोथेरेपी के अनेक दुष्प्रभाव थे। जैसे-रोगियों में जीन संपादित कोशिकाओं से बुखार तथा ठंड जैसी समस्याएं। यह कार्यात्मक जीनोमिक्स अनुसंधान में CRISPR आधारित गेन-ऑफ-फंक्शन स्क्रीन की व्यापक प्रयोज्यता को प्रदर्शित करते हैं जो कुशल जीनोम-वाइड जीन-एडिटिंग सिस्टम की संभावित शक्ति नई विविधताओं और विशेषज्ञताओं के अभिनव विकास को जारी रखती है जो निकट भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है।

5 भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-एस सफलतापूर्वक लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इसरो ने पहली बार एक निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी विक्रम सबऑर्बिटल रॉकेट है। प्रारंभ (शुरुआत) नाम का मिशन, अंतरिक्ष में भारतीय निजी क्षेत्र का पहला प्रवेश है। रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद करीब 115 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित रूप से गिरा जिसके बाद इस मिशन को सफल घोषित किया गया।

प्रारंभ मिशन के बारे में:

- प्रारंभ एक ऐसा मिशन है जिसके तहत विक्रम-एस, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान उप-कक्षीय उड़ान में 3 ग्राहक उपग्रह (2 भारतीय और 1 विदेशी) ले जाएगा। प्रारंभ मिशन का उद्देश्य तीन पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है, जिसमें 2.5 किलोग्राम पेलोड शामिल है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) के व्यापक समर्थन के साथ हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।

विक्रम-एस रॉकेट के बारे में:

- यह एक सिंगल-स्टेज सॉलिड-फ्यूल सबऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसका नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अंतरिक्ष यान उप-कक्षीय उड़ान में कक्षीय वेग की तुलना में धीमी गति से यात्रा करता है, जिसका अर्थ है कि यह बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त तेज है लेकिन पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। प्रक्षेपण यान कलाम-80 इंजन का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है।
- विक्रम-एस एक छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसएलवी) है जो 290 से 560 किलोग्राम (पीएसएलवी 1,750 किलोग्राम) का पेलोड सूर्य के समक्ष वाले ध्रुवीय कक्षाओं में ले जा सकता है।

मिशन का महत्त्व:

- विक्रम-एस का सफल प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र के प्रवेश का प्रतीक है, जो अब तक सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित है। इससे प्रक्षेपण यान, उपग्रह, पेलोड और ग्राउंड स्टेशन की बाजारों में निजी भागीदारी बढ़ेगी। इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के भी जल्द ही निजी कंपनियों द्वारा निर्मित और संचालित किए जाने की संभावना है।

आगे की राह:

बड़ी संख्या में कंपनियां अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश रखने की क्षमता रखती हैं। इसरो उनके लिए एक सहायक की भूमिका निभा सकता है और प्रौद्योगिकियों के निर्माण में उनकी मदद कर सकता है। इस तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ेगी जिससे भारत निजी उपग्रहों का लॉन्च हब बन सकता है।

6 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने आतंक के वित्तपोषण में उभरते रुझानों, नई उभरती वित्तीय तकनीकों के दुरुपयोग और आतंक के वित्तपोषण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रभावी ढंग से चर्चा की।

तकनीक का दुरुपयोग:

- आतंकवादी समूह आधुनिक हथियारों तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे डार्क नेट और क्रिप्टो-करेंसी की बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं। आतंकवाद का डायनामाइट से मेटावर्स और एके-47 से आभासी संपत्ति में परिवर्तन निश्चित रूप से देशों के लिए चिंता का विषय है।

आतंकवाद के लिए डार्क नेट का उपयोग:

- डार्कनेट या डार्क वेब या डीप वेब इंटरनेट साइटों का गुप्त समूह है जिसे केवल एक विशेष वेब ब्राउजर जैसे-टोर, फ्रीनेट, आई2पी और टेल्स द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसका उपयोग इंटरनेट गतिविधि को गुमनाम और निजी रखने के लिए किया जाता है, जो कानूनी तथा अवैध दोनों अनुप्रयोगों में सहायक होता है। इसका उपयोग सरकारी सेंसरशिप से बचने के लिए और अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। डार्क वेब, ओनियन राउटर (ToR) का उपयोग करके गोपनीयता से काम करता है। हाल के दिनों में आतंकवादी अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहें हैं।

आतंकवाद के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल:

- क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल या डिजिटल करेंसी का एक रूप है जो

नेटवर्क आधारित है। मुद्रा का यह रूप किसी केंद्र सरकार या प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है और न ही कानूनी निविदा के रूप में माना जाता है। इन वर्षों में विभिन्न प्रकार की क्रिप्टो मुद्राएं आई हैं। जैसे-बिटकॉइन, रिपल, मोनेरो, जेडकैश-2 आदि, लेकिन बिटकॉइन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता का एक प्राथमिक कारण लिपिक और जटिल कागजी कार्यवाही की कमी है। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी पर नियमन की कमी का आतंकवादी संगठन दुरुपयोग कर रहे हैं।

- 2019 में हमास की सैन्य शाखा और एक नामित आतंकवादी संगठन इज्ज एड-दीन अल-कसम ब्रिगेड (एक्यूबी) ने एक वेबसाइट के माध्यम से धन एकत्र किया, जिसने प्रत्येक दाता को धन भेजने के लिए एक नया बिटकॉइन पता तैयार किया। अभियान ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो भी प्रकाशित किया, जिसमें लोगों को गुमनाम रूप से दान करना सिखाया गया। दिसंबर में, अख बार-अल-मुसलमीन और इसदारत जैसी आईएस समर्थक वेबसाइट बिटकॉइन दान के माध्यम से धन की याचना कर रही थीं। इसदारत को केवल टीओआर (द ओनियन राउटर) ब्राउजर के माध्यम से 'डार्क वेब' पर देखा जा सकता है।

आगे की राह:

हवाला प्रणाली शायद आतंकवादी समूहों का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वित्तीय साधन था। यह काफी सरल प्रणाली थी जो सीमाओं के पार धन के हस्तांतरण की अनुमति देती थी। लेकिन 9/11 के हमलों के बाद हवाला प्रणाली ऑनलाइन डोमेन में आ गई है और अनुमानित 258.9 बिलियन यूरो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से उपयोग किए गए हैं जिसमें अधिकांश फंड इस्लामिक स्टेट अल-कायदा से जुड़े हैं।

7 ईओएस-06 उपग्रह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) ने श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle-PSLV) C-54 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।

EOS-06 उपग्रह के बारे में:

- EOS-06 ओशनसैट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, जो बढ़ी हुई पेलोड क्षमता के साथ ओशनसैट-2 की निरंतर सेवाएं प्रदान करता है। ऑनबोर्ड उपग्रह में चार महत्त्वपूर्ण पेलोड होते हैं। ओशन कलर मॉनिटर (OCM-3), सी-सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर (SSTM), Ku-बैंड स्कैटरोमीटर (SCAT-3), ARGOSA है। ओशनसैट-2 जिसे सितंबर 2009 के दौरान लॉन्च किया गया था। यह वैश्विक महासागरों को कवर करने और वैश्विक पवन वेक्टर, निचले वातावरण, आयनमंडल के लक्षण आदि के साथ समुद्र के डेटा की निरंतरता प्रदान करने के लिए संरूपित किया गया था। इस मिशन के परिणामस्वरूप वैश्विक क्लोरोफिल वितरण, केडी-490 वितरण, समुद्र के रंग की छवियां, तेल रिसाव, पवन वेक्टर उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शोध सहयोग हुए हैं।
- EOS-06 से समुद्र विज्ञान, जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए समुद्र के रंग डेटा, समुद्र की सतह के तापमान तथा पवन वेक्टर डेटा का निरीक्षण करने की परिकल्पना की गई है। यह उपग्रह क्लोरोफिल, एसएसटी, हवा की गति और भूमि आधारित भू-भौतिकीय मापदंडों का उपयोग करके संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों का भी समर्थन करेगा।

आईएनएस-2बी के बारे में:

- INS-2B भारत और भूटान के बीच एक सहयोगी मिशन है जिसमें 2 पेलोड नैनोएमएक्स (एक मल्टीस्पेक्ट्रल ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड) और एपीआरएस-डिजिपीटर हैं। भारत ने इस मिशन हेतु क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की। भूटानी इंजीनियरों को उपग्रहों के निर्माण और परीक्षण के साथ-साथ उपग्रह डेटा की प्रक्रिया तथा विश्लेषण करने के लिए बेंगलुरु में यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। यह नया लॉन्च किया गया उपग्रह भूटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियां प्रदान करेगा।

आगे की राह:

EOS-06 उपग्रह को राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महासागर अध्ययन हेतु डिजाइन और विकसित किया गया है। यह समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रहों की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है जो भारतीय जल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देते हुए हिंद महासागर को रणनीतिक बढ़त प्रदान कर सकता है। INS-2B उपग्रह दोनों देशों (भारत-भूटान) के बीच अंतरिक्ष में विस्तारित सहयोग को चिह्नित करेगा जिसके जरिए भारत अंतरिक्ष कूटनीति को बढ़ा सकता है और विज्ञान के क्षेत्र में गहरा सहयोग कर सकता है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अन्य गैर-उपग्रह इसरो को एक निजी प्लेयर के लिए एक संभावित उपग्रह लॉन्चर बना सकते हैं। वहीं, निजी प्लेयर्स के साथ इसरो विदेशी बाजार में दबदबा बना सकता है।

1 पुरानी पेंशन योजना का मूल्यांकन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया गया।

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) क्या है?

- ओपीएस के तहत केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को अंतिम आहरित मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पहले किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 10,000 रुपये था, तो उसे 5000 रुपये की पेंशन दिया जाता है।
- इसमें कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ते (डीए) में संशोधन का लाभ मिलता है। डीए जीवन यापन की लागत में वृद्धि के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाने वाला एक समायोजन है। OPS को 1 जनवरी, 2004 से बंद कर दिया गया था।

ओपीएस के साथ समस्याएं:

1. पेंशन की देनदारी अनफंडेड होना:

- अर्थात, पेंशन कोष के लिए कोई अभिवृद्धि नहीं की गई, जो लगातार बढ़ रही थी जिसे भविष्य के भुगतानों के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
- केंद्र सरकार हर साल बजट से पहले सेवानिवृत्त लोगों को भुगतान का अनुमान लगाकर पेंशन प्रदान करती है जिसकी भरपाई करदाताओं के भुगतान से किया जाता है।
- करदाताओं की वर्तमान पीढ़ी ने आज की तारीख में सभी पेंशनभोगियों को भुगतान किया है।
- 'Pay-as-you-go' योजना ने अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी मुद्दों का निर्माण किया।

2. ओपीएस अस्थिर था:

- पेंशन देनदारियों में हो रही वृद्धि से पेंशनरों के लाभ में हर साल बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा कर्मचारियों के वेतन की तरह, पेंशनरों को इंडेक्सेशन से लाभ हुआ।
- सरकार ने उन्हें 'महंगाई राहत' (मौजूदा कर्मचारियों के लिए डीए के समान) का भुगतान किया।
- बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के कारण जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है।

3. बढ़ता आर्थिक दबाव:

- राज्यों का संचयी पेंशन बिल 1990-91 में 3,131 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 3,86,001 करोड़ रुपये हो गया है। राज्यों द्वारा पेंशन भुगतान उनके स्वयं के कर राजस्व का एक चौथाई होता है जिससे राज्य सरकारों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार का राजस्व प्रभावित होता है।

समस्याओं से निपटने की योजना:

- 1998 में वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा (OASIS) परियोजना को केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। OASIS का प्राथमिक उद्देश्य उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित था जिनके पास वृद्धावस्था आय सुरक्षा नहीं थी। हालांकि, प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को सरकार का समर्थन नहीं मिला, लेकिन यह 2003 में अधिसूचित नई पेंशन योजना का आधार बनी।

Age of Joining	21		30		40	
Grade Pay (Initial Basic Pay)	Pension (NPS)	Pension (OPS)	Pension (NPS)	Pension (OPS)	Pension (NPS)	Pension (OPS)
1800 (18000)	2,75,000	1,10,000	1,00,000	62,000	30,000	33,000
2400 (25500)	3,90,000	1,55,000	1,44,000	88,000	42,000	47,000
4200 (35400)	5,44,000	2,16,000	2,00,000	1,22,000	60,000	65,000
4800 (47600)	7,30,000	2,90,000	2,70,000	1,65,000	80,000	87,000
5400 (56100)	8,60,000	3,43,000	3,16,000	1,93,000	94,000	1,00,000

नई पेंशन योजना (एनपीएस):

- इसमें कर्मचारी द्वारा मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत तथा सरकार द्वारा एक समान योगदान शामिल है। सरकार द्वारा योगदान को 2019 में संशोधित करके 14 प्रतिशत कर दिया गया।
- एनपीएस को देश में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा लागू किया जाता है।

आगे की राह:

ओपीएस, अल्पावधि में राज्य सरकारों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए पैसे बचाता है क्योंकि उन्हें कर्मचारी पेंशन फंड में 10 प्रतिशत योगदान नहीं देना होगा। योजनाओं और पाठ्यक्रम सुधार का सावधानीपूर्वक विश्लेषण समय की मांग है।

2 आरबीआई ने भारत में वोस्ट्रो खाते खोलने की दी अनुमति

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में विदेशी व्यापार की सुविधा हेतु दो भारतीय बैंकों (यूको बैंक और इंडसइंड बैंक) में नौ विशेष वोस्ट्रो खाते खोलने की मंजूरी दी। Sberbank और VTB Bank-रूस के शीर्ष सबसे बड़े बैंक है जो RBI से अनुमोदन प्राप्त करने वाले पहले विदेशी ऋणदाता हैं।

वोस्ट्रो खाता क्या है?

- वोस्ट्रो खाता ऐसा खाता होता है जो एक घरेलू बैंक विदेशी बैंक के लिए घरेलू बैंक की मुद्रा (रुपये) में कार्य करता है।
- एक वोस्ट्रो खाता विदेशी संवाददाता बैंक को एक घरेलू बैंक हेतु मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है ताकि उन देशों में ग्राहकों के लिए वायर ट्रांसफर, निकासी और जमा को निष्पादित करने में सक्षम बनाया जा सके, जहां घरेलू बैंक की भौतिक उपस्थिति नहीं है।
- वोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है (Yours) अपना।

रुपये में वैश्विक व्यापार निपटान तंत्र:

- प्रतिबंधों से प्रभावित रूस के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू व्यापारियों के लिए भारतीय रुपये में निपटान की अनुमति दी है।
- भारतीय आयातक रुपये में भुगतान करेंगे, जिसे भागीदार देश के संवाददाता बैंक के वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा।
- भारतीय निर्यातकों को वोस्ट्रो खाते द्वारा शेष राशि को रुपये में निर्यात आय का भुगतान किया जाएगा।

प्रमुख लाभ:

- **भारतीय निर्यात और मुद्रा को बढ़ावा-** यह भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार विकास को बढ़ावा देगा और भारतीय रुपये में वैश्विक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करेगा।
- **विदेशी मुद्रा की बचत और व्यापार घाटा कम होगा-** इससे देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह अधिक मजबूत होगा जिससे रुपये को स्थिर करने में मदद मिलेगी।
- **प्रतिबंधित देशों के साथ लेन-देन में तेजी लाना-** व्यापार समझौते के विकल्प का खुलना, पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के सामने एक व्यापारिक भागीदार के रूप में रूस के महत्त्व को दर्शाता है।
- **भारतीय रुपये में बंदोबस्त-** रुपये के कमजोर होने के जारी परिदृश्य के बीच, यह तंत्र व्यापार प्रवाह के रुपये के निपटान में बढ़ावा देगा जिससे विदेशी मुद्रा की मांग में कमी आएगी।

आगे की राह:

वोस्ट्रो खाता भारत और रूस के बीच व्यापार हेतु रुपये में भुगतान के निपटान का मार्ग प्रशस्त करता है ताकि व्यापार अन्य विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित न हों। इससे दोनों देशों के हितों में वृद्धि होने की संभावना है।

3 एनएफआरए ने लेखापरीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण किया शुरू

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने लेखापरीक्षा पेशे की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु अपने लेखापरीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण दिशानिर्देशों को प्रकाशित किया है। यह निरीक्षण दिशा-निर्देश अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा नियामकों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम पद्धति की तर्ज पर आधारित हैं।

ऑडिट गुणवत्ता निरीक्षण:

- लेखापरीक्षा निरीक्षण दुनिया भर में स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों के कामकाज का अभिन्न अंग हैं।
- स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच (जिसमें 54 देशों के स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामक शामिल हैं) आवश्यक है ताकि जनहित संस्थाओं के लेखापरीक्षा करने वाली लेखापरीक्षा फर्मों का आवर्ती निरीक्षण किया जा सके।
- इस निरीक्षण में आमतौर पर लागू ऑडिटिंग मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण नीति और प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु व्यक्तिगत ऑडिट असाइनमेंट की फर्म-व्यापी गुणवत्ता समीक्षा शामिल होता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए नियामक के पास, ऑडिट गुणवत्ता

निरीक्षण एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।

- निरीक्षणों का समग्र उद्देश्य ऑडिटिंग मानकों तथा अन्य नियामक और पेशेवर आवश्यकताओं के साथ ऑडिट का मूल्यांकन करना है। इसके अन्य प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं-
  1. शासन ढांचे और उसके कामकाज की पर्याप्तता।
  2. ऑडिट गुणवत्ता पर फर्म के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता।
  3. लेखापरीक्षा जोखिमों और शमन उपायों के मूल्यांकन तथा पहचान की प्रणाली।
- निरीक्षण का उद्देश्य ऑडिट फर्म की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए क्षेत्रों और अवसरों की पहचान करना है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए):

- एनएफआरए को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-132(1) के तहत 2018 में एक वैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया था।
- यह एक ऑडिट रेगुलेटर है जो कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली अकाउंटिंग और ऑडिटिंग नीतियों की सिफारिश करता है।
- एनएफआरए लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन, गुणवत्ता की निगरानी और प्रवर्तन भी करता है।
- एनएफआरए में एक अध्यक्ष होता है, जो लेखा परीक्षा, वित्त या कानून में विशेषज्ञता रखता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं।
- इसके खाते की निगरानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

आगे की राह:

लेखापरीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण, लेखापरीक्षा फर्मों को प्रतिक्रिया तथा पाठ्यक्रम सुधार का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही उन नीतियों, प्रक्रियाओं की अधिक पारस्परिक समझ को बढ़ावा देगा जो लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन को रेखांकित करते हैं। इससे आने वाले समय में व्यवस्थित सुधार आने की संभावना है।

4 भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचे को मंजूरी दी है जिसे स्वच्छ पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए जुटाया जाएगा।

ग्रीन बॉन्ड क्या है?

- ग्रीन बांड वित्तीय साधन हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी और जलवायु-उपयुक्त परियोजनाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और हरित भवनों में निवेश के लिए धन एकत्रित करते हैं। ये कंपनियों, देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
- ग्रीन बांड में नियमित बांड की तुलना में पूंजी की अपेक्षाकृत कम लागत होती है।
- भारत में पहला ग्रीन बॉन्ड 2015 में यस बैंक द्वारा जारी किया गया था।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क:

- COP-26 के दौरान ग्लासगो में प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट किए गए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु, भारत की प्रतिबद्धता को यह ढांचा सुविधाजनक बनाएगा।
- यह पेरिस समझौते के तहत अपनाए गए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।
- ऐसे बॉन्ड जारी करने से प्राप्त आय को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करेगी।
- यह फ्रेमवर्क हरित परियोजनाओं में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा।

हरित वित्त कार्य समिति:

- मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में, ग्रीन बांड के माध्यम से वित्त पोषण हेतु पात्र परियोजनाओं का चयन करने के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति में पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग और अन्य के

सदस्य शामिल हैं।

महत्त्वः

- यह फ्रेमवर्क जलवायु कार्यवाही और सतत विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।
- ग्रीन बांड जलवायु मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए जारीकर्त्ता की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करते हैं।
- संस्थागत निवेशकों को प्रोत्साहन देकर यह घरेलू बाजार को उत्प्रेरित करता है।
- फ्रेमवर्क को एक स्वतंत्र संगठन- सिसरो द्वारा 'अच्छे शासन स्कोर' के साथ 'मीडियम ग्रीन' का दर्जा दिया गया है।

आगे की राहः

ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के विकास से अंततः देश में एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा जो वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मददगार साबित होगा।

5 9वां इंडिया-यू.एस आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक का आयोजन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय केंद्रीय वित्त तथा कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी सचिव डॉ. जेनेट एल येलेन के मध्य नई दिल्ली में भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी की 9वीं बैठक आयोजित की गई।

बैठक की मुख्य विशेषताएंः

- दोनों देशों ने ऋण स्थिरता, द्विपक्षीय ऋण में पारदर्शिता तथा ऋण संकट का सामना कर रहे देशों के लिए उचित और न्यायसंगत ऋण उपचार के विस्तार पर बारीकी से समन्वय करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों देशों ने वैश्विक मैक्रोइकनॉमिक आउटलुक के लिए मौजूदा हेडविंड पर भी चर्चा की, जिसमें बढ़ती कमोडिटी तथा ऊर्जा की कीमतों के साथ-साथ आपूर्ति पक्ष में व्यवधान और इन वैश्विक मैक्रोइकनॉमिक चुनौतियों को संबोधित करने में बहुपक्षीय सहयोग शामिल हैं। इन वैश्विक मैक्रोइकनॉमिक चुनौतियों को संबोधित करने में बहुपक्षीय सहयोग की केंद्रीय भूमिका के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- दोनों देश 2023 की पहली छमाही के दौरान बहुपक्षीय सम्मेलन पर काम समाप्त करने के लिए आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) पर ओईसीडी/जी-20 समावेशी ढांचे का आह्वान करते हैं। वे GloBE (वैश्विक आधार-विरोधी कटाव) कार्यान्वयन ढांचे के पूरा होने की आशा करते हैं। वे सदस्य देशों और BEPS पर ECD/G-20 समावेशी फ्रेमवर्क से कर नियम (STTR) के विषय पर बातचीत का आह्वान करते हैं।
- दोनों देशों ने एक पूर्वानुमानित, समयबद्ध, व्यवस्थित और समन्वित तरीके से ऋण उपचार के लिए जी-20 साझा रूपरेखा को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देश सार्थक शमन कार्यों और कार्यान्वयन पर पारदर्शिता के संदर्भ में विकासशील देशों के लिए 2025 तक सार्वजनिक तथा निजी स्रोतों से हर साल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने अपतटीय कर चोरी से निपटने के लिए सूचना साझा करने में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। दोनों देश विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के लिए वित्तीय खाते की जानकारी साझा करने से संबंधित चर्चा में शामिल हुए।
- दोनों देशों ने जलवायु महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाने के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से व्यक्त जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने हेतु संबंधित घरेलू प्रयासों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रयासों को फिर से सक्रिय किया। उन्होंने जलवायु कार्यवाही सहित विकास उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए भारत तक पहुंच बनाने और उपलब्ध वित्त पोषण जुटाने में मदद करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंक प्रणाली के माध्यम से काम करने के महत्त्व को स्वीकार किया। दोनों की योजना वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय रूप से बातचीत जारी रखने की है।

भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों के सामने चुनौतियांः

- 2018 में, अमेरिका ने भारत के कुछ स्टील उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया और एल्यूमीनियम उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया। आत्मानिर्भर भारत अभियान ने इस विचार को और तेज कर दिया है कि भारत तेजी से एक संरक्षणवादी बाजार अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। यूएसए ने जीएसपी कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को शुल्क मुक्त लाभ वापस लेने का फैसला किया। नतीजतन, अमेरिका को 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर विशेष शुल्क उपचार हटा दिया गया, जिससे भारत के निर्यात क्षेत्रों जैसे- फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, कृषि उत्पाद और ऑटोमोटिव पार्ट्स प्रभावित हुए। इन सभी चुनौतियों का शीघ्र समाधान

किया जाना चाहिए।

आगे की राह:

आर्थिक तथा वित्तीय साझेदारी की 9वीं बैठक में अमेरिका-भारत संबंधों के बढ़ते महत्त्व और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते आर्थिक-वित्तीय संबंधों को दर्शाया गया है। दोनों पक्षों के बीच आर्थिक-वित्तीय साझेदारी के तहत निरंतर बातचीत से, द्विपक्षीय संबंधों के अधिक मजबूत होने की संभावना हैं।

6 भारत का बढ़ता क्रेडिट इकोसिस्टम

चर्चा में क्यों?

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2022 में गैर-खाद्य बैंक ऋण में 16.9% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में, कुल ऋण बाजार 11.1% की वृद्धि दर्ज करते हुए 174.3 लाख करोड़ रुपये था। खुदरा ऋण और अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कार्ड का बढ़ता उपयोग इस वृद्धि का मुख्य कारक है। भारत में ऋण की मांग समय के साथ तेजी से बढ़ी है।

विभिन्न प्रकार की क्रेडिट प्रणाली:

- अतीत में, औपचारिक ऋण केवल व्यक्तिगत, ऑटो और गृह ऋण जैसे वित्तीय उत्पादों के लिए उपलब्ध था। बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) ने हाल ही में अपना ध्यान क्रेडिट कार्ड, अभी खरीदें बाद में भुगतान करें (बीएनपीएल) और उपभोक्ता टिकाऊ ऋण (क्रेडिट ईएमआई) जैसे उत्पादों पर केंद्रित किया है। पारंपरिक बैंक और नए स्टार्टअप बिना बैंक वाली आबादी (Unbanked Population) को ऋण उपलब्ध कराकर नए ग्राहकों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

क्रेडिट कार्ड:

- भारत पारंपरिक रूप से डेबिट कार्ड का बाजार रहा है, पिछले दस वर्षों में, क्रेडिट कार्ड जारी करने में वृद्धि ने इसे बदल दिया है। क्रेडिट कार्ड अब व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। सरलीकृत ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाएं, अद्वितीय कार्ड उत्पाद, वैयक्तिकृत ऑफर और पुरस्कार, बेहतर मोबाइल ऐप जैसे नवाचार मौजूदा ग्राहकों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हुए हैं जिसने कई नए लोगों को आकर्षित किया है।
- पिछले 5 वर्षों में क्रेडिट कार्ड जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 2022 के बीच 19.8% की सीएजीआर से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2021 और 2022 के कोविड-19 प्रतिबंधित वर्षों के दौरान भी, क्रेडिट कार्ड जारी करने की दर क्रमशः 7.46% और 18.66% की दर से बढ़ी है।

अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (Buy Now Pay Later):

- ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान के उद्भव तथा फिनटेक कंपनियों के तेजी से विकास के कारण, अभी खरीदें बाद में भुगतान करें (बीएनपीएल) भारत में एक तेजी से बढ़ता हुआ ऋण प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में, बीएनपीएल केवल प्रत्यक्ष भुगतान पद्धति से कहीं अधिक हो गया है। मुफ्त ईएमआई प्रदान करके, यह अनिवार्य रूप से उधारकर्त्ताओं के वित्तीय तनाव को कम करता है। BNPL विशेष रूप से GenZ उपभोक्ताओं, युवा करोड़पति और पहली बार कर्ज लेने वालों के बीच लोकप्रिय रहा है, जिन्हें आमतौर पर पारंपरिक बैंकों द्वारा अनदेखा किया जाता है।

बीएनपीएल की कुछ विशेषताएं हैं:

- औसत लेनदेन सीमा 1,500-25,000 रुपये के बीच है।
- पुनर्भुगतान चक्र 15-45 दिनों के बीच है।
- नियमित क्रेडिट कार्ड के विपरीत, बीएनपीएल उन लोगों के लिए कम लागत वाली, अल्पकालिक वित्तपोषण का एकमात्र रूप है, जिनके पास पहले कभी क्रेडिट नहीं था।

उपभोक्ता टिकाऊ ऋण (कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन):

- बढ़ती शहरी आबादी, बढ़ती आय खपत और कम ब्याज वाले ऋणों की उपलब्धता के कारण, क्रेडिट ईएमआई, जिसे उपभोक्ता टिकाऊ ऋण भी कहा जाता है, औपचारिक ऋण की एक अन्य श्रेणी है जो तीव्र गति से बढ़ रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का मूल्य 21% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। यह 2020-21 में 84 बिलियन डॉलर था जो 2026-27 में 205 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है।

उपभोक्ता टिकाऊ ऋण की मुख्य विशेषताएं:

- अधिकांश कंपनियां तत्काल अनुमोदन और न्यूनतम दस्तावेजीकरण आवश्यकता प्रदान करते हैं, जबकि मोबाइल नंबरों का उपयोग केवाईसी प्रक्रियाओं को जल्दी से पूरा

करने के लिए किया जा सकता है।

- कम प्रोसेसिंग लागत, उचित ब्याज दर और कुछ मामलों में नो-कॉस्ट ईएमआई उपलब्ध है।
- अधिकांश उपभोगकर्त्ताओं को डाउन पेमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं होती है।
- ऋण अवधि 3-60 महीने है।

आगे की राह:

आरबीआई ने अपने पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज में क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों को यूपीआई से जोड़ने की योजना की घोषणा की। आरबीआई देश भर में स्वीकृति बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की भी योजना बना रहा है, जिससे कार्ड लेनदेन की संख्या में और वृद्धि होगी।

7 जीएसटी मुआवजा

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने मुआवजा उपकर कोष से अप्रैल-जून, 2022 की अवधि हेतु शेष जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की। वर्ष 2022-23 के दौरान उपरोक्त राशि सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अब तक जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये हो गयी है।

केंद्र सरकार ने कहा कि अक्टूबर, 2022 तक केवल 72,147 करोड़ रुपये के कुल उपकर संग्रह के बावजूद, केंद्र ने अपने संसाधनों से 43,515 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस रिलीज के साथ, केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए उपलब्ध इस साल मार्च के अंत तक अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है। राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया था कि राज्य वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रमों, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय पर व्यय सफलतापूर्वक कर सकें।

मुआवजा उपकर के बारे में:

- जी.एस.टी. आने से पहले राज्यों को पहले पांच वर्षों के लिए 14% वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) से नीचे किसी भी राजस्व की कमी के लिए मुआवजे की गारंटी दी गई थी। केंद्र द्वारा राज्यों को हर दो महीने में मुआवजा उपकर से जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया जाता है। यह मुआवजा उपकर जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 द्वारा निर्दिष्ट किया गया था।
- विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात करने वाले और जीएसटी संरचना योजना का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर, सभी करदाता केंद्र सरकार को जीएसटी मुआवजा उपकर जमा करने तथा भेजने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

मुआवजा उपकर कोष के बारे में:

जीएसटी अधिनियम में कहा गया है कि एकत्रित उपकर और जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित राशि को निधि में जमा किया जाएगा।

वस्तु एवं सेवा कर:

- GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पारित किया गया था।
- यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
- जीएसटी उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है।
- यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है जिसे अंतिम खपत बिंदु पर लगाया जाता है।
- इससे दोहरे कराधान, करों के प्रपाती प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण के मुद्दों आदि को कम करने में मदद मिली है, जिसने एक आम राष्ट्रीय बाजार का नेतृत्व किया है।
- जीएसटी कैस्केडिंग प्रभाव या कर पर कर से बचाता है जिससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।

आगे की राह:

मुआवजा उपकर एक उपकर है जो चुनिंदा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर एकत्र किया जाता है। उपकर जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को किसी भी राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति करता है। यह उपकर उन व्यक्तियों द्वारा देय नहीं होगा जिन्होंने मुआवजा लेवी का विकल्प चुना है। इस उपकर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग केवल मुआवजा उपकर का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, न कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी जैसे अन्य करों के लिए।

1 आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं बैठक (एडीएमएम प्लस) सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

भारत के रक्षामंत्री ने सिएम रीप (कंबोडिया) में एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के रक्षामंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम):

- इसकी स्थापना 2006 में सुरक्षा चुनौतियों की अधिक समझ के साथ-साथ पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ाकर आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- यह आसियान में सर्वोच्च रक्षा परामर्शी और सहकारी तंत्र है।
- इसमें आसियान के 10 सदस्य देशों के साथ ही 8 अन्य देश शामिल हैं।

एडीएमएम-प्लसः

- एडीएमएम प्लस में 10 आसियान सदस्य और इसके आठ संवाद भागीदार शामिल हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- प्रथम एडीएमएम प्लस मीटिंग 2010 में हनोई (वियतनाम) में आयोजित किया गया था, जबकि ब्रुनेई 2021 के लिए एडीएमएम प्लस फोरम का अध्यक्ष था।
- **उद्देश्यः** क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना।

व्यावहारिक सहयोग के 7 क्षेत्रों में शामिल हैं-

1. आतंकवाद का मुकाबला।
2. समुद्री सुरक्षा।
3. सैन्य चिकित्सा।
4. मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन।
5. मानवीय खदान कार्यवाही।
6. साइबर सुरक्षा।
7. शांति स्थापना अभियान।

बैठक की मुख्य बातेंः

- रक्षा मंत्री ने आसियान देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला।
- भारत-आसियान संबंध को हाल ही में व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया।
- **समुद्री सुरक्षाः** भारत मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की वकालत करता है। इसमें कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर चल रही आसियान-चीन वार्ता अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से यूएनसीएलओएस के अनुरूप होनी चाहिए।
- **आतंकवादः** भारत ने अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्काल तथा दृढ़ वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया।
- **अन्य सुरक्षा चिंताएंः** भारत ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा जैसी अन्य चिंताओं पर भी प्रकाश डाला।
- रक्षामंत्री ने भारत-आसियान रक्षा संबंधों के दायरे को और बढ़ाने के लिए दो प्रमुख पहलों का प्रस्ताव रखाः
  1. **'यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में महिलाओं के लिए भारत-आसियान पहल'**- इसमें आसियान सदस्य देशों की महिला शांति सैनिकों के लिए अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के पहलुओं को शामिल करते हुए महिला अधिकारियों के लिए भारत में 'टेबल टॉप अभ्यास' आयोजित करना शामिल है।
  2. **'समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण पर भारत-आसियान पहल'**- इसमें समुद्री प्रदूषण के महत्त्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में युवाओं की ऊर्जा को चैनलाइज करना शामिल है। भारत भारतीय तट रक्षक द्वारा चेन्नई में भारत-आसियान समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है।

आगे की राहः

वर्ष 2022 को 'आसियान-भारत मैत्री वर्ष' के रूप में नामित किया गया है। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' पर जोर देते हुए, फोरम ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत-आसियान संबंधों के महत्त्व को पहचाना।

2 ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिवः भारतीय वायु सेना में ईवीएस का पहला बैच शामिल

चर्चा में क्यों?

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय सेना ने यह पहल की है। भारतीय वायु सेना ने 15 नवंबर, 2022 को हरित गतिशीलता की शुरुआत पर भारत सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बेड़ा शामिल किया। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 12 इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। फ्लैग-ऑफ समारोह वायु सेना मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इलेक्ट्रिक कारों के पहले बैच को प्रदर्शन की निगरानी और विश्लेषण के लिए दिल्ली एनसीआर इकाइयों में तैनात किया गया है।

उद्देश्यः

- पर्यावरण के अनुकूल गतिशीलता हेतु परिवर्तन के राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता।
- भारतीय सेना ने अपने 'गो ग्रीन इनिशिएटिव' के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए 16 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टाटा पॉवर्स के साथ समझौता किया जिसके तहत दिल्ली छावनी में विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता क्यों?

- जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता सीमित है जिसका उपयोग हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है।
- पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले जहरीले उत्सर्जन से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्सर्जन प्रभाव पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में बहुत कम है। दक्षता के दृष्टिकोण से भी इलेक्ट्रिक वाहन ग्रिड से लगभग 60% विद्युत ऊर्जा को पहियों को चलाने के लिए कवर कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल या डीजल कारें ईंधन में संग्रहीत ऊर्जा का केवल 17%-21% ही पहियों में परिवर्तित कर सकती हैं जिससे लगभग 80% ऊर्जा की बर्बादी होती है।
- पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में शून्य टेलपाइप उत्सर्जन होता है जबकि पेट्रोल या डीजल वाहन औसत ईवी की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं।
- कार्बन फुट प्रिंट में कमी लाने और हरित गतिशीलता की शुरूआत के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया वाहनों के साथ ही लग्जरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ी है।

आगे की राहः

भारतीय वायु सेना डाउनग्रेडेड पारंपरिक वाहनों के खिलाफ ई-वाहनों की खरीद करके इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने की योजना बना रही है। वायु सेना के विभिन्न ठिकानों पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना सहित ई-वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने की भी योजना है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी इलेक्ट्रिक पावर स्थापित क्षमता प्राप्त करने में सहायता मिलने की संभावना है।

3 वांगला-मेघालय का 100 ड्रम महोत्सव

चर्चा में क्यों?

वांगला मेघालय के प्रसिद्ध त्यौहारों में से एक है, जिसे गारो समुदाय द्वारा बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 3 दिवसीय वांगला महोत्सव के 46वें पर्व का कार्यक्रम 10 से 12 नवंबर तक चला। इस त्यौहार की शुरुआत स्वदेशी खेलों, हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी के साथ हुई, जिसका उद्घाटन गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) अल्बिनुश आर. मारक ने किया।

वांगला क्या है?

वांगला महोत्सव मेघालय के सबसे लोकप्रिय त्यौहारों में से एक है। वांगला महोत्सव उर्वरता के सूर्य देवता (सालजोंग) के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। वांगला महोत्सव का उत्सव परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक है, जो खेतों में अच्छा उत्पादन लाता है। यह सर्दी के आगमन का भी प्रतीक है। 1976 से मनाया जाने वाला यह गारो जनजाति का सबसे महत्त्वपूर्ण त्यौहार है जो बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता

है।

वांगला महोत्सव की विशेषताएं:

- इसे 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है।
- इस अवसर पर आदिवासी अपने मुख्य देवता (सालजोंग) को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं।
- यह आम तौर पर दो दिनों के लिए मनाया जाता है और कभी-कभी एक सप्ताह तक भी जारी रहता है।
- पहले दिन किए जाने वाले समारोह को 'रागुला' के रूप में जाना जाता है जो मुखिया के घर के अंदर किया जाता है, वहीं दूसरे दिन को 'कक्कत' के नाम से जाना जाता है।
- युवा और बूढ़े लोग अपने रंगीन परिधानों में पंख वाले सिर के साथ लंबे अंडाकार आकार के ड्रमों पर बजने वाले संगीत की धुन पर नृत्य करते हैं।
- इस नृत्य की एक विशिष्ट विशेषता दो समानांतर रेखाओं की एक कतार से संबंधित है। एक पुरुष की और दूसरी उत्सव की पोशाक पहने महिलाओं की।
- यह आराम करने का अवसर है और कई दिनों तक पहाड़ और घाटियाँ नगाड़ों की असाधारण ताल से गूँजती रहती हैं।
- पुरुषों के 'ऑर्केस्ट्रा' में ड्रम, गोंग और बांसुरी शामिल हैं, जो भैंस के सींग से बनी एक आदिम बांसुरी के सुरीले संगीत द्वारा विरामित हैं।
- युवा और वृद्ध समान उत्साह के साथ उत्सव में शामिल होते हैं। युवा और वृद्ध कलाकारों में गति की एक उल्लेखनीय भावना है जो ऊर्जावान नृत्य देखने वाले पर एक स्थायी छाप छोड़ता है।

मूल रूप से वांगला महोत्सव मेघालय में गारो की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने का एक तरीका है। यह क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। वांगला गारो समुदाय से सटे विचार की ट्रेन के रूप में कार्य करता है। इससे उत्सव एकता की ताकत और एकजुटता के प्रभाव को चित्रित किया जाता है।

4 बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर, 2022 को बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रौद्योगिकी समानता और सशक्तीकरण की एक शक्ति है तथा इसने भारत के अभिनव युवा को तकनीक और प्रतिभा के वैश्वीकरण करने को बढ़ावा दिया है।

बेंगलुरु टेक समिट के बारे में:

- कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु टेक समिट के 25वें संस्करण की मेजबानी की। यह तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन था जिसका समापन 18 नवंबर, 2022 को हुआ।
- 32 देशों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया तथा 28 नए सामान पेश किए गए। इस दौरान कुल 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
- शिखर सम्मेलन में विशेष बूस्टर किट के लॉन्च किया, जो विशेष सॉफ्टवेयर उत्पादों और सेवाओं का एक मजबूत चयन है। ये विशेष रूप से युवा स्टार्ट-अप की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और उचित मूल्य पर उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इसी के चलते सरकार ने पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों के साथ नौ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें गूगल, Paytm, HDFC, RazorPay, Microsoft, The GAIN, Dayanand Sagar Entrepreneurship Research and Business Incubation, AWS Activate और StrongHer Ventures शामिल थे।

प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण और भारत:

- 'प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण' उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके माध्यम से प्रौद्योगिकी पहुंच लोगों को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराई जाती है।
- शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बताया, भारत इस वर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें से 40वें स्थान पर पहुंच गया है।
- इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 2021 के बाद से, भारत में यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप की संख्या दोगुनी हो गई है। भारत अब 81,000 मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
- पीएम ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे भारतीय युवाओं की अब प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच बढ़ी है? पिछले 8 वर्षों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन 60 मिलियन से बढ़कर 810 मिलियन हो गए हैं, जबकि 75 करोड़ लोग अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं।

भारत ने प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण कैसे किया?

- दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को शुरू किया गया जो लगभग 200 मिलियन परिवारों अर्थात 600 मिलियन लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। साथ ही कोविड टीकाकरण अभियान लांच किया गया था जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान था।
- स्वामित्व योजना ने संपत्ति के रिकॉर्ड को वैधता प्रदान की और वंचितों के लिए वित्त तक पहुंच बढ़ाई है। JAM ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुगम हो सके जो कई सामाजिक कार्यक्रमों का आधार बना।
- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान के अन्तर्गत भारत की बुनियादी ढांचे में 100 ट्रिलियन रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना है। इसके साझा मंच का उपयोग करके केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन सहयोग के लिए कार्य कर सकते हैं।

आगे की राह:

हालांकि, एफडीआई सुधारों या ड्रोन नियमों के उदारीकरण, सेमी-कंडक्टर क्षेत्र में बढ़ते कदम, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रोत्साहन योजनाओं या व्यापार करने में आसानी के उदय के माध्यम से, भारत ने तकनीकी बुनियादी ढांचे के बेहतर विकास के लिए कई उत्कृष्ट कारक बनाए हैं। शासन और विनियमन पर भी साथ-साथ काम करना समय की आवश्यकता है ताकि तकनीकी बुनियादी ढांचा वेब 3.0, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि के आगामी विकेंद्रीकृत युग के साथ और मजबूत हो सके।

5 काशी तमिल संगमम 2022

चर्चा में क्यों?

वाराणसी में महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है जबकि तमिलनाडु और तमिल संस्कृति भारत के प्राचीनता वैभव केंद्र रहे हैं।

काशी तमिल संगमम के बारे में:

- 'काशी तमिल संगमम' सरकार द्वारा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' और 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत तमिलनाडु तथा काशी की संस्कृतियों के बीच पुराने संबंधों को फिर से पोषित करने हेतु शुरू की गई एक पहल है।
- यह एक महीने का कार्यक्रम है जो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 2500 लोगों के 12 समूह चेन्नई, रामेश्वरम और कोयम्बटूर सहित अन्य जगहों से शामिल होंगे।
- उत्तर प्रदेश राज्य मेजबान के रूप में कार्य कर रहा है। IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कार्यक्रम के लिए ज्ञान भागीदारों के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूरे काशी तमिल संगमम के दौरान, भारत के दो महत्त्वपूर्ण और प्राचीन शैक्षिक केंद्रों के विभिन्न विषयों पर विद्वानों, विशेषज्ञों के बीच विभिन्न अकादमिक चर्चा तथा सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
- काशी विश्वनाथ मंदिर और राज्य के अन्य सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थानों के दर्शन करना, कार्यक्रम का भाग है।
- संगमम ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे-साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, नृत्य, रंगमंच, योग, आयुर्वेद, हथकरघा, शिल्प और आधुनिक नवाचारों के रूप में ट्रेडिंग एक्सचेंज, एडुटेक तथा अन्य अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियां आदि।

संगमम को इस समय आयोजित करने का महत्त्व:

- तमिल कैलेंडर के अनुसार, वर्ष का यह समय 'कार्तिक मास' है जो तमिलनाडु के इतिहास में बहुत शुभ है। इस समय के दौरान न केवल दक्षिण राज्यों बल्कि उत्तर राज्यों के विभिन्न महत्त्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाते हैं।
- महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संस्कृति की ये दो अभिव्यक्तियाँ भौगोलिक रूप से दूर होते हुए भी सदियों से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। काशी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर के आस-पास के स्थान जो आंतरिक रूप से ज्ञान केंद्र के रहे हैं, दूर-दूर से ज्ञान प्राप्ति हेतु आते थे। इसी प्रकार तमिलनाडु में कांचीपुरम, पुडुचेरी, मदुरै, तंजावुर, रामेश्वरम, श्रीरंगम, कन्याकुमारी आदि स्थान ज्ञान के उत्कृष्ट केंद्र थे।
- 15वीं शताब्दी में मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले पांड्य राजा पराक्रम भगवान शिव के लिए एक मंदिर चाहते थे। उन्होंने एक शिवलिंग वापस लाने के लिए काशी (उत्तर प्रदेश) की यात्रा की थी। वापस लौटने पर वे एक पेड़ के नीचे रुके लेकिन जब उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने की कोशिश की, तो शिवलिंग धारण करने वाली

गाय ने हिलने से मना कर दिया। पराक्रम पांड्या समझ गए कि यह प्रभु की इच्छा थी और वहां लिंगम स्थापित किया, एक ऐसा स्थान जिसे शिवकाशी (तमिलनाडु) के नाम से जाना जाने लगा।

- जो भक्त काशी की यात्रा कर पाने में असमर्थ थे। पांड्यों ने केरल के साथ राज्य की सीमा के पास दक्षिण-पश्चिमी तमिलनाडु में आज के तेनकासी में काशी विश्वनाथर मंदिर का निर्माण किया था।

आगे की राह:

यह संगमम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो एक ऐसी पीढ़ी का पोषण करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करती है जो भारतीय संस्कृति और लोकाचार में निहित है। साथ ही साथ 21वीं सदी की मानसिकता से तालमेल बिठाती है ताकि उत्तर-दक्षिण के बीच दूरी को कम किया जा सके।

6 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जारी किया।

मुख्य बिन्दु:

- 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2021 में 9.8% से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2% हो गई।
- बेरोजगारी की दर पुरुषों के लिए 6.6% और महिलाओं के लिए 9.4% रही। बेरोजगारी दर को श्रम शक्ति में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 44.5% था जो जुलाई-सितंबर 2021 में 42.3% था। डब्ल्यूपीआर पुरुषों में 68.6% और महिलाओं में 19.7% था। डब्ल्यूपीआर को जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- श्रम बल की भागीदारी दर बढ़कर 47.9% (जुलाई-सितंबर 2021 में 46.9%) हो गई जिसे 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है जो शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं। पुरुषों के बीच एलएफपीआर 73.4% और महिलाओं के बीच 21.7% रहा जो जुलाई-सितंबर 2021 में 73.5% तथा 19.9% था।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में:

- लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) लॉन्च किया था।

पीएलएफएस के उद्देश्य:

1. वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीने की कम समय अवधि में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (अर्थात श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना।
2. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार तथा बेरोजगारी के संकेतकों का अनुमान लगाना।

बेरोजगारी क्या है?

बेरोजगारी तब होती है जब एक व्यक्ति जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है उसे काम नहीं मिलता है। एनएसओ एक व्यक्ति की निम्नलिखित गतिविधि स्थितियों पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता है:

- आर्थिक गतिविधि में संलग्न अर्थात 'रोजगार'।
- काम की तलाश कर रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं, परन्तु रोजगार नहीं मिलता अर्थात 'बेरोजगार'।
- न तो काम की तलाश में हैं और न ही काम के लिए उपलब्ध हैं।
- पहले दो श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम शक्ति का प्रतिशत है जो काम से बाहर है।

बेरोजगारी दर = (बेरोजगार श्रमिक/कुल श्रम बल) X 100

आगे की राह:

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह माना जा सकता है कि भारत आर्थिक सुधार के पथ पर है और भारत उभरते बाजारों में से एक प्रमुख बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने युवाओं को कौशलयुक्त बना करके, रोजगारयुक्त बनाया जा सके जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो।

7 भारतीय विदेश नीति पर युवाओं का दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा भारत की विदेश नीति सर्वेक्षण रिपोर्ट का दूसरा सर्वेक्षण जारी किया गया। सर्वेक्षण में भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में शहरी युवा विश्व व्यवस्था में चल रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को मापा गया है।

सर्वेक्षण के परिणाम:

विदेश नीति में महत्त्वपूर्ण मोड़:

- पोखरण परमाणु परीक्षण, भारत-चीन युद्ध और गलवान घाटी संघर्ष को भारत की विदेश नीति में महत्त्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिन्हित किया गया।

विदेश नीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती:

- चीन के साथ सीमा संघर्ष को भारत की सबसे बड़ी विदेश नीति चुनौती के रूप में देखा गया। यह पाकिस्तान के साथ संघर्ष से बड़ी चुनौती मानी गयी।
- आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ सीमा संघर्ष भारत की विदेश नीति के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियां बने हुए हैं।
- सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर युवाओं ने यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान के साथ न उलझने की भारत की विदेश नीति से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को लाभ हुआ है।

भारत-अमेरिका संबंध:

- युवाओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता के बाद से दूसरे सबसे भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखा।
- 85% उत्तरदाताओं ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अगले 10 वर्षों में भारत का प्रमुख भागीदार होगा।
- 83% उत्तरदाताओं ने यह भी सहमति व्यक्त की कि भारत के उत्थान हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन महत्त्वपूर्ण होगा।

रूस-भारत संबंध:

- कई उत्तरदाताओं ने यूक्रेन पर आक्रमण के बावजूद रूस के प्रति आशावादी रहे।
- 43% ने रूस को आजादी के बाद से भारत के सबसे विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा।
- कई लोगों ने व्यापक भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में अपनी जागरूकता दिखाई। उदाहरण के लिए, भारी बहुमत ने सहमति व्यक्त की कि रूस के साथ भारत के आर्थिक संबंध सीमित हैं। उन्होंने रूस-चीन संबंधों को मजबूत करने तथा भारत-रूस के बीच कुछ असहमति हेतु चिंता व्यक्त की।
- जब अगले 10 वर्षों में भारत के अग्रणी साझेदार की बात आई तो रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे स्थान पर था।

विदेश नीति के चालक के रूप में भारतीय हित:

- भारतीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए युवाओं ने कहा कि यदि यूएस-चीन तनाव बढ़ता है, तो भारतीय युवाओं ने गुटनिरपेक्षता और तटस्थता को प्राथमिकता दी। लेकिन जब भारतीय हित दांव पर लगे तो प्रतिक्रियाएं बदल गई, 73% ने कहा कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ गठबंधन करना चाहिए।

क्षेत्रीय शक्ति का महत्त्व:

- बहुध्रुवीय तथा अधिक अनिश्चित विश्व व्यवस्था में क्षेत्रीय शक्तियों का महत्त्व बढ़ा है।
- क्वाड को लेकर उत्तरदाताओं के बीच संतोषजनक जवाब मिला लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के प्रति अधिक विश्वास रहा।
- जापान को भविष्य में सबसे महत्त्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक पार्टनर के रूप में देखा गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान रहा।

भारत के पड़ोसियों का महत्त्व:

- नई विश्व व्यवस्था में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी के बावजूद, युवाओं ने भारत के पड़ोस को सामरिक महत्त्व दिया।
- उत्तरदाताओं का मानना था कि भारत ने अपने पड़ोस को कुशलतापूर्वक परिभाषित किया है तथा सभी क्षेत्रों-सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति में पर्याप्त विदेश नीति का पालन किया है।

गैर-पारंपरिक और अंतर्राष्ट्रीय खतरे:

- गैर-पारंपरिक और अंतर्राष्ट्रीय खतरों को महत्त्वपूर्ण खतरों के रूप में देखा गया।
- महामारी को चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा संघर्ष की तुलना में भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती माना गया था।

आगे की राह:

पूरे क्षेत्र में राजनीतिक जुड़ाव, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए भारत को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में निवेश जारी रखने की जरूरत है। 91% उत्तरदाताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उपस्थिति का समर्थन किया।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. खाद्य सुरक्षा और मानक (आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ) विनियम, 2022

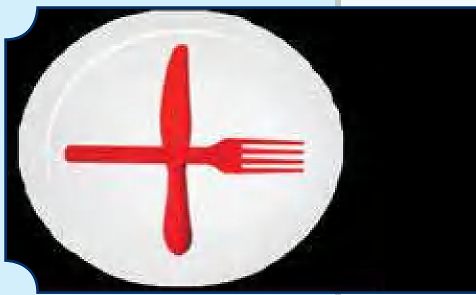

जीएमओ से उत्पादित किसी भी खाद्य या खाद्य सामग्री के निर्माण, पैक, स्टोर, बिक्री, बाजार या आयात की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। यदि जीएमओ को भोजन, बीज या अन्य पौधे-प्रसार सामग्री के उत्पादन के लिए भोजन या स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग किया जाना है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) से अनुमोदन आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA), 2006 के तहत नए नियम प्रस्तावित हैं और ये निम्न पर लागू होतें हैं:

- आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) जो भोजन के उपयोग हों।
- जीएमओ से उत्पादित खाद्य सामग्री जिसमें संशोधित डीएनए होता है।
- जीएमओ व्युत्पन्न सामग्री/योजक/प्रसंस्करण सहायक।

2. राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति

- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है।
- 2021 के दौरान भारत में लगभग 1.6 लाख आत्महत्याएं दर्ज की गई, जो 2020 की तुलना में 7.2% की वृद्धि दर्शाती हैं। पारिवारिक समस्याएं और बीमारी आत्महत्या के मुख्य कारण थे।

रणनीति के प्रमुख उद्देश्य:

- अगले तीन वर्षों के भीतर आत्महत्याओं के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना।
- अगले पांच वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करने वाले मनोरोग बाह्य रोगी विभागों की स्थापना करना।
- अगले आठ वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को एकीकृत करना।
- आत्महत्याओं की जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश विकसित करना और

3. ब्लैक नेप्ड तीतर कबूतर

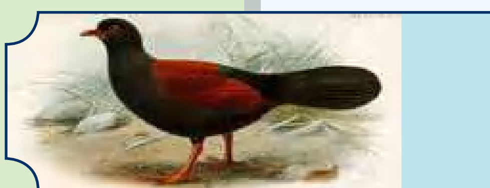

140 वर्षों तक नहीं देखे जाने के बाद, ब्लैक नेप्ड तीतर कबूतर को पापुआ न्यू गिनी में फिर से खोजा गया है। यह चौड़ी पूँछ वाला एक बड़ा, जमीन पर रहने वाला कबूतर है। यह आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों और निचले पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास रहते हैं। ये निचले इलाकों में भी पाए जाते हैं। यह न्यू गिनी और आसपास के द्वीपों के प्राथमिक वर्षा वनों में भी पाया जाता है। आईयूसीएन में यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आता है।

4. 2019 के पांच सबसे घातक बैक्टीरिया

द लांसेट अध्ययन के अनुसार, 2019 में भारत में पांच प्रकार के बैक्टीरिया के कारण लगभग 6.8 लाख मौतें हुई। ये बैक्टीरिया ई. कोलाई, एस. निमोनिया, के. निमोनिया, एस. ऑरियस और ए. बॉमनी हैं, जो शीर्ष 5 सबसे घातक जीवाणु रोगजनक हैं। अध्ययन से पता चलता है कि अकेले पांच बैक्टीरिया 2019 में वैश्विक स्तर पर सभी मौतों (77 लाख) के आधे से अधिक हेतु जिम्मेदार हैं। अकेले भारत में, 5 बैक्टीरिया रोगजनकों के कारण 6.8 लाख मौतें हुई। अध्ययन में पाया गया कि सबसे घातक जीवाणु रोगजनक, संक्रमण के प्रकार स्थान और उम्र के अनुसार भिन्न होते हैं। सामान्य जीवाणु संक्रमण 2019 में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण था, और विश्व स्तर पर आठ मौतों में से एक का कारण था।

5. गांधी मंडेला पुरस्कार

हाल ही में 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार 14वें दलाई लामा को प्रदान किया गया। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार शांति, समाज कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खेल, नवाचार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देकर महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के मूल्यों तथा आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है।

गांधी मंडेला फाउंडेशन:

गांधी मंडेला फाउंडेशन भारत का पंजीकृत ट्रस्ट है जो दुनिया भर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी वैश्विक उपस्थिति अमेरिका, अफ्रीका, रूस, लंदन, स्विट्जरलैंड, चीन, नेपाल, बांग्लादेश में भी हैं। इस फाउंडेशन ने महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए गांधीजी की 150वीं जयंती के दौरान गांधी मंडेला पुरस्कारों की स्थापना की। जूरी समिति में तीन देशों (भारत, नेपाल और बांग्लादेश) के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।

6. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल

- यह गैर-व्यक्तिगत डेटा को छोड़कर, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए डेटा सुरक्षा व्यवस्था के दायरे को कम करता है।
- व्यक्तिगत डेटा किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी डेटा है जो ऐसे डेटा से या उसके संबंध में पहचाना जा सकता है।
- बिल में डेटा संरक्षण बोर्ड की परिकल्पना की गयी है जो डाटा को संरक्षित करेगा।
- प्रस्तावित बिल सीमा पार डेटा प्रवाह पर रियायतें प्रदान करता है।
- यह भारत के बाहर के क्षेत्रों को सूचित करेगा जहां भारतीयों का डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है।
- गैर-अनुपालन, या डेटा उल्लंघन के लिए 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में राज्य एजेंसियों को छूट देने की अनुमति दी गयी है।
- सहमति प्रबंधकों को प्रस्तावित करता है, ताकि किसी व्यक्ति को डेटा फिड्यूशियरी के साथ उसके इंटरैक्शन के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखने में सक्षम बनाया जा सके।

7. विश्व नेताओं को भारत की पारंपरिक कलाकृतियाँ की गयी भेंट

G-20 शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं को भारत की पारंपरिक कलाकृतियाँ पाटन पटोला और माता नी पछेड़ी भेंट कीं।

पाटन पटोला (जीआई टैग गुजरात):

यह शुद्ध रेशम से बुने हुए डबल इकत या पटोला की प्राचीन कला है। यह उत्तर गुजरात में पाटन के क्षेत्र से 11वीं शताब्दी से विद्यमान है। रंगाई की तकनीक को 'बंधनी' प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसे गेंदा, प्याज की त्वचा, अनार आदि के प्राकृतिक अर्क से रंगा जाता है।

माता नी पछेड़ी:

यह गुजरात का हस्तनिर्मित कपड़ा है जिसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। यह एक धार्मिक कपड़ा लोक कला है जिसके केंद्र में देवी माँ की विशेषता है। उनकी कहानियाँ और किंवदंतियाँ शेष कपड़े को भरती हैं। यह प्राकृतिक रंगों के साथ आयताकार आकार का हाथ से पेंट किया हुआ कपड़ा है।

8. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) 2023

हाल ही में, जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रकाशित किया गया था। भारत को दुनिया के शीर्ष-5 देशों में स्थान दिया गया है और जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन पर G-20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2023 के अनुसार, भारत 2 स्थान की छलांग लगाकर अब 8वें स्थान पर है। भारत सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। किसी भी देश को पहली, दूसरी और तीसरी रैंक नहीं दी गई। डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को ही चार छोटे देश हैं जो भारत से ऊपर चौथे, पांचवें, छठे और सातवें स्थान पर हैं। CCPI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने 2030 के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर अग्रसर है।

9. लीड आईटी शिखर सम्मेलन

भारत और स्वीडन ने मिस्र के शर्म अल शेख में COP-27 के मौके पर लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। लीड आईटी पहल औद्योगिक क्षेत्र में निम्न कार्बन संक्रमण पर केंद्रित है। लीड आईटी को न्यूयॉर्क में 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के समर्थन से स्वीडन और भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा लॉन्च किया गया था। शिखर सम्मेलन का समापन लीडआईटी के सदस्यों द्वारा शिखर सम्मेलन के बयान को अपनाने के साथ हुआ, जिसने उद्योग के निम्न-कार्बन संक्रमण को जारी रखने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। सदस्य नए सदस्यों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

WORLD ECONOMIC FORUM

10. मास्को प्रारूप संवाद

रूस ने 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर परामर्श के मास्को प्रारूप की तीसरी बैठक की मेजबानी की। भारत बैठक में संयुक्त सचिव के रूप में मौजूद था।

- बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें वर्तमान मानवीय स्थिति तथा सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा चल रहे प्रयास, अंतर-अफगान वार्ता, एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार का गठन शामिल है।
- मास्को प्रारूप अफगानिस्तान पर कई संवाद प्लेटफार्मों में से एक है। जो काबुल पर तालिबान के अधिग्रहण से पहले शुरू हुआ था।
- इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत शामिल हैं।
- इस मास्को प्रारूप का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।

11. तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल

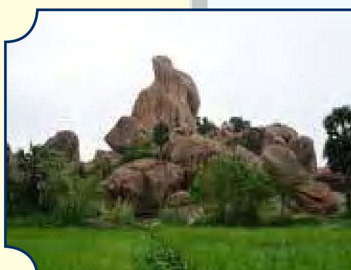

तमिलनाडु की राज्य सरकार ने हाल ही में जैविक विविधता अधिनियम, 2022 के तहत मदुरै जिले के अरट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) वे अधिसूचित क्षेत्र हैं जो अद्वितीय और पारिस्थितिक रूप से नाजुक स्थिति में हैं। ये प्रजातियों की समृद्धि, दुर्लभ, स्थानिक और खतरे वाली प्रजातियों, कीस्टोन प्रजातियों, विकासवादी महत्त्व की प्रजातियों आदि एक से अधिक घटकों की मेजबानी करने के लिए जाने जाते हैं। ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से और सांस्कृतिक पहलुओं जैसे पवित्र उपवनों/वृक्षों तथा स्थलों की उपयोगिता से भी महत्त्वपूर्ण होते हैं।

12. कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल

रोजगार मेले के तहत नियुक्त सभी लोगों के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल मिशन कर्मयोगी के तहत एक पहल है। मॉड्यूल के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में नए भर्ती हुए लोगों को ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाएगा।

- इससे नए सरकारी कर्मचारियों को नई भूमिका के अनुकूल होने के लिए आवश्यक आचार संहिता को समझने में मदद मिलेगी।
- कार्यस्थल में नैतिकता, सत्यनिष्ठा, मानव संसाधन नीतियां और अन्य लाभ, भत्ते आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर मॉड्यूल द्वारा ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य देश के लोगों के भीतर सिविल सेवाओं के सार को बिठाना है।

13. गुट्टी कोया जनजाति

हाल ही में तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में गुट्टी कोया आदिवासियों के एक समूह द्वारा एक वन रेंज अधिकारी (FRO) की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। गुट्टी कोया, कोया जनजाति की एक उप-जनजाति है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में रहती है। वे खुद को 'कोइटर' कहते हैं, जिसका अर्थ है लोग।

उनकी मातृभाषा कोया है जो एक द्रविड़ भाषा के अन्तर्गत आती है। वे उड़िया और तेलुगु भाषा भी बोल सकते हैं। कोया द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण मेला सम्मक्का सरलम्मा जात्रा है जो वारंगल जिले के मुलुग तालुक के मेदराम गांव में माघ मास (जनवरी या फरवरी) की पूर्णिमा के दिन दो साल में एक बार मनाया जाता है।

14. सी विजिल एक्सरसाइज 2022

सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण, अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास, नवंबर 2022 में समुद्री गतिविधियों में शामिल तट रक्षक और अन्य मंत्रालयों के साथ भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर के तटीय रक्षा अभ्यास की कल्पना 2018 में 26/11 के मुंबई हमलों के बाद से समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में शुरू किए गए विभिन्न उपायों के रूप में की थी। 'सी विजिल' अभ्यास का उद्देश्य पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करना और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करना है। सी विजिल अभ्यास का उद्घाटन संस्करण जनवरी 2019 में हुआ था। सी विजिल का दूसरा संस्करण जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था।

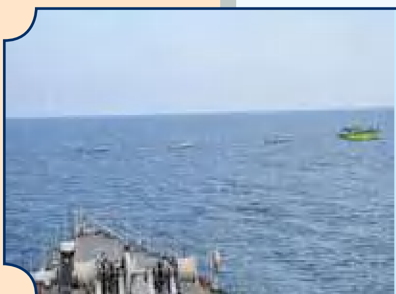

15. भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की एक पुस्तिका जारी की। श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी दर में केरल (837.3), जम्मू और कश्मीर (519) और तमिलनाडु शीर्ष (478) पर रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय औसत 323.2 रुपये है। कृषि और गैर-कृषि खंडों के मामले में भी, जिसके लिए डेटा उपलब्ध है, केरल शीर्ष भुगतानकर्त्ता था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश था। मध्य प्रदेश और गुजरात सबसे कम भुगतानकर्त्ता रहे हैं। निवेश औद्योगिक राज्य गुजरात और महाराष्ट्र निवेश आकर्षित करने में सबसे आगे हैं। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है।

यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार की जनसंख्या और घनत्व देश में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य बने रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कर्नाटक देश के सभी राज्यों की ग्रिड-इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता में सबसे ऊपर है जिसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू-कश्मीर में आयोजित हुआ।
2. सरस आजीविका मेला, 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुआ। सरस हथकरघा और हस्तशिल्प की भारतीय विरासत को बढ़ावा देने, इसमें ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, एसएचजी आदि को जोड़ने की एक पहल है।
3. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 26-28 नवंबर 2022 तक चौथी भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता की।
4. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ 'नई चेतना-पहल बदलाव की' शीर्षक से महीने भर चलने वाले राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की।
5. तीन दिवसीय इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 23 नवंबर से 25 नवंबर, 2022 तक मानेकशॉ सेंटर (नई दिल्ली) में आयोजित किया गया था।
6. केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर तीसरे वैश्विक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) का मुकाबला करने पर भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया।
7. भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान-भारत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की।
8. दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों को पछाड़ते हुए, यूपी ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद से महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक नई कंपनियों को जोड़ा है।
9. हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया।
10. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया।
11. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) ने पूर्वी तिमोर को समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है।
12. पाकिस्तान, घाना और बांग्लादेश जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन मुहैया कराने के लिए G-7 'ग्लोबल शील्ड' पहल से धन प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ताओं में से होंगे, कार्यक्रम की घोषणा मिस्र में COP-27 शिखर सम्मेलन में की गई थी।
13. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापा गया भारत का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 3.1 प्रतिशत बढ़ा, जो बिजली उत्पादन में दो अंकों की वृद्धि से समर्थित था।
14. भारत की खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापा जाता है, अक्टूबर में तीन महीने के निचले स्तर 6.77% पर आ गई, जो सितंबर में 7.41% से कम थी।
15. आईएनएस त्रिकंद ने उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन 'सी सोर्ड-2' में भाग लिया।
16. भारत में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स-III द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है।
17. लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में केरल टूरिज्म को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है।
18. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साह ने लोगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए एक नया पोर्टल 'अमर सरकार' लॉन्च किया।
19. विभिन्न संस्कृतियों के बीच सहिष्णुता का निर्माण करने और संदेश फैलाने के उद्देश्य से हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है ताकि सहिष्णुता को समाज का एक अभिन्न अंग बनाया जा सके।
20. इंडिया तथा मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्पन्न हुआ।

ऑनलाइन बॉन्ड प्रदाताओं हेतु सेबी फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

सूचीबद्ध ऋण इंस्ट्रूमेंट्स की बिक्री करने वाले ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म (OBP) के प्रदाताओं की सुविधा के लिए, पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक नियामक ढांचा पेश किया है।

प्रमुख बिंदु

- नए नियमों के अनुसार कोई भी स्टॉक ब्रोकर, सेबी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
- ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण मानदंड के साथ-साथ नियामक द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकने वाले किसी भी अतिरिक्त मानक का पालन करना होगा।
- यह देखते हुए कि सेबी-विनियमित मध्यस्थ प्लेटफॉर्म की आपूर्ति करेंगे। इस कदम से निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा, विशेष रूप से गैर-संस्थागत निवेशकों का।
- कोई भी व्यक्ति जो इस विनियम के प्रभावी होने की तारीख से पहले पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म का संचालन करता है। वह तीन महीने की अवधि के लिए ऐसा कर सकता है।

OBPs को विनियमित करने की आवश्यकता

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान, गैर-संस्थागत निवेशकों को ऋण प्रतिभूतियों की पेशकश करने वाले ओबीपी की संख्या में वृद्धि हुई है।
- उनमें से अधिकांश फिनटेक कंपनियां हैं या स्टॉक ब्रोकरों द्वारा समर्थित हैं।
- इसके अलावा, उनके माध्यम से लेनदेन करने वाले पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी उल्लेनीय वृद्धि हुई है।
- जहाँ ओबीपी निवेशक, विशेष रूप से गैर-संस्थागत निवेशक को बांड बाजार तक पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं। उनका संचालन सेबी के नियामक दायरे से बाहर था।
- बांड बाजार विकास के लिए, विशेष रूप से गैर-संस्थागत स्थान में विकास के लिए, अत्यधिक संभावनाएं प्रदान करता है।
- इसलिए, ऐसे ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म से संपर्क में रहने वाले निवेशकों के लिए संचालन और प्रकटीकरण में पारदर्शिता हेतु जांच तथा संतुलन की आवश्यकता है।

ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के बारे में

- नियामक के अनुसार एक ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म के अलावा होता है, जिस पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित ऋण प्रतिभूतियों की पेशकश की जाती है और उनका लेन-देन किया जाता है।
- इसके अलावा, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता का अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के प्लेटफॉर्म का संचालन प्रदान करता है।

बांड बाजार के बारे में

- बांड बाजार सभी ऋण प्रतिभूतियों के व्यापार और निर्गम के लिए सामूहिक शब्द है।
- सरकारें आम तौर पर कर्ज चुकाने के लिए पूंजी जुटाने या बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बांड जारी करती हैं, जबकि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां व्यापार विस्तार परियोजनाओं के वित्तपोषण या चल रहे संचालन को बनाए रखने के लिए बांड जारी करती हैं।

कार्बन बॉर्डर टैक्स

चर्चा में क्यों?

BASIC समूह, अर्थात् ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में भेदभावपूर्ण प्रथाओं और एकतरफा उपायों, जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्स आदि जो बाजार को विकृत करते हैं और पार्टियों के बीच विश्वास की कमी को बढ़ाते हैं, को नकारने का आह्वान किया।

कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में

- यूरोपीय संघ 2021 में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) लेकर आया था।
- यह एक योजना है जो 2026 से लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम तथा बिजली उत्पादन जैसे कार्बन-गहन उत्पादों पर कर लगाने का इरादा रखती है।
- कार्बन सीमा कर का अर्थ है किसी ऐसे देश में निर्मित वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाना जहां पर्यावरण नियमों में ढील हो, न कि इसे खरीदने वाले पर।

सीबीएएम की कार्यप्रणाली

- सीबीएएम योजना निम्नलिति तरीके से काम करती है:
- यूरोपीय संघ के आयातक उस कार्बन मूल्य के बराबर कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे, जिसका भुगतान उत्पादों के निर्माण के समय यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के अनुसार किया गया हो।
- इसके विपरीत, गैर-यूरोपीय संघ उत्पादक देश यह दिखा सकता है कि उन्होंने पहले ही किसी तीसरे देश से आयातित वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए गए कार्बन के लिए कीमत चुका दी है, तो यूरोपीय संघ के आयातक के लिए संबंधित लागत पूरी तरह से घटाई जा सकती है।

निष्कर्ष

- कार्बन सीमा कर, आयातित वस्तुओं पर कर लगाकर स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा दे सकता है।
- उभरती प्रौद्योगिकियों और वित्तपोषण के लिए उचित समर्थन के बिना, यह विकासशील देशों के लिए हानिकारक होगा।
- यह कर लागू होने की दशा में, भारत को फायदों और कमियों को देने की जरूरत है तथा इसके आंकलन के बाद यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय रूप से इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।

कार्बन बॉर्डर टैक्स पर भारत का रुख

- भारत ने, अन्य BASIC देशों की तरह विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर किए गए जिम्मेदारियों के अनुचित स्थानांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया है।
- भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों पर और अधिक बोझ नहीं डाल सकें, जबकि वे स्वयं जिम्मेदारियों से बचते रहें।
- भारत ने CoP-27 में कहा कि सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है और सिर्फ कोयला को विकसित देशों द्वारा लक्षित किया जा रहा है, जो कि भारत की उर्जा आपूर्ति का मुख्य स्रोत है।
- भारत के लिए संक्रमण का मतलब स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच करना नहीं है, बल्कि समय के साथ कम कार्बन वाली विकास रणनीति अपनाना है जो खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, विकास और रोजगार सुनिश्चित करता है, जिससे कोई भी पीछे नहीं रहता है।

समान योजनाओं वाले अन्य राष्ट्र

- यूरोपीय संघ के अलावा, अमेरिका में कैलिफोर्निया कुछ बिजली आयातों पर शुल्क लागू करता है।
- कनाडा और जापान समान संरचनाओं पर काम करने की योजना बना रहे हैं।

भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति

चर्चा में क्यों?

भारत ने शर्म अल-शेख (मिस्र) में आयोजित हुए कॉप-27 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) प्रस्तुत किया।

दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति के बारे में

- पेरिस समझौते 2015 के तहत, देशों को दो प्रकार की जलवायु कार्ययोजनाएं प्रस्तुत करनी थीं-
  - अल्पकालिक।
  - दीर्घकालिक।
- अल्पकालिक जलवायु रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) कहा जाता है जिसे हर पांच साल में प्रस्तुत किया जाता है।
- पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सभी प्रासंगिक मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों तथा नागरिक समाज संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति तैयार की जाती है।

प्रमुख विचार

भारत की दीर्घकालिक कम-कार्बन विकास रणनीति के 4 प्रमुख आधार हैं:

- दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत कम रहा है।
- विकास के लिए भारत की महत्त्वपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताएं हैं।
- भारत विकास के लिए कम-कार्बन रणनीतियों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है।
- भारत को जलवायु लचीलापन बनाने की जरूरत है।

भारत के सामने चुनौतियां

- वैश्विक कार्बन बजट।
- वित्त और प्रौद्योगिकी के संबंध में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विकसित देशों की विफलता।
- कृषि को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय शॉक।
- नेट-जीरो पर प्रतिबद्ध होने से:
  - गरीब भारतीय राज्यों के लिए राजस्व हानि।
  - रोजगार के अवसरों में कमी।

दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) की मुख्य विशेषताएं

क्षेत्रीय परिवर्तन:

- **एलटी**- एलईडीएस ने छह रणनीतिक क्षेत्रों जैसे- बिजली, परिवहन, शहरी, उद्योग, कार्बन डाइऑक्साइड हटाने और जंगलों को प्राथमिकता दी है।
  - **बिजली क्षेत्र**- अधिक नवीकरणीय ऊर्जा, मांग पक्ष में कमी और कोयले के फेज डाउन के लिए उचित बदलाव को प्राथमिकता दिया जा रहा है।
  - **परिवहन क्षेत्र**- भारत स्वच्छ ईंधन, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि और तेजी से विद्युतीकरण पर ध्यान दे रहा है।
  - **शहरी क्षेत्र**- इसमें भवनों की भौतिक दक्षता पर ध्यान दिया जाता है।
  - **औद्योगिक क्षेत्र**- यह ऊर्जा दक्षता, विद्युतीकरण, सामग्री दक्षता और हरित हाइड्रोजन में सुधार करने का लक्ष्य रखता है।
  - **कार्बन डाइऑक्साइड हटाना**- एलटी-एलईडीएस में इसका शामिल होना दर्शाता है कि भारत नई तकनीक के प्रयोग हेतु तत्पर है।
  - **वन**- भारत की मजबूत वन नीतियां हैं और वह अपने वनों की रक्षा करना जारी रखेगा। यह कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने के लिए वृक्षावरण का विस्तार करेगा।

वित्त और निवेश:

- काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के अनुसार, भारत को 2070 के शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए $10 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।

LiFE:

- LiFE मिशन भारत के नागरिकों, समुदायों, उद्योगों और दुनिया के नीति निर्माताओं को पर्यावरण के लिए एक जीवन शैली अपनाने का आह्वान है।
- LiFE बड़े जलवायु लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत योगदान के महत्त्व को बढ़ाता है।

भारतीय अवसंरचना पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक ने हाल ही में भारतीय बुनियादी ढांचे पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक है, 'भारत की बुनियादी ढांचे की जरूरतों का वित्तपोषण: वाणिज्यिक वित्तपोषण और नीतिगत कार्यवाही की संभावनाएं'।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- भारत को शहर के बुनियादी ढांचे में अपना औसत वार्षिक निवेश पिछले दस वर्षों में $10.6 बिलियन से बढ़ाकर $55 बिलियन प्रति वर्ष करना है जो अगले 15 वर्षों में कुल $840 बिलियन होगा।
- इसने नीतिगत कार्रवाइयों की शृखंला का आग्रह किया जिसमें केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए अधिक स्थिर, सूत्र आधारित तथा बिना शर्त वित्तीय व्यवस्था पर स्विच करना शामिल है।

नीतिगत हस्तक्षेप से जुड़े सुझाव

- शहरों की निवेश सहायता इकाई जैसी समर्पित संरचना का निर्माण।
- ये इकाइयां अवसंरचनात्मक वित्त पर ध्यान केंद्रित करती हैं। राज्य और शहरों को उनके अवसंरचनात्मक वित्तपोषण तथा प्रबंधन में सहायता कर सकती हैं।
- इसने निम्न द्वारा यूएलबी के वित्तपोषण के अवसरों में सुधार करने का सुझाव दिया:
  - अधिक निजी और वाणिज्यिक निवेशों को शामिल करना।
  - अधिक निजी भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करना।

भारत में बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति

- भारत में (ब्राजील के बाद) दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, क्योंकि 1990 के दशक की शुरुआत से आपूर्ति में समान वृद्धि के बिना 6% से अधिक की तेजी से वृद्धि हुई है।
- भारत में बुनियादी ढांचे के लिए धन की भारी कमी, जिसे सकल घरेलू उत्पाद के 5% से अधिक माना जाता है, देश की सबसे बड़ी चुनौती है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी में बाधाएं हैं:
  - भूमि अधिग्रहण,
  - प्रतिस्पर्धी बोली,
  - गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA)

अन्य अवलोकन

- रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक लगभग 600 मिलियन लोग भारतीय शहरों में रह रहे होंगे जो 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- इसने हरित, स्मार्ट, समावेशी और सतत शहरीकरण के लिए निजी प्लेयर की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

सरकारी निजी कंपनी भागीदारी

- वर्तमान शहरी अवसंरचना वित्तपोषण:
  - 75% केंद्र और राज्यों द्वारा किया जाता है।
  - 15% यूएलबी द्वारा अपने स्वयं के अधिशेष राजस्व के माध्यम से किया जाता है।
  - 5% निजी क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित हैं।
- शहरी बुनियादी ढाँचे में वार्षिक सरकारी निवेश $16 बिलियन (2018) से ऊपर है जो निजी निवेश की आवश्यकता को दर्शाता है।
- ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र के वित्तपोषण की वांछनीय राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
- भारत में 2011 और 2018 के बीच शहरी संपत्ति कर जीडीपी का 0.15% था जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए सामान्य 0.3-0.6% से कम है।
- नगरपालिका सेवाओं के लिए कम सेवा शुल्क भी निजी निवेश की वित्तीय

संविधान की मुख्य विशेषताएं

संविधान के बारे में

भारतीय संविधान अपनी तत्वों और भावना में अद्वितीय है। इसमें दुनिया के लगभग हर संविधान से ग्रहण की गई विशेषताएं हैं लेकिन भारत के संविधान में कई मुख्य विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधानों से अलग करती हैं।

सबसे लंबा लिखित संविधान

- संविधानों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
  - लिखित जैसे–भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूएस।
  - अलिखित जैसे–यूके, न्यूजीलैंड और इजराइल।
- भारतीय संविधान के विस्तृत होने के प्रमुख कारण:
  - **भौगोलिक कारक:** देश की विशालता और विविधता के कारण।
  - **ऐतिहासिक कारक:** सरकार के प्रभाव के कारण।
  - 1935 का भारत शासन अधिनियम।
  - केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एकल संविधान।
  - संविधान सभा में विधि विशेषज्ञों की प्रमुखता।

विभिन्न स्त्रोतों का प्रभाव

- **भारत शासन अधिनियम, 1935:** संघीय तंत्र, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान तथा प्रशासनिक विवरण।
- **ब्रिटिश संविधान:** संसदीय शासन व्यवस्था, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख और द्विसदनीयता।
- **अमेरिकी संविधान:** मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद।
- **आयरलैंड का संविधान:** राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि।
- **जापान संविधान:** विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

एकात्मक की ओर झुकाव

एकात्मक की ओर झुकाव एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं, आपातकालीन प्रावधानों आदि द्वारा देखा जा सकता है।

मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान का भाग 3, छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।

सरकार का संसदीय स्वरूप

संसदीय प्रणाली को सरकार के 'वेस्टमिंस्टर' मॉडल, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के रूप में भी जाना जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं हैं:

- नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति।
- बहुमत वाले दल का शासन।
- विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी।
- मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं।
- प्रधानमंत्री का नेतृत्व।
- केवल निचला सदन (लोकसभा) भंग होता है।

संघीय व्यवस्था

भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता शामिल हैं।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए हैं। इनका लक्ष्य भारत में एक 'कल्याणकारी राज्य' स्थापित करना है।

नम्यता तथा अनम्यता के गुण

- अनुच्छेद–368 के तहत संविधान में 2 तरह से संशोधन किया जा सकता है।
- केशवानंद भारती केस (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद–368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन यह संविधान के 'मूल ढांचे' को नहीं बदल सकती है।

भारत ऑस्ट्रेलिया-ETCA

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) की पुष्टि की। यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह एक दशक से अधिक समय के बाद विकसित देश के साथ भारत के लिए इस तरह का पहला समझौता है।

ETCA के उद्देश्य

- इस सौदे में अगले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लगभग $50 बिलियन तक बढ़ाने की क्षमता है।
- इससे स्टार्ट-अप अर्थव्यवस्था में कम से कम 10 लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है।
- यह ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों को 1.4 बिलियन उपभोक्ताओं के विशाल भारतीय बाजार का दोहन करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरी ओर, यह भारतीय निर्यातकों को अपने मूल्य वर्धित उत्पादों के विपणन का अवसर प्रदान करता है।
- यह अन्य विकसित देशों के साथ भविष्य के एफटीए के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंध

- भारत, ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जबकि ऑस्ट्रेलिया, भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- 2021 तक ऑस्ट्रेलिया के निर्यात और आयात में भारत की हिस्सेदारी क्रमशः 3.7 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत है। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार वर्तमान में लगभग 25 बिलियन डॉलर है।
- भारत मुख्य रूप से कच्चे माल का आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया से इसके 82 प्रतिशत आयात में कोयला, सोना, तांबा अयस्क, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, मैंगनीज अयस्क आदि शामिल हैं।
- ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात का 72 प्रतिशत निर्मित सामान जैसे- पेट्रोलियम, औषधियां, हीरे, आभूषण, रेलवे कोच और वाहन, मिल्ड चावल तथा शाकनाशी हैं।
- दोनों देश जापान के अलावा त्रिपक्षीय आपूर्ति शृंखला लचीलापन पहल (SCRI) में भागीदार हैं।

एफटीए का महत्त्व

- आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- निर्यातकों और आयातकों के लिए नए बाजार खोलना।
- विदेशी निवेश के अवसर सृजित करना।
- घरेलू उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और सरकारी सहायता पर उनकी निर्भरता कम करना।
- स्थानीय उद्योगों के लिए सब्सिडी पर खर्च कम करने में सरकारों की मदद करना।

ETCA का विवरण

- इंडिया-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए से बिना किसी प्रतिबंध के 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त हो जाएगा। भारत के श्रम प्रधान निर्यात जैसे कपड़ा और परिधान, कृषि और मछली उत्पाद, चमड़ा, जूते तथा फर्नीचर, कई इंजीनियरिंग उत्पाद, आदि को लाभ होगा, जो अब तक ऑस्ट्रेलिया में 4-5 प्रतिशत आयात शुल्क प्राप्त करता है।
- यह समझौता ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उत्पादों की 6,000 से अधिक व्यापक श्रेणियों तक शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करेगा।
- फार्मास्यूटिकल्स- यह ऑस्ट्रेलिया को पेट्रोलियम उत्पादों के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात है। इस सौदे से इसके निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा।
- कोयला- भारत के 24 अरब डॉलर के कुल कोयला व्यापार घाटे में से ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा 11 अरब डॉलर है। इस सौदे से कोयले को भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण इनपुट बनाने की संभावना है।
- ऑस्ट्रेलिया, भारतीय वाइन के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देगा, जबकि भारत ऑस्ट्रेलियाई वाइन पर आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत करेगा।
- सेवा क्षेत्र- इस सौदे में लगभग 135 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। यह योग शिक्षकों और भारतीय रसोइयों के लिए 1,800 का वार्षिक कोटा प्रदान करता है और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारत के एक लाख से अधिक छात्रों के लिए प्रतिबद्धता प्रदान करता है।
- पण्य वस्तु व्यापार- इस सौदे से 2026-27 तक द्विपक्षीय व्यापार निर्यात में 10 बिलियन डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है।
- व्यापार समझौता आईटी/आईटीईएस से संबंधित लंबे समय से लंबित दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) को भी हल करता है जिससे सालाना 200 मिलियन डॉलर की बचत होगी।

आगे की राह

व्यापार सौदा भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में मील का पत्थर साबित होगा जो न केवल आपसी सहयोग को बढ़ाएगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 अधिसूचित किया जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा।

अनुप्रयोग

ये नियम ई-अपशिष्ट या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण, बिक्री, स्थानांतरण, खरीद, नवीनीकरण, विंडन, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण में शामिल सभी निर्माता, रिफर्बिशर, डिस्मेंटलर और रिसाइकलर पर लागू होंगे।

ई-अपशिष्ट का भंडारण

- प्रत्येक निर्माता, रिफर्बिशर और पुनर्चक्रणकर्ता ई-अपशिष्ट को अधिकतम 180 दिनों की अवधि के लिए भंडारित कर सकते हैं।
- वह ई-कचरे की बिक्री, हस्तांतरण और भंडारण का रिकॉर्ड रखेगा। इन रिकॉर्ड को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा और ई-कचरे का भंडारण उस समय लागू नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

प्रतिबंध

सरकार ने रेडियोधर्मी सामग्री के संपर्क में आने के कारण बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।

पुनर्चक्रण

- विनिर्माता ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे ताकि अंतिम उत्पाद को पुनर्चक्रण योग्य बनाया जा सके।
- निर्माता यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाए गए पुर्जे एक-दूसरे के अनुकूल हों ताकि ई-कचरे की मात्रा कम हो सके।

ई-कचरे का परिवहन

किसी उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा के अंतिम निपटान के लिए निर्धारित विनिर्माण या पुनर्चक्रण से उत्पन्न कचरे का परिवहन खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के प्रावधानों का पालन करेगा।

भारत में ई-कचरे से संबंधित मुद्दे

- **उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा:** भारत लगभग 1.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ई-कचरे का उत्पादन करके विश्व में पांचवें स्थान पर है।
- **बाल श्रम की भागीदारी:** भारत में 10–14 आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बाल श्रमिक विभिन्न यार्डों और रीसाइक्लिंग कार्यशालाओं में पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा-उपकरणों के बिना विभिन्न ई-कचरा गतिविधियों में लगे हुए हैं।
- **अप्रभावी कानून:** अधिकांश एसपीसीबी/पीसीसी वेबसाइटों पर किसी भी सार्वजनिक सूचना का अभाव है। अधिकांश पीसीबी/पीसीसी की वेबसाइटों पर ई-कचरे से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, जो उनके प्रमुख सार्वजनिक इंटरफेस पॉइंट्स हैं।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** वर्तमान पुनर्चक्रण तथा संग्रह सुविधाओं और उत्पन्न होने वाले ई-कचरे की मात्रा के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पुनर्चक्रण सुविधाओं का अभाव है।
- **स्वास्थ्य को खतरा:** ई-कचरे में 1,000 से अधिक जहरीले पदार्थ होते हैं, जो मिट्टी और भूजल को दूषित करते हैं। एक्सपोजर से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, उल्टी और आंखों में दर्द हो सकता है। रिसाइकल करने वालों को लिवर, किडनी और तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं।
- **प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव:** असंगठित क्षेत्र के लिए ई-कचरे को संभालने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। ई-कचरे को संभालने के लिए कुछ कर रहे उत्पादकों के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं।
- **कम जागरूकता और संवेदनशीलता:** उपक करने के बाद निपटान के संबंध में सीमित पहुंच और जागरूकता।
- **ई-कचरे का आयात:** भारत में अपशिष्ट उपकरणों का आयात किया जाता है। विकसित देशों में उत्पन्न ई-कचरे को भारत, चीन, घाना और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों में पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है।
- **अधिकारियों की अनिच्छा:** नगरपालिकाओं की गैर-भागीदारी सहित ई-कचरा प्रबंधन और निपटान के लिए जिम्मेदार विभिन्न प्राधिकरणों के बीच समन्वय का अभाव।
- **सुरक्षा निहितार्थ:** जीवन के अंत वाले कंप्यूटरों में अक्सर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाते के विवरण होते हैं, जिन्हें अगर हटाया नहीं जाता है तो धोखड़ी का अवसर छोड़ देते हैं।

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

01. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करते हुए, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) निम्नलिखित मे से किन कारकों को देखता है?

1. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बाजार मूल्य रुझान
2. उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर एमएसपी के संभावित प्रभाव
3. उत्पादन की लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 30 प्रतिशत
4. अंतर-फसल मूल्य समता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

02. सरायघाट की लड़ाई:

(a) मराठों और राजपूतों के बीच लड़ी गई थी
(b) मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी
(c) मराठा और अफगान के बीच लड़ी गई थी
(d) मराठा और अहोम साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी

03. शिग्मो, एक फसल उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है:

(a) गोवा में (b) असम में
(c) महाराष्ट्र में (d) त्रिपुरा में

04. जापी, जोराई और गामोसा मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़े हैं?

(a) मणिपुर (b) नागालैंड
(c) असम (d) मिजोरम

05. निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय रेलवे में कुछ परिचालनों के निजीकरण का सुझाव दिया?

(a) उषा थोराट समिति
(b) एन गोपालस्वामी समिति
(c) सुभाष गर्ग समिति
(d) विवेक देबरॉय समिति

06. रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब होगा:

1. आयात और निर्यात दोनों के लिए रुपये में भुगतान
2. विश्व स्तर पर जारी बांडों के लिए रुपये में भुगतान
3. केंद्रीय बैंकों द्वारा पूरी दुनिया में भारतीय रुपये को आरक्षित मुद्रा के रूप में जमा/संग्रहित करना

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

07. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. WPI केवल वस्तुओं से संबंधित है, सेवाओं से नहीं।
2. WPI, वस्तुओं के थोक मूल्यों की औसत गति को देखता/पकड़ता है और मुख्य रूप से GDP अपस्फीतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है।
3. WPI में विनिर्मित वस्तुओं का भार अधिक होता है और CPI में खाद्य वस्तुओं का भार अधिक होता है।
4. RBI मौद्रिक नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से WPI को मुख्य मीट्रिक मानता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 3
(c) 1, 3 और 4 (d) 2, 3 और 4

08. भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द कनाल और मरला का अर्थ है:

(a) सिंचाई प्रणाली
(b) वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रकार
(c) भूमि माप की इकाइयाँ
(d) मुद्रा की इकाइयाँ

09. यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से किन रूपों में हो सकती है?

1. मौखिक परंपराओं और अभिव्यक्तियों में
2. सामाजिक प्रथाओं में
3. प्रकृति से संबंधित ज्ञान और अभ्यासों में
4. पारंपरिक शिल्प कौशल में

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 और 4 (b) 1 और 4
(c) 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

10. राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2019 ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को निम्नलिखित में से किस/किन मामले/मामलों की जांच करने का अधिकार दिया है?

1. विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों से जुड़े आतंकवादी मामले
2. साइबर अपराध के मामले
3. मानव तस्करी के मामले

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित में से कौन से शहर सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के महानगर थे?

1. गनवेरीवाला
2. राखीगढ़ी
3. धोलावीरा
4. हड़प्पा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 3 और 4 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

12. धोलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यहाँ की दीवारें कई अन्य हड़प्पा स्थलों में मिट्टी की ईंटों के बजाय बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बनी थीं।
2. धोलावीरा में मनुष्यों के व्यापक नश्वर अवशेष खोजे गए हैं।
3. यह शेल और अर्ध-कीमती पत्थरों से बने आभूषणों के निर्माण का भी केंद्र था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कई बदलावों से गुजरने के बाद, 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था।
2. 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के दौरान भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

14. ऑफ-बजट उधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ऑफ-बजट उधार, देश के राजकोषीय घाटे को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने में मदद करता है।
2. ऑफ-बजट उधार, राजकोषीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं है और इसका कोई राजकोषीय निहितार्थ नहीं है।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ऑफ-बजट खर्चों को निधि (फण्ड) देने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उत्तरी हिंद महासागर में दुनिया के एक चौथाई उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं।
2. भारतीय उपमहाद्वीप पर उष्णकटिबंधीय तूफानों का प्रभाव, घनी आबादी और कम समय में बड़ी मात्रा में वर्षा को अवशोषित करने की खराब क्षमता के कारण काफी गंभीर होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

16. ब्राह्मणी नदी बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ब्राह्मणी गंगा नदी की सहायक नदी है।
2. बैतरणी नदी के साथ मिलकर यह बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक बड़ा डेल्टा बनाती है।
3. यह मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) केवल 2

17. समुद्र के स्तर में वृद्धि मुख्य रूप से होती है:

1. गर्म समुद्र के पानी के विस्तार के कारण
2. भूमि पर हिमनदों के पिघलने के कारण
3. ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

18. निम्नलिखित में से किस/किन स्थिति/स्थितियों में हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत से मानसून वापस आ गया है?

1. यदि क्षेत्र में लगातार तीन दिनों तक वर्षा गतिविधि बंद रहती है।
2. निचले क्षोभमंडल के ऊपर एक प्रति-चक्रवाती हवा बन जाती है और नमी की मात्रा में काफी कमी आती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जब जियोमैग्नेटिक रिवर्सल होता है, तो समुद्री कछुए जैसे नेविगेशन के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने वाले जानवर, अपनी नियमित यात्रा के दौरान खो सकते हैं।
2. जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, समुद्री कछुओं की आनुवांशिक विविधता के लिए खतरा बन सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

20. सूखे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सूखा, समय की एक विस्तारित अवधि में वर्षा की मात्रा में प्राकृतिक कमी का परिणाम है, आमतौर पर एक मौसम या उससे अधिक समय में।
2. सूखा अक्सर उच्च हवाओं, उच्च तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता से जुड़ा होता है।
3. कृषि सूखा तब होता है जब उपलब्ध मिट्टी की नमी, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए अपर्याप्त होती है और अत्यधिक तनाव और कमजोर पड़ने का कारण बनती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) केवल 1

21. केन्द्र-राज्य संबंधों को सुधारने के लिये पुंछी आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी अनुशंसाएँ की गई है/हैं?
1. त्रि-भाषा फॉर्मूले को इसकी मूल भावना के साथ लागू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
2. राज्यपाल को पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए तथा केन्द्र सरकार की इच्छा पर उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए।
3. नई अखिल भारतीय सेवाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और न्यायिक क्षेत्र में सृजन किया जाना चाहिए।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

22. निम्नलिखित में से कौन-से अपराध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आते हैं?
1. बैंकिंग धोखाधड़ी
2. विदेशी विनिमय उल्लंघन
3. सांस्कृतिक सम्पत्ति की तस्करी
4. वन्य जीवों का अवैध शिकार
5. आतंकी हमलों की घटनाएँ
6. दवाओं और खाद्य पदार्थों में मिलावट

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2, 3 और 5
(c) केवल 3, 4, 5 और 6
(d) केवल 1, 2, 3, 4 और 6

23. 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इनका उद्देश्य देश में 'राजनीतिक लोकतंत्र' की स्थापना करना है।
2. न्यायालय इस आधार पर किसी कानून की वैधता को बनाए रख सकता है कि यह निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था।
3. यह व्यक्ति के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

24. निम्नलिखित याचिकाओं में से कौन PIL के रूप में वर्णित विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आती हैं?
1. पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने से मना करने के विरूद्ध याचिका
2. पारिवारिक पेंशन के मामले
3. मकान मालिक-किरायेदारों के मामले
4. मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन से संबंधित मामले

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 1, 2 और 3

25. अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक संगठन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. विकास के उच्चतर स्तर पर जीडीपी में सेवा क्षेत्रक का अंशदान अन्य दो क्षेत्रकों से अधिक होता है।
2. 1991 के बाद की अवधि में भारत में सेवा क्षेत्रक की भागीदारी अन्य विकसित देशों की भांति रही है।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्रक की कभी भी सर्वाधिक भागीदारी नहीं रही है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

26. बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केन्द्रीय बैंक देश की मुद्रा सृजन का अनन्य स्रोत है।
2. वाणिज्यिक बैंक भी अर्थव्यवस्था की मुद्रा सृजन प्रणाली का भाग हैं।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

27. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

विनिमय दर के प्रकार		प्रावधान
1. LERMS	:	भारत में प्रवाहित विनिमय दर की शुरूआत
2. NEER	:	संभारों के समायोजन को शामिल करना
3. REER	:	विनिमय दर का भारित औसत

उपर्युक्त दिये गये युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

28. नैनो-तकनीकी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रोग्राम योग्य पदार्थ वे हैं जिनकी प्रकृति प्रतिवर्तनीय होती है।
2. नैनो पदार्थ वे हैं जो प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

29. जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दोनों अपने शुरूआती दौर में वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे।
2. दोनों ही व्यापार-वाणिज्य को बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे।
3. दोनों ने ही ब्याज लेकर जीवनयापन करने वाले लोगों की आलोचना की।

जैन और बौद्ध धर्म के बीच उपर्युक्त समानताओं में से कौन-सा/ से सही है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 1 और 3

30. निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता और मिश्र की सभ्यता के बीच कौन-सा/से अंतर सही है/हैं?
1. मिस्त्र की सभ्यता में पुत्री, पैतृक संपत्ति या शासन की उत्तराधिकारी होती थी लेकिन हड़प्पा समाज में इस प्रवृत्ति को नहीं देखा गया।
2. मिस्त्र की सभ्यता की तुलना में हड़प्पा सभ्यता में पत्थरों पर कलाकारी बड़े पैमाने पर की गई है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

31. प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की वास्तुकला विशेषताओं के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मौर्यकालीन वास्तुकला पर पर्शियन और ग्रीक दोनों के ही प्रभाव दिखाई देते हैं।
2. सांची स्तूप के प्रवेश द्वार को फूलों के रूपांकन से सजाया गया है।
3. गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों को ग्रीक भगवान की तरह बनाया गया है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 3 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 1 और 3

32. निम्नलिखित में से कौन से मंदिर पल्लव शासकों के शासनकाल में निर्मित हुए थे?
1. तट (शोर) मंदिर
2. वैंकुंठ पेरूमल मंदिर
3. कैलाशनाथ मंदिर
4. बृहदेश्वर मंदिर

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 1, 2 और 3

33. प्रारंभिक-मध्यकालीन समय के दौरान भारत के लोगों की स्थिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. भारतीय हस्तशिल्प कला के उच्च मानकों में कोई गिरावट नहीं थी।
2. भारतीय कृषि में लगातार गिरावट शुरू हो गई थी।
3. लड़कियों की विवाह योग्य आयु में वृद्धि हुई थी जबकि महिलाओं को वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 1 और 3

34. भारत में क्रिप्स मिशन भेजने के कारणों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. भारत पर जापान के आक्रमण के भय ने मित्र राष्ट्रों के लिए भारत के समर्थन को निर्णायक बना दिया।
2. भारतीय राष्ट्रवादी मित्र राष्ट्रों को किसी भी कीमत पर सहायता देने हेतु तैयार नहीं थे।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

35. ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. इस अधिनियम के अंतर्गत ट्रेड यूनियन को विधिक संघ के रूप में मान्यता दी गई।
2. इसमें ट्रेड यूनियन की गतिविधियों के विनियमन एवं पंजीकरण की शर्तों को शामिल किया गया।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

36. विभिन्न महाद्वीपों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल भू-क्षेत्र का एक तिहाई है।
2. केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है।
3. केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

37. निम्नलिखित स्थितियों में से कौन 'डेडवेट लॉस' आय को निरूपित करती है/हैं?
1. जब कीमत बहुत अधिक होती है, तो लोगों की जरूरतों की तुलना में बिक्री के लिए उत्पाद की मात्रा अधिक होती है।
2. जब कीमत बहुत कम होती है, तो उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पादों की तुलना में उपभोक्ताओं की मांग अधिक होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

38. निम्नलिखित निरर्हताओं के आधार पर कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता या बने हुए सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यहाँ आप उन निर्हर्ताओं को बताये जिनका निर्धारण अंतिम रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है?
1. वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो।
2. उसे किसी अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो।
3. वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया है।

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

39. यदि आप उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं परंतु आप के मोहल्ले में लोगों का एक समूह सरकार द्वार बनाये गये किसी कानून के विरोध में धरना दे रहे हैं, जिसके कारण आप अपने विश्वविद्यालय जाने में असमर्थ हैं साथ ही मोहल्ले में भारी शोर का माहौल है। इस स्थिति में संविधान द्वारा दिए गये आप के किस/किन अधिकार/अधिकारों का हनन हो रहा है?
1. अनुच्छेद 19(1)(d)
2. अनुच्छेद 21(a)
3. अनुच्छेद 21

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

40. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से कथन भारतीय संविधान की सीमाओं को बताता/बताते है/हैं?
1. भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है।
2. भारतीय संविधान में लैंगिक न्याय के कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों विशेषकर परिवारों से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है।
3. इसमें कुछ बुनियादी सामजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के बजाय राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है।

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

41. संविधान सभा द्वारा लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रणाली को अस्वीकार करने का/के कारण है/हैं?

1. मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया समझने में कठिनाई होना।
2. बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की स्थिरता।
3. यह काफी खर्चीली व्यवस्था है।
4. यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती।

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

42. G20 समूह के देशों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. वैश्विक जीडीपी में इसके सदस्यों की भागीदारी 80% से अधिक है, साथ ही वैश्विक व्यापार में 75% तथा वैश्विक जनसंख्या में 60% से अधिक है।
2. इस समूह का प्रमुख उद्देश्य एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का निर्माण करना है।
3. भारत इस समूह का संस्थापक सदस्य है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 3 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

43. निम्नलिखित मिशन में से कौन सा/से मिशन अन्तरिक्ष में शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए प्रारंभ किया/किये गया/गये है/हैं ?

1. वेनेरा श्रंखला
2. मेरिनर श्रंखला
3. मैगलन मिशन
4. वीनसकाई मिशन

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 4 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

44. निम्नलिखित में से कौन सी नैरोबैंड इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (NB-IOT) की विशेषता(एँ) है/हैं?

1. यह इन्टरनेट ऑफ थिंग्स हेतु एक वायरलेस संचार मानक है, यह लोकल एरिया नेटवर्क की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
2. यह उन उपकरणों को कनेक्ट करने में सहयोग करता है जिनके लिए कम डेटा तथा लो-बैंडविथ की आवश्यकता होती है।
3. इनका संचालन उन LTE बेस स्टेशनों पर किया जाता है जहाँ से NB-IOT संचालन के लिए संसाधन ब्लाक आवंटित किया जा सकता हो।

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

45. भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इन्होंने मोड्यूलर फंक्शन को प्रस्तुत किया जिसका उपयोग सैद्धान्तिक भौतिकी के स्ट्रिंग थ्योरी में किया जाता है।
2. भारत में इनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है।
3. इन्होंने हाइपरज्यामिति श्रेणी, रिमान श्रेणी, इलिप्टिकल इंटीग्रल, अपसारी श्रेणी के सिद्धांत और जीटा फंक्शन के कार्यात्मक समीकरण जैसे विषयों पर कार्य किया।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

46. टोकामैक क्या है?

(a) संलयन की ऊर्जा का दोहन करने के लिए अभिकल्पित एक प्रायोगिक चुम्बकीय संलयन उपकरण।
(b) मैक संख्या 10 वाली हाइपरसोनिक मिसाइल।
(c) S400 की क्षमता वाली मिसाइल।
(d) नाभिकीय हथियार ले जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल।

47. प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. यह कर शेयर, बांड, ऋण पत्र, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फण्ड आदि पर लागू होता है।
2. यह सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होता है।
3. इसका उद्देश्य कर परिहार (Tan avoidance)को प्रोत्साहित करना तथा कराधान का विस्तार करना है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

48. निम्नलिखित में से कौन अनुबंध कृषि का/के प्रभाव है/हैं?

1. यह उत्पादन, मूल्य और विपणन लागतों के जोखिमो को कम करती है।

2. यह नये बाजार खोलने का वातावरण तैयार करती है।
3. यह छोटे पैमाने पर कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाती है।
4. यह किसानों का शोषण करती है।

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 4 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

49. निम्नलिखित में से किस स्थिति में राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा बराबर हो सकता है?

(a) यदि राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों के बराबर हो जाये।
(b) यदि पूंजीगत व्यय, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के बराबर हो जाये।
(c) ऐसी स्थिति संभव नहीं है।
(d) यदि पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों के बराबर हो जाये।

50. निम्नलिखित में से किस/किन के द्वारा भारत में बफर स्टॉक ऑपरेशन संचालित किया जाता है?

1. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा
2. भारतीय खाद्य निगम द्वारा
3. लघु किसान कृषि व्यापार संघ द्वारा
4. मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति द्वारा

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 4 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर

1.	(c)	18.	(b)	35.	(c)
2.	(b)	19.	(c)	36.	(c)
3.	(a)	20.	(b)	37.	(c)
4.	(c)	21.	(c)	38.	(b)
5.	(d)	22.	(d)	39.	(c)
6.	(d)	23.	(b)	40.	(d)
7.	(a)	24.	(c)	41.	(b)
8.	(c)	25.	(d)	42.	(d)
9.	(d)	26.	(c)	43.	(c)
10.	(d)	27.	(a)	44.	(c)
11.	(d)	28.	(c)	45.	(d)
12.	(b)	29.	(d)	46.	(a)
13.	(a)	30.	(a)	47.	(b)
14.	(a)	31.	(d)	48.	(c)
15.	(b)	32.	(d)	49.	(b)
16.	(c)	33.	(a)	50.	(d)
17.	(d)	34.	(a)		

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. डिजिटल शक्ति अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

A- महिलाओं में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना
B- महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना
C- माताओं की शारीरिक फिटनेस
D- महिलाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाना

उत्तर- (B)

2. हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है?

A- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार इकाई
B- पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट, यू.एस
C- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
D- यूनेस्को

उत्तर- (B)

3. 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह सम्मेलन कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में संपन्न हुआ है।
2. भारत का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया।
3. इस वर्ष आसियान-भारत संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई।
4. मानव संसाधन, डी-माइनिंग और विकास परियोजनाओं, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट कृषि, पर्यटन आदि पर व्यापक चर्चा की।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A- 1, 2 और 3
B- 3 और 4
C- 1, 2 और 4
D- केवल 3

उत्तर : (C)

4. ADMM-Plus की उद्घाटन बैठक का आयोजन किया गया था

A- हनोई
B- ब्रुनेई
C- सिएम रीप
D- मलेशिया

उत्तर- (C)

5. 'ड्रग फ्री चाइल्डहुड का अधिकार' पर वैश्विक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसका आयोजन यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) के सहयोग से फोर्थ वेव फाउंडेशन द्वारा किया गया था।
2. यह गुजरात में आयोजित किया गया था।
3. नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A- 1 और 3
B- 2 और 3
C- केवल 1
D- 1, 2 और 3

उत्तर- (A)

6. ऑपरेशन बरखाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इस विद्रोही-विरोधी ऑपरेशन को 1 अगस्त 2014 को शुरू किया था।
2. इसका उद्देश्य साहेल क्षेत्र में गैर-राज्य सशस्त्र समूहों के पुनरुत्थान को रोकने में स्थानीय सशस्त्र बलों की सहायता करना था
3. इसका नेतृत्व अमेरिकी सेना द्वारा किया जा रहा था।
4. 9 नवंबर, 2022 को समाप्त कर दिया है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A- 1, 2 और 3
B- 3 और 4
C- 1, 2 और 4
D- केवल 3

उत्तर- (C)

7. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल हो सकता है?

A- केवल निवासी भारतीय नागरिक
B- केवल 21 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति
C- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की तारीख के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारी
D- 1 अप्रैल, 2004 को या उसके बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों सहित सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी

उत्तर- **(C)**

8. घरेलू बैंक द्वारा विदेशी बैंक के लिए बनाए गए स्थानीय मुद्रा खाते को कहा जाता है:

A- वोस्त्रो खाता

B- नोस्ट्रो खाता
C- लोरो खाता
D- उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- (A)

9. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एनएफआरए एक संवैधानिक निकाय है।
2. इसके खाते की निगरानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।
3. यह कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखापरीक्षा नीतियों की सिफारिश करती है।

सही विकल्प चुनें।

A- 1, 2 और 3 B- 2 और 3
C- 1 और 2 D- केवल 3

उत्तर- (B)

10. हाल ही में जारी ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

1. भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2015 में जारी किया गया था।
2. परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने से आय जुटाई जा सकती है।
3. भारत में, सेबी ग्रीन बॉन्ड के मानदंडों को नियंत्रित करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

A- 1, 2 और 3 B- 1 और 2
C- 1 और 3 D- केवल 3

उत्तर- (D)

11. वांगला महोत्सव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वांगला महोत्सव उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है।
2. यह गर्मी के आगमन का प्रतीक है।
3. इसे 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है।
4. यह मेघालय राज्य के गारो समुदाय के बीच सबसे लोकप्रिय है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A- 1, 2 और 3 B- 2 और 4
C- केवल 2 D- 1, 3 और 4

उत्तर- (D)

12. भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते, ईसीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं?

A- इजराइल
B- यूनाइटेड किंगडम
C- ऑस्ट्रेलिया
D- इंडोनेशिया

उत्तर- (C)

13. कार्बन बॉर्डर टैक्स कार्बन-गहन उत्पादों पर कर लगाने की एक योजना है, किसके द्वारा प्रस्तावित है?

A- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
B- यूरोपीय संघ (EW)
C- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC)
D- विश्व व्यापार संगठन (WTO)

उत्तर- B

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. नार्कोएनालिसिस परीक्षण में, अभियुक्त के शरीर में एक दवा इंजेक्ट की जाती है, जो उन्हें एक कृत्रिम निद्रावस्था या बेहोश अवस्था में ले जाती है, जिसमें उनकी कल्पना को बेअसर कर दिया जाता है।
2. एक पॉलीग्राफ टेस्ट इस धारणा पर आधारित होता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो शारीरिक प्रतिक्रियाएं पहले की अपेक्षा अलग-अलग होती हैं
3. नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट दोनों ही वैज्ञानिक रूप से 100% सफलता दर साबित हुए हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 2 B- 1, 2
C- 2, 3 D- 1, 2, 3

उत्तर- B

15. नो मनी फॉर टेरर (NMFT) सम्मेलन एक पहल के रूप में है

A- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
B- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)
C- विश्व बैंक
D- उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- B

16. निम्नलिखित में से किस मिशन का उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना है?

A- चंद्रयान -3
B- पार्कर मिशन
C- आर्टेमिस मिशन
D- ओसिरिस-रेक्स मिशन

उत्तर- C

व्यक्तित्व

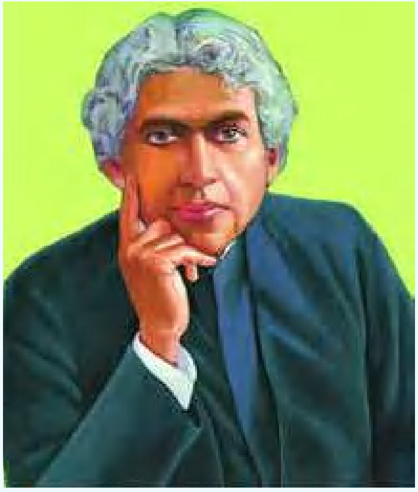

जगदीश चंद्र बोस

भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर, 1858 को मेमनसिंह गाँव (वर्तमान बांग्लादेश) में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध भौतिकविद् तथा पादपक्रिया वैज्ञानिक बोस ने अपने किताबों में अपने अनुभव व अनुसंधान को व्यक्त किया है।

जगदीश चंद्र बोस रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर अध्ययन करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपने ज्ञान और आविष्कार से सिद्ध कर दिया कि भारत के पास भी स्वदेशी वैज्ञानिक शोध तथा आविष्कार करने की क्षमता है। बोस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने केस्कोग्राफ जैसे यंत्र को विकसित करके प्लांट रिसर्च में एक रिवोल्यूशन ला दिया। इन्होंने वैज्ञानिक मार्कोनी से पहले रेडियो तरंगों द्वारा वायरलेस या बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे-रेडियो, टेलीविजन, रडार, सुदूर संवदेन अर्थात रिमोट सेंसिंग सहित माइक्रोवेव ओवन की कार्यप्रणाली में बोस का योगदान अहम है। आज पूरी दुनिया बोस को मार्कोनी के साथ बेतार संचार के पथप्रर्दशक कार्य हेतु रेडियो का सह-आविष्कारक मानती है।

एक ओर जहां बोस ने बहुत छोटी तरंगें उत्पन्न करने का तरीका दिखाया, वहीं दूसरी तरफ हेनरिक हर्ट्ज के रिसीवर को उन्होंने एक उन्नत रूप दिया। कुछ समय बाद जब यह साबित हुआ कि मार्कोनी के वायरलेस या बेतार रिसीवर का आविष्कार जगदीश चन्द्र बोस ने किया था तो यह जानकर सभी हैरान थे। मार्कोनी के प्रदर्शन से पहले ही वर्ष 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था।

बोस ने ऐसे यंत्र का निर्माण किया, जिससे 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न की जा सकती थीं। यह यंत्र इतना छोटा था कि उसे एक छोटे बक्से में कहीं भी ले जाया जा सकता था। उन्होंने दुनिया को उस समय एक बिल्कुल नई तरह की रेडियो तरंग दिखाई, जो एक सेंटीमीटर से पांच मिलिमीटर की थी, जिसे आज माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग कहा जाता है।

बोस ने ही सबसे पहले दर्शाया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी सुदूर स्थल तक हवा के सहारे पहुंच सकती हैं। ये तरंगें किसी क्रिया को दूसरे स्थान से नियंत्रित भी कर सकती हैं। उनकी यहीं धारणा बाद में रिमोट कंट्रोल सिस्टम का सैद्धांतिक आधार बनीं।

आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे-वेव गाईड, ध्रुवक, परावैद्युत लैंस, विद्युतचुम्बकीय विकिरण के लिये अर्धचालक संसूचक आदि सभी उपकरणों का उन्नींसवी सदी के अंतिम दशक में बोस ने अविष्कार किया और उपयोग किया था। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। उनके कार्यों के लिए 'इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स' ने जगदीश चन्द्र बोस को अपने 'वायरलेस हॉल ऑफ फेम' में सम्मिलित किया है।

बोस ने पादप विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया था। बोस ने पादप कोशिकाओं पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया। उनके प्रयोग इस तथ्य की ओर संकेत कर रहे थे कि संभवतः सभी पादप कोशिकाओं में उत्तेजित होने की क्षमता होती है। ठंडक, गर्मी, स्पर्श और विद्युत उद्दीपन के साथ-साथ बाहरी नमी के कारण भी पौधों में एक्शन पोटेंशल उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने ऐसे संवेदनशील यंत्र बनाए जो पौधों में भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या विद्युतीय स्तर की अति सूक्ष्म जैविक क्रियायों को भी दर्ज कर सकते थे।

वर्ष 1901 से बोस ने अपने प्रयोग के लिए छुई-मुई अर्थात मिमोसा पुडिका और शालपर्णी अर्थात डेस्मोंडियम गाइरेंस का उपयोग किया। छुई-मुई की पत्तियों को छुएं तो वे एक दूसरे की ओर झुकने लगतीं हैं। बोस ने डिसमोडियम गायरेन्स के विद्युतीय स्पंदन को जीवों की रिकॉर्ड की गई ह्रदय गति से तुलना करने के लिए स्पन्दन रिकॉर्डर का प्रयोग किया।

पौधों में धीमी गति से हो रही वृद्धि को मापने के लिए बोस ने खुद ही एक अत्यन्त संवेदी यंत्र बनाया, उन्होंने इस यंत्र को क्रेस्कोग्राफ नाम दिया। यह उपकरण पौधे की वृद्धि को स्वतः दस हजार गुना बढ़ाकर दर्ज करने की क्षमता रखता था।

बोस ने दर्शाया कि पौधों में हमारी तरह ही दर्द का एहसास होता है। अगर पौधों को काटा जाए या फिर उनमें जहर डाल दिया जाए तो उन्हें भी तकलीफ होती है और वह मर भी सकते हैं। एक अन्य अध्ययन क्षेत्र, जिसने बोस को आकर्षित किया, वह था पौधों में जड़ों से तने और पत्ते तक पानी का ऊपर चढ़ना। पौधे जो पानी सोखते हैं, उसमें अनेक प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्व भी होते हैं। यह जलीय मिश्रण का पौधों में ऊपर चढ़ना 'असेन्ट ऑफ सैप' कहलाता है। पौधों की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं पर समय के प्रभाव के अध्ययन की बुनियाद जगदीश चंद्र बोस ने डाली थी, जो आज विज्ञान की एक शाखा क्रोनोबायोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी कुछ प्रमुख किताबें सजीव तथा निर्जीव की अभिक्रियाएँ (1902), वनस्पतियों की अभिक्रिया (1906), पौधों की प्रेरक यांत्रिकी (1926) इत्यादि हैं।

ध्येयIAS
most trusted since 2003

BEST SELLERS
BPSC EXAMINATION

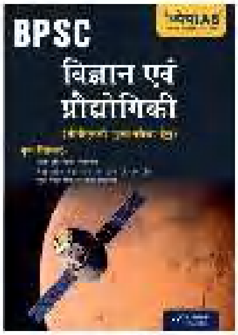

MRP: 199/-

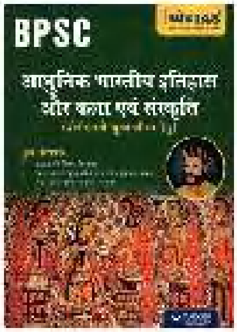

MRP: 290/-

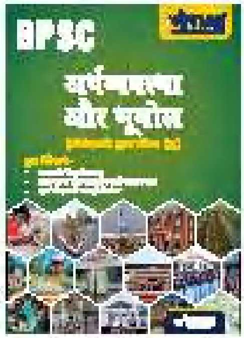

MRP: 210/-

MRP: 300/-

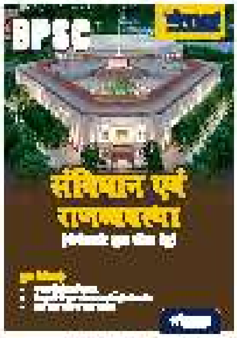

MRP: 360/-

MRP: 320/-

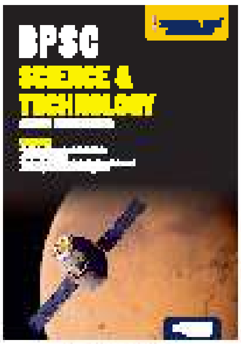

MRP: 260/-

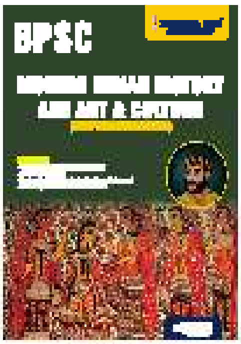

MRP: 285/-

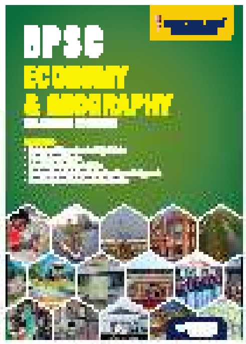

MRP: 160/-

MRP: 290/-

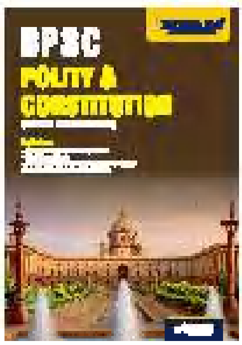

MRP: 300/-

TRUEWORD
PUBLICATION

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 55

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & Ill Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744